

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 17 मार्च, 1980

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12) 22
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(12) 27
भाोक प्रस्ताव	(12) 59
पार्लियामैंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में अन्धे व्यक्तियों पर अभिकथित लाठी चार्ज सम्बन्धी चर्चा	(12) 60
स्वामी अग्निवे 1 एम0एल0ए0 की अभिकथित गिरफ्तारी	(12) 61
ध्यानाकर्षण सूचना— आमतौर पर राज्य के सूखा क्षेत्रों तथा विशेषतया मेहम के पन्द्रह गांवों में तालाबों में पानी	(12) 64

सूखने सम्बन्धी	
वाक आउट	(12) 65
वैयक्तिक स्पष्टीकरण –	
(1) चौधरी राम लाल वधवा द्वारा	(12) 110
(2) श्री जयनारायण वर्मा द्वारा	(12) 111
आधे घंटे की चर्चा –	
वेतन आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी	(12) 111
सदन की बैठक का समय बढ़ाना	(12) 119
आधे घण्टे की चर्चा (पुनरारम्भ)	(12) 119

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 17 मार्च, 1980

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,
विधान भवन सैक्टर- 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई।

अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon. Members, Question Hour.

Milk Plants in the State

***1585. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :-** Will the Minister for Jails and Dairy Development be please to state-

(a) the number and names of milk plants in the State together with their locations and the dates from which these started functioning ;

(b) the year wise amount of income accrued to each of the plants mentioned in part (a) above separately;

(c) the total installed manufacturing capacity of each of the above said milk plants; and

(d) whether each of the aforesaid milk plants is getting full milk supply according to its installed capacity and;

if not, the steps taken or proposed to be taken to make up the short fall ?

Co-operation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) A statement is laid on the Table of the House.

(Annexure 'A')

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(Annexure 'B')

(c) A statement is laid on the Table of the House.

(Annexure 'C')

(d) It has been experience that but for 3-4 months of flush season during winter our milk plants remain under-utilised.

For increasing the milk supply we have launched various technical inputs programmes, including veterinary health care, artificial insemination of cattle, fodder development subsidy and subsidies to the societies to improve their managerial/technical competency under the Desert Development Programme and Operation Flood Programme in the districts of Gurgaon, Faridabad, Rohtak, Bhiwani, Sirsa and Hissar. In addition to the present dairy development programmes, the remaining districts of the State are expected to be covered under Phase-II of Operation Flood Programme which is expected to commence by July-August, 1980. The strengthening of cooperative milk societies so that they could

independently work on 'AMUL' pattern and the provision of technical inputs as envisaged during the coming years are bound to increase the milk production and consequently availability of surplus milk to the milk plants so that the handling capacity can be utilised to the maximum extent.

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name & location of the Plant	Date from which started functioning
1.	Milk Plant, Jind	5-12-1970
2.	Milk Plant, Bhiwani	28-10-1972
3.	Milk Plant, Ambala	29-8-1973
4.	Milk Plant, Rohtak	26-10-1976
5.	Milk Plant, Ballabgarh, Distt. Faridabad	31-3-1979

ANNEXURE 'B'

Year	Jind	Bhiwani	Ambala	Rohtak	B/garh	Total
1970-71	(-) 16.45	Nil	Nil	Nil		(-) 16.45
1971-72	(-) 11.33	Nil	Nil	Nil		(-) 11.33
1972-73	(-) 0.60	(-) 9.95	Nil	Nil		(-) 10.55
1973-74	(+) 8.71	(-) 14.75	(-) 10.99	Nil		(-) 16.98
1974-75	(+) 11.95	(-) 14.61	(-) 16.48	Nil		(-) 19.14
1975-76	(-) 2.91	(+) 2.34	(-) 10.73	Nil		(-) 11.30
1976-77	(+) 5.76	(-) 0.25	(-) 16.80	(+) 2.50		(-) 9.79
1977-78 (1-4-77 to 30-6- 78 15 months)	(-) 5.65	(-) 6.31	(-) 22.45	(-) 23.95		(-) 58.36
1978-79	(-) 4.61	(-) 6.59	(-) 12.86	(-) 3.99	Nil	(-) 28.05

ANNEXURE 'C'

Sr. No.	Name of the Plant	Installed manufacturing capacity (in litres per day)
1.	Milk Plant, Jind	50,000
2.	Milk Plant, Bhiwani	15,000
3.	Milk Plant, Ambala	20,000
4.	Milk Plant, Rohtak	1,00,000 (Total handling capacity of Rohtak Milk Plant is 1,00,000 litres per day. Products conversion capacity of this Plant is only 50,000 litres per day and the remaining 50,000 litres is the storage capacity for supply of milk to Mother Dairy, Delhi Milk Scheme, Delhi, etc.)
5.	Milk Plant, Ballabgarh	50,000

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, अनैक्सचर 'बी' को पढ़ने से पता लगता है कि सारे के सारे मिल्क प्लांटस घाटे में चल रहे हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसका क्या कारण है और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि ये सारे के सारे मिल्क प्लांटस घाटे में चल रहे थे। इसके लिए हमने काफी प्रयत्न किए हैं। कई तरह की स्कीम्ज हमने चालू की हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि युटिलाइजे इन कैपेसिटी इनकी कम थी। ये पूरी तरह प्रौपरली चल नहीं रहे थे। दूध कम आ रहा था। हमने इकनॉमिक ड्राइव भुरू की है। पार्ट (डी) के जवाब में लिखे गए मैयर्ज लिए हैं, जिनका बहुत बड़ा असर हुआ है और हमारे तीन प्लांटस दिसम्बर तक की इन्फर्मे इन के मुताबिक पहली दफा प्रौफिट में चलने भुरू हो गए हैं। जींद में दिसम्बर के महीने में 0.34 लाख रुपये का प्रौफिट रहा है। भिवानी में 0.39 लाख और रोहतक में 5.01 लाख रुपये का प्रौफिट रहा। अम्बाला और बल्लभगढ़ की प्रौब्लम हम कंट्रोल करने जा रहे हैं। पिछले दो महीनों में इनमें भी काफी सुधार कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: सरप्राइजिंग बात तो यह है कि 70-71 से औनवर्ड अगर हम देखें तो कभी 16 लाख, कभी 11 लाख और कभी 10 लाख रुपये का घाटा रहा है मगर 77-78 में आकर के यह घाटा 58.36 लाख रुपये का हो गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी सप्लीमेंटरी क्वै चन के जवाब में बताया कि दिसम्बर के महीने में तीन प्लांटस प्रॉफिट में आ गए हैं मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उसका ब्यौरा इन्होंने जवाब के साथ क्यों नहीं दिया जब चार महीने के बाद यह जवाब आ रहा है ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, 78-79 तक की फिगरज इन्होंने पूछी थीं, वह मैंने सप्लाई कर दी है। बाद की फिगरज तो मैंने अपनी मर्जी से हाउस की जानकारी के लिए कलैक्ट करवाई थीं। (विधन) जहां तक वधवा साहब के इस सवाल के जवाब का संबंध है कि हमने इस घाटे को कम करने के लिए मेन मैयर क्या लिया है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इकनॉमिक ड्राइव करके इन प्लांटस में जो रोजाना के खर्च थे उन्हें एक महीने में 50-60 हजार रुपए कम कर दिया है।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्र न में इन प्लांटस के स्टार्ट होने से अब तक की इन्फर्मे ान मांगी थी। लेकिन ये उसे अब बता रहे हैं और जवाब के साथ इसे इन्होंने नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: मेरे ख्याल में 78-79 का मतलब पहली अप्रैल, 1979 तक होता है और पहली अप्रैल, 1979 के बाद की फिगरज मन्त्री जी अब बता रहे हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: परन्तु इन्होंने यह बात हमें राइटिंग में नहीं दी है कि दिसम्बर 80 तक कितना प्रॉफिट हुआ है।

श्री अध्यक्ष: वय 1979-80 की फिगरज अगर दिसम्बर तक की आपके पास हैं तो आप दे दीजिए।

ठाकुर बीर सिंह: जीन्द प्लांट में जुलाई महीने में 2.76 लाख रुपये का लौस था; अगस्त में 2.05 लाख और सितम्बर में 1.97 लाख रुपये का लौस था। सितम्बर तक टोटल लौस 6.78 लाख रुपये का था। अक्टूबर में 0.51 लाख और नवम्बर में 0.70 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। दिसम्बर में इसमें 0.87 लाख रुपये का लौस हुआ। टोटल प्रॉफिट 0.34 लाख रुपये का रहा। भिवानी में जुलाई के महीने में 1.81 लाख, अगस्त में 1.03 लाख और सितम्बर में 0.77 लाख रुपये का लौस था। टोटल लौस इस क्वार्टर का 3.61 लाख रुपये का था। अक्टूबर में इसमें 0.31 लाख रुपये का लौस रहा। नवम्बर में इसमें 0.9 लाख रुपये का प्रॉफिट रहा और दिसम्बर में भी 0.61 लाख रुपये का प्रॉफिट रहा। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले में जुलाई में 4.52 लाख रुपये का लौस था और अगस्त में 4.22 लाख रुपये का लौस था।

Mr. Speaker: I do not think there is any point in giving month to month figures. It would be better if you can give the closing figures and I presume that the year closes on 31st March.

ठाकुर बीर सिंह: इनका हिसाब किताब जुलाई महीने से जून महीने तक चलता है। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह क्वै चन दिया गया था उस वक्त ये फिगरज हमारे पास नहीं थी और मैं अब भी कह सकता था कि फिगरज आई नहीं हैं लेकिन मैंने हाउस की जानकारी के लिए ये फिगरज बाद में कुलैक्ट करके यहां बताई हैं।

डा० मंगल सैन: क्या मिनिस्टर साहब की जानकारी में यह बात है कि रोहतक जिले के छोटे किसानों ने लाखों रुपये का दूध डेरी को दिया हुआ है लेकिन उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं।

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो डाक्टर साहब ने इस बारे में अलग से क्वै चन दिया हुआ है और उसका जवाब हाउस में आएगा लेकिन अगर वह अभी भी जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूं कि फरवरी महीने के आखिर तक के टोटल अकाउंटस क्लीयर कर दिए गए हैं।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अनैक्सचर 'बी' में लिखा है कि "Figures from 1-4-1976 onwards are provisional as the accounts have not been audited yet." क्या मंत्री जी बताएंगे कि सन् 76 से लेकर आज तक के अकाउंटस औडिट क्यों नहीं हुए और ये कब तक औडिट हो जाएंगे ? साथ ही उनसे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या औडिट होने के बाद यह घाटा और भी बढ़ सकता है ?

ठाकुर बीर सिंह: वैसे तो ये अकाउंटस कम्पलीट हैं, फिर भी ऑडिट का अपना हिसाब किताब होता है। जहां तक अब तक ऑडिट न होने का सम्बंध है, इसके बारे में अर्ज यह है कि इस महकमे के ऑडिट सैल में भुरु से बड़ा कम स्टाफ चला आ रहा है। स्टाफ बढ़ाने के लिए हमने केस भेजा है और फाईनैस डिपार्टमेंट से वह क्लीयर भी हो गया है। इसके अलावा और सीनियर ऑफिसरज भी हमने इस सैल में लगा दिए हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सारे अकाउंटस ऑडिट हो जाएंगे ?

श्री फतेह चंद विज: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अनैक्सचर 'ए' में बताया है कि 5 स्थानों पर ये मिलक प्लांटस लगे हुए हैं। क्या वे बतायेंगे कि किसी और जगह भी इस तरह के मिलक प्लांटस लगाने का सरकार का इरादा है ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस समय सिरसा का प्लांट अन्डर कंस्ट्रक्शन है। उसमें चिलिंग प्लांट तो तकरीबन कम्पलीट हो गया है। वह चलने वाला भी था लेकिन बिजली की कमी के कारण वह चल नहीं सका। अब जेनरेटर भेज दिया है। एक दो दिन में वह काम करना भुरु कर देगा। इस प्लांट का काम पूरा होने के बाद ही हम और जगहों के बारे में सौचेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार सरकार ने अनेक महकमों में

'अनाज के बदले काम' स्कीम चालू की है क्या उसी तरह की कोई स्कीम इस महकमें में भी चालू की जाएगी ? (विघ्न)

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात समझा नहीं क्योंकि 'फूड फार वर्क' स्कीम के तहत कोई दूध नहीं देगा। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, अनैक्सचर 'बी' में लिखा है कि जीन्द मिलक प्लांट में 73-74 में 8.71, 74-75 में 11.95 और 76-77 में 5.76 लाख रुपये का प्रॉफिट था लेकिन 77-78 में जब जनता पार्टी का राज आया तो उसमें 5.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ। उसके बाद वह अभी तक नुकसान में चल रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह नुकसान जनता पार्टी की कमजोरी की वजह से था या महकमे की वजह से था ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, यह कोआप्रे ान का महकता श्री बीरेन्द्र सिंह जी के पास था। (विघ्न) जीन्द प्लांट के बारे में तो मैंने बता दिया कि यह इससे भी ज्यादा घाटे में था लेकिन अब मुनाफे में चल रहा है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: क्या मन्त्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि पीक सीजन में मिलक प्लांटस में पूरा दूध आ जाता है ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, जितनी हमारी युटिलाइजे ान कैपेसिटी है उसके मुकाबले में 50-60 परसेंट के

बीच में ही पीक सीजन में दूध मिलता है। पीक सीजन में हाइयेस्ट सप्लार्ई 60 परसैंट तक पहुंचती है। उसका कारण यह है कि जितनी मिलक प्लांट की कोआप्रेटिव सोसाइटीज हैं, वहीं गांवों में दूध खरीदती हैं। उन सासाइटीज की तादाद बहुत कम रही है। अभी पिछले दिनों महकमा की इस बारे में मीटिंग हुई थी और उन्होंने इसके सुधार के लिए कई ढंग निकाले हैं। मिसाल के तौर पर यह फैसला हुआ है कि जिन गांवों में जाने के लिए रास्ते हैं और जो सड़कों के साथ लगते हैं उनमें सोसाइटीज खोली जायें और जो गांव मिलक प्लांट के नजदीक लगते हैं उनमें भी अधिक सोसाइटीज खोली जायें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने भैंस खरीदने के लिए कोआप्रेटिव सोसाइटीज से कर्जे लिए हैं और इस वर्ष वहां पर अकाल पड़ गया यानी अकालग्रस्त हैं। क्या वहां लोन की रिकवरी रोक दी है या अभी तक जारी है ?

ठाकुर बीर सिंह: लोन भी तो कई तरह के हैं। जो लोनज कमि रियल बैंकस की तरफ से आते हैं उन पर 11 परसैंट ब्याज वसूल किया जाता है। इन पर हम चार परसैंट भी और सात परसैंट भी सबसिडी देते हैं। जो मुफाल और काडा से लोन दिया जाता है। वह पैसा लैंड डिवैल्पमेंट बैंकस के जरिए आ रहा है। उनका सीधा ताल्लुक रिजर्व बैंक से है। हमने रिजर्व बैंक को कहा है कि इस साल इसकी रिकवरी न की जाये। हमने सैंटर के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर राव बीरेन्द्र सिंह जी के सामने भी यह मामला

रखा था। उन्होंने भी वायदा किया है कि वह रिजर्व बैंक से कुछ राहत दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि यह अभी हाल में रिकवर न किया जा सके। रिजर्व बैंक ने कुछ निर्णय भी लिया है। उसके ऊपर हम आगे की कार्यवाही करने जा रहे हैं।

चौधरी संत कंवर: मैं आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि टैक्निकल सहायता न मिलने के कारण हरियाणा सरकार को मिल्क प्लांटस से कितना नुकसान हुआ है और जब टैक्निकल सहायता मिल जायेगी तो कितना लाभ होगा ?

ठाकुर बीर सिंह: पहले ये सारे प्लांटस हरियाणा डेरी डिवैल्पमेंट कार्पोरेट्स द्वारा चलाये जा रहे थे। 1-4-77 को कोआप्रेटिव फ़ैडरेट्स बनायी गईं और उसके बाद ये प्लांटस फ़ैडरेट्स ने ले लिए। इनकी कंडीशन सुधारने के लिए चालीस लाख रुपया लगाया गया और उसके साथ ही साथ 48 लाख रुपया लीज मनी भी दी गई और अब भी देते आ रहे हैं। चार लाख रुपये का बर्डन फ़ैडरेट्स पर है। अब हमने इस लीज मनी को माफ़ करने के लिए रैवेन्यू डिपार्टमेंट में केस मूव किया हुआ है।

इसके साथ साथ मैं अपने लायक दोस्त को बताना चाहता हूँ कि इसमें काफी पैसा लगा हुआ है। बैंकों से 16 परसेंट ब्याज के हिसाब से कर्जा लेकर इन प्लांटस को चालू किया गया था। अब डैजर्ट डिवैल्पमेंट स्कीम के फेज टू का जो प्रोग्राम आ

रहा है उसके तहत हमें 25—30 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं। इसमें से पांच करोड़ रुपया इन प्लांटस की डिवाइसमेंटा और युटिलाइजिंग इन आफ रैगुलर कैपेसिटी के लिए लगाया जाएगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल: क्या मन्त्री महोदय इन मिल्क प्लांटस में कोई ऐसा सिस्टम लागू करने के लिए तैयार हैं कि लोग इन प्लांटस को दूध देते हैं उन्हीं के लड़कों को वहां सर्विसिज में लिया जायेगा ?

ठाकुर बीर सिंह: ऐसी कोई योजना नहीं है। अब जो भी प्लांटस लगे हैं उनमें फिलहाल गुंजाइश नहीं है। अगर नये प्लांटस लगेंगे तो आपकी तजबीज को कन्सिडर कर लिया जायेगा।

Down-gradation of Schools

***1470. Shri Hira Nand Arya:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that 29 duly upgraded schools were downgraded recently and the Punjab and Haryana High Court issued stay orders in some of the cases;

(b) whether it is also a fact that matching grants were also given to some of the upgraded schools and; if so, the details thereof; and

(c) the total number of schools upgrades in the State after the above orders of downgrading the schools ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भान्ति देवी):

(क) जी हां।

(ख) किसी ऐसे स्कूल को मैचिंग ग्रांट नहीं दी गई।

(ग) 138।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदया से जानना चाहता हूं कि इन 29 स्कूलों में कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जिनमें क्लासिज चल रही है ?

श्रीमती भान्ति देवी इसके लिए माननीय सदस्य सैपरेट नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय सैपरेट नोटिस देने की बात नहीं है। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जो स्कूल डाउनग्रेड किये गये थे, क्या उनमें क्लासिज चल रही हैं और अगर चल रही हैं तो कौन कौन से स्कूलों में चल रही हैं ?

श्रीमती भान्ति देवी: 29 स्कूल डाउनग्रेड किये गये थे। तेरह स्कूल तो हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आये वे चालू हैं। आठ स्कूल हमारी सरकार ने फिर से यूं के यूं चलने दिये और बाकी

आठ स्कूलों में से तीन स्कूलों को उनकी कन्डी टान्ज पूरी होने पर अपग्रेड कर दिया गया। केवल पांच स्कूल ही डाउनग्रेडिड हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदया से जानना चाहता हूँ कि जिन स्कूलों को डाउन ग्रेड किया गया था उनमें से कौन से स्कूल ऐसे हैं जिनमें क्लासिज चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष: आप अगर नाम जानना चाहते हैं तो दफतर से जा कर ले लें।

श्री हीरा नन्द आर्य: जिन 13 स्कूलों को हाई कोर्ट से स्टे मिला है वे कौन कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा है कि नाम उनके पास नहीं हैं नाम जानना चाहते हैं तो दफतर से ले लें।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदया ने बताया है कि 29 स्कूल डाउनग्रेड किये गये थे जिनमें से अब केवल पांच स्कूल डाउनग्रेडिड हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन पांच स्कूलों को किस आधार पर छोड़ा गया और आठ को सरकार ने क्यों यूं का यूं रहने दिया ?

श्री अध्यक्ष: जो भी स्कूल भार्ते पूरी करते गये उनको अपग्रेड करते गये। भायद पांच ने भार्ते पूरी न की हों इसलिए अपग्रेड न किये हों। इस पर बहुत डिस्कान हो चुकी है। पहले

भी इस पर कम से 20 मिनट डिस्कान हो चुकी है और इस सवाल का बहुत अच्छी तरह से जवाब आ चुका है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इस सवाल के 'सी' पार्ट का जो जवाब दिया है उससे ऐसा महसूस होता है कि 138 स्कूलों को अपग्रेड जो किया गया वह 29 स्कूलों को डाउनग्रेड करके किया गया है। इन 138 स्कूलों को अपग्रेड करने का क्या क्राइटेरिया था और किन किन हलकों में ये अपग्रेड किए गए हैं ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, 29 स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया था। इन स्कूलों को डाउनग्रेड किए जाने का कारण दो तीन पहले मैंने यहां हाउस में बताया भी था जिस समय चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी और उस सरकार में श्री हीरा नन्द आर्य ऐजुकेशन मिनिस्टर थे तो इन्होंने कुछ स्कूलों को गलत ढंग से अपग्रेड कर दिया था। श्री हीरा नन्द आर्य ने अकेले अपने हलके में 14 स्कूलों को अपग्रेड किया। श्री रणसिंह हमान के हलके में 10 स्कूलों को अपग्रेड किया। कुछ स्कूलों को अपग्रेड चौधरी देवी लाल जी के हलके में भी किया गया। उस समय पार्टी मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि प्रत्येक एम0एल0ए0 के हलके के अन्दर कम से कम 2-2 स्कूलों को अपग्रेड करना है, परन्तु चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने जाते जाते इन स्कूलों को गलत ढंग से अपग्रेड कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 14 स्कूलों को तो अकेले श्री हीरा

नन्द आर्य ने अपने हलके में अपग्रेड किया था। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि बहुत ही गलत ढंग से इन स्कूलों को अपग्रेड किया गया है तो हमने उन स्कूलों को डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड कर दिए जाने के बाद कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए। इन 29 स्कूलों में 13 स्कूलों को हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया था। कुछ लोग बाद में हम से मिले उन्होंने हमसे कहा कि हमारे स्कूलों में क्लासिज चालू हो गई हैं और बच्चे भी ज्यादा हैं इस लिए मेहरबानी करके हमारे स्कूलों को डाउन ग्रेड न किया जाये। हमने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उन स्कूलों को उसी प्रकार से जारी रखा। हमने उन स्कूलों को डाउनग्रेड किया जो स्कूल भार्त पूरी नहीं करते थे और जहां लड़कों की संख्या भी बहुत कम मात्रा में थी। उसके बाद 138 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। इन्होंने अपनी पार्टी के हल्कों में अर्थात् जो एम0एल0एज0 इनके साथ थे उनके हल्कों में तो स्कूलों को अपग्रेड कर दिया था लेकिन जो साथी इधर हमारे साथ बैठे हैं इनके हल्कों में बहुत कम मात्रा में स्कूलों को अपग्रेड किया था। इसलिए हमें सब हल्कों को बराबर लाने के लिए ऐसा करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: यह जवाब तो पहले भी दिया जा चुका है और इसको सभी मेंबर साहेबान ने सुन लिया होगा।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब के 'ग' पार्ट में बताया है कि 138 स्कूलों को अपग्रेड किया गया।

तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एक एक हल्के में कितने कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया और इनको अपग्रेड करने का क्या क्राईटेरिया फिक्स किया हुआ था ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, किसी हल्के में 3 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, किसी में 4 स्कूलों को अपग्रेड किया है और किसी हल्के में 2 स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया है।

**Quota of jobs reserved for Ex-servicemen in the
Transport Department**

***1606. Chaudhri Partap Singh Thakran:** Will the Minister for Transport be please to state-

(a) the quota of jobs reserved for Ex-servicemen in the services together with the actual percentage of such personnel existing at present in the Transport Department;

(b) the percentage of the quota referred to in part (a) above filled up in the Transport Department through S.S.S. Board and the Public Service Commission from 1-4-79 to date; and

(c) whether there is any deficiency in the percentage of Ex-servicemen in the said Department; if so, the steps taken or proposed to be taken to make up this shortfall ?

परिवहन मन्त्री (श्री जगन नाथ):

(क)	भूतपूर्व सैनिकों के लिए निश्चित कोटा:- 1. श्रेणी 1 और 2 2. श्रेणी तीन और चतुर्थ	5 प्रति गाँव 20 प्रति गाँव
	भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान वास्तविक प्रति गाँव श्रेणी 1 और 2 श्रेणी तीन और चतुर्थ	17 प्रति गाँव 21 प्रति गाँव
(ख)	श्रेणी 1 तथा 2 श्रेणी तीन और चतुर्थ	8.5 प्रति गाँव 0.18 प्रति गाँव
(ग)	जी नहीं।	

चौधरी संत कंवर: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब के पार्ट 'बी' में क्लास-3 और क्लास-4 में भूतपूर्व सैनिकों की हुई भर्ती की परसेंटेज केवल 0.18 बताई है। क्या

इसका कारण यह तो नहीं है कि रोडवेज के अन्दर डायरेक्ट ऐम्पलाएमेंट के जरिए भर्ती कर ली जाती है ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, ऐसी बात तो नहीं है। अभी पिछले वर्ष 7-9-79 को हड़ताल हो गई थी। हड़ताल की अवधि के दौरान कुछ कर्मचारी रखे गए थे। उस समय यह फैसला किया गया था कि हड़ताल की अवधि के दौरान जितने कंडक्टर और ड्राइवरो को लगाया गया या किसी और पर पर कोई कर्मचारी लगाया गया, पहले उनइ कर्मचारियों को लगाया जायेगा बर्ती वे उस के पद के हिसाब से जिस पद के विरुद्ध उसे लगाया गया है सभी क्वालिफिके गन्ज पूरी करते हों। अब तक 606 कर्मचारी लगाये जा चुके हैं। इस वजह से अभी तक बैकवर्ड क्लासिज, भाडयूल्ड कास्टस और ऐक्स सर्विसमैन की भी भर्ती पूरी नहीं हुई। जिस समय हड़ताल हुई उस समय मुख्य मंत्री और एम0एल0एज0 ने यही फैसला किया था कि पहले इन कर्मचारियों को जो हड़ताल के समय काम पर आये हैं, लगाया जाये। जैसा पहले बताया है कि अब तक 606 कर्मचारियों को लगाया जा चुका है और जो बाकी रहते हैं उनको भी भीघ्र लगा दिया जायेगा। जिस समय तक ये कर्मचारी नहीं लगाये जाते उस समय तक भाडयूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लास और ऐक्स सर्विसमैन की भी भर्ती नहीं की जा सकती।

चौधरी पीर चन्द: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भाडयूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लासिज और ऐक्स सर्विसमैन

का जो घाटा है उसको इस साल के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री जगन नाथ : मैंने पहले ही बताया है कि जब तक हड़ताल के दौरान लगाये गए कर्मचारी नहीं लगाए जाते उस समय तक और भर्ती नहीं की जायेगी। ज्यों ही ये कर्मचारी लग जायेंगे उसके बाद भाडयूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लास और ऐक्स सर्विसमैन को लेने की पूरी पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, सवाल के 'बी' पार्ट के जवाब में बताया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और एस0एस0एस0 बोर्ड के द्वारा क्लास वन और टू में 8.5 प्रतिशत और क्लास थ्री और फोर में 0.18 परसेंट भर्ती की गई है जबकि ऐक्चुअल परसेंटेज इन लोगों की 17 परसेंट और 21 परसेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने क्लास वन और टू में 8.5 परसेंट और क्लास थ्री और फोर में 20 परसेंट डायरेक्ट भर्ती किए हैं ? क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इन व्यक्तियों को एस0एस0एस0 बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए क्यों नहीं भर्ती किया गया ?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, यह कमिश्नरियल डिपार्टमेंट है। हम पदों को भरने के लिए ऐडवरटाइजमेंट भी करते हैं। एस0एस0एस0 बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी आदमी लगाते हैं। कई बार एस0एस0एस0 बोर्ड से और पब्लिक

सर्विस कमी इन से आदमी आने में काफी समय लग जाता है। इसलिए हम ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज के जरिए सीधी भर्ती कर लेते हैं। क्योंकि इस डिपार्टमेंट को अचानक ही ड्राइवरों कंडक्टरों और अन्य कर्मचारियों की जरूरत पड़ जाती है जिसके बगैर काम चलना असंभव हो जाता है, इसलिए हम ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज के जरिए भर्ती कर लेते हैं। जिस समय हमारे पास एस0एस0एस0 बोर्ड से ड्राइवर कंडक्टर या और कर्मचारी जिनकी हमने मांग की हुई होत है, आज जाते हैं उस समय ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज के जरिए भर्ती किए कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है।

Pay Scale of Lady Health Visitors

***1604. Chaudhri Des Raj:** Will the Finance Minister be please to state-

(a) whether it is a fact that the revised grade of Lady Health Visitors in Punjab is Rs. 570-940 and of those in the selection grade is Rs. 680-1120;

(b) whether it is also a fact that in Haryana the maximum grade of Lady Health Visitors is being fixed at Rs. 725/- and no selection grade is being given to the Lady Health Visitors in Haryana especially when the qualifications of Lady Health Visitors in Punjab and Haryana are the same;

(c) whether the Government intends to bring the Lady Health Visitors of Punjab and Haryana at par in the matter of grade and selection grade; a dn

(d) if not, the reasons thereof ?

Finance Minister (Lala Balwant Rai Tayal):

(a) The revised grade of Lady Health Visitor in Punjab is Rs. 510-940 (and not 570-940) with a selection grade of Rs. 680-1120.

(b) The revised grade of Lady Health Visitor in Haryana has not been fixed so far. The matter is under consideration.

(c) No decision has yet been taken.

(d) In view of (c) above, question does not arise.

चौधरी देस राज: स्पीकर साहब, पे कमी इन की तो रिपोर्ट भी आ चुकी है और भाया भी हो चुकी है। क्या मन्त्री जी यकीन दिला सकते हैं कि हरियाणा में लेडी हैल्थ विजिटर्स के पे स्केल्ज को पंजाब के बराबर लाया जायेगा ?

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैंने बता दिया है कि यह मामला अभी अन्डर कंसिड्रे इन है। जब कोई फ़ैसला हो जायेगा तभी पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष: क्या पे कमी इन की रिपोर्ट में इसके बारे में कोई झगडा है ?

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, सवाज के भाग 'बी' और 'सी' में यह बताया गया है कि मामला विचाराधीन है या

अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे कोई इस बात के निर्णय के लिये डैड लाईन तय करने के लिए तैयार हैं। कि इस दिन तक यह मामला तय हो जायेगा ?

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक कमेटी बनायी गयी है और जल्दी ही इसके बारे में डिस्मिशन ले लिया जायेगा।

Mr. Speaker: Is that linked with the Report of the Pay Commission ?

लाला बलवन्त राय तायल: जी हाँ।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, इस पे कमी इन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाये तो एस0डी0ओज0 और ऐक्सीयन्ज की पे कुछ भी बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। क्या सरकार उनकी पे भी बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का ऐक्सीयन्ज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, लेडी हैल्थ विजीटर्स के लिये प्रोमो इन ऐवेन्यूज बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पे कमी इन ने उनके लिये कोई प्रोमो इन ऐवेन्यूज भी ओपन करने के लिये सिफारिश की है ?

Mr. Speaker: I do not think, the Finance Minister will be knowing about it. (Interruption and noise) वह तो डिपार्टमेंट वाले बतायेंगे कि उनके लिये प्रोमो इन एवेन्यूज कितने हैं या नहीं हैं। इनसे तो आफ सिर्फ पे के बारे में पूछिये।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि कोई कमेटी बनी हुई है। क्या उस कमेटी में लेडी हेल्थ विजिटर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव लिया जायेगा ताकि उनकी पूरी बात वहां पर सुनी जा सके ?

लाला बलवन्त राय तायल: इसके बारे में तो स्पीकर साहब, मैं कई बार बतला चुका हूं कि एक कमेटी हमने चीफ सैक्रेटरी के अधीन तीन सैक्रेटरीज की बनाई हुई है जिसमें इसके बारे में कंसिड्रे इन होना है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात पे आ कर सकता है। उसके बाद गौर करके वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री मांगेराम गुप्ता: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी है जिसमें हरेक आदमी अपनी बात पे आ कर सकता है। क्या मन्त्री महोदय इस कमेटी में तीन की बजाये 5 सैक्रेटरीज रखने के लिये तैयार हैं यानी दो तीन सैक्रेटरीज और बढ़ाने के लिये तैयार हैं ?
(गौर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में वे बता चुके हैं कि चीफ सैक्रेटरी उसके चेयरमैन हैं और दो तीन सीनियर सैक्रेटरीज उसके मेंबर्ज हैं। Moreover, there is also to be half an hour discussion on this matter to day.

Shrimati Sushma Swaraj: Mr. Speaker, through you, I want to know from the Fianance Minister to what is the present pay scale of Lady Health Visitors in Haryana and what is the difference in their pay scale as compared to that of Punjab ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अगर ये पूछेंगी कि किसी क्या पे है, वह तो इस वक्त बताना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जहां कहीं भी अन्तर है, उस अन्तर को दूर करने के लिये हमने चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है। वह कमेटी सारी बातों को देखेगी। उसमें हर डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति को पूरा इंसाफ दिया जायेगा और हमारी यह कोशिश होगी कि पंजाब से भी ज्यादा स्केलज उन लोगों को दिये जायें, कम नहीं देंगे।

Shrimati Sushma Swaraj: This is not the answer to my question.

Mr. Speaker: The Hon. Member has asked a very specific question कि हरियाणा की लेडी हैल्थ विजिटर्स की क्या पे है ?

लाला बलवन्त राय तायल: इस वक्त हरियाणा में लेडी हैल्थ विजिटर्ज का पे स्केल 140-6-170-8-210-10-300 का है। (व्यवधान व भाोर)

डा0 मंगल सैन: पंजाब के अन्दर जो पे स्केल है, वह भी तो पूछा है ?

श्री अध्यक्ष: जवाब में पंजाब का दिया हुआ है और हरियाणा का भी उन्होंने बता दिया है।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, 140 बेसिक पे पर टोटल एमोलूमेंटस कितने बनते हैं, यह नहीं बताया है, यानी इस वक्त लेडी हैल्थ विजिटर को कितने पैसे मिलते हैं ? (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो आप कैलकुलेट कर लीजिये। (गोर व व्यवधान)

चौधरी देस राज: सर, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो लेडी हैल्थ विजिटर का मन्त्री महोदय ने 140 का ग्रेड बताया है, इसमें उनको एट प्रेजैन्ट कितने टोटल एमोलूमेंटस मिलते हैं ?

लाला बलवन्त राय तायल: यह इन्फर्मे इन मुझसे मांगी नहीं गयी थी वरना मैं यह भी दे देता। जो इन्फर्मे इन मुझसे मांगी गयी थी वह मैंने हाउस को दे दी हैं।

Industrial Development of the Rural Area

***1656. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether any communication from the Government of India was received by the State Government for associating Industrialists/business houses to develop the rural industries in the State; and

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to associate the said houses to take part in the rural development of the State and the results, if any, so far achieved in the behalf ?

Development Minister (Rao Ram Narain):

(a) Yes.

(b) The State Government has issued various circular letters. Officers of the Development Department were also deputed to contact them in person both individually and by organising meetings. A detailed pamphlet on the subject is under issue. Advertisements are being given in the leading News Papers and a high level conference with high industrialists has been proposed.

So far four units have been given approval under Section 35 CC of the Income Tax Act and four cases are under examination under section 35 CCA (Interruptions)

Mr. Speaker: Even the Hon. Members who were fanatics of Hindi, have started speaking in English. (Interruption and Noise)

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, जब हिन्दी जानने वाले भी अंग्रेजी में जवाब देने लगे तो उनसे हिन्दी की बजाय अंग्रेजी में ही सवाल पूछना उचित है। जब उनसे सवाल इंगलि में पूछा जाता है तो फिर वे हिन्दी में जवाब दे देते हैं। वे लिखा हुआ जवाब तो हिन्दी की बजाय अंग्रेजी में पढ़ेंगे लेकिन सप्लीमेंट्री का जवाब हिन्दी में देंगे। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चन्द जैन: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से जो पत्र आये हैं, वह कब आये हैं और जिन चार यूनिट्स को ऐप्रूवल दी गयी है, इंडट्रियल बिजनेस हाउसिज उन पर कितना रुपया देहातों में खर्च करना चाहते हैं और कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

राव राम नारायण: ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन जिन चार यूनिट्स को ऐप्रूवल दी गयी है, उनके नाम मेरे पास हैं, वह मैं बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष: लैटर इस साल आया है या पिछले साल आया है, यह तो आप बात ही सकते हैं (व्यवधान व भाोर)

राव राम नारायण: वह मैं नाम आपको बता देता हूँ (तोर व व्यवधान).....

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इनकी आवाज को जरा ठीक करवा दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। (गोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: I would request the Hon. Members not to cast aspersions on others (Interruptions and noise). I think, there is some defect in the mike, and that is why it is not audible. (Interruptions). राव साहब, आपने जो कहा है वह ठीक से सुनाई नहीं दिया है। आप उसे फिर कह दें (व्यवधान)।

Rao Ram Narain: Sir, I can give the details of these concerns. They are-

Sr. No.	Name of Company	Particulars of projects	Approval under Section 35CC/35CCA
1.	M/S Hinmdustan Everest Tools Ltd. Dohil Chambers 46 Nehru Place, New Delhi.	Regarding repair & addition of 2-3 rooms to the existing Govt. Primary School, Village Badmalik, Distt. Sonapat	Approved u/s 35 CC.
2.	Do	Projects of providing brick road and brick soling in the streets of village Jatheri, Distt. Sonapat.	Do
3.	M/S Jindal Aluminium Ltd. 16 th K.M. Tumkur Road, Bangalore.	Regarding construction of School building and provision of furniture etc. to Siwani Arjanand Govt. High School, Vill. Nalwa, Distt. Bhiwani.	Do
4.	M/S Haryana Tube	Regarding	Do

	Mng. Co. Pvt. Ltd. Delhi Road, Hisar	construction of clinic/nursing home at village Siwani.	
--	---	--	--

श्री मूल चन्द जैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रकम कितनी आई ?

राव राम नारायण: रकम का ब्यौरा हमारे पास नहीं है ।

डा० मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी ऐप्लीके िंज आई है ?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, अब तक हमारे पास आठ ऐप्लीके िंज आई । चार ऐप्लीकेंटस काम कर रहे हैं और चार अन्डर प्रोसैस हैं ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, भारत सरकार ने हिन्दुस्तान के अमीर लोगों के लिए एक स्कीम भेजी है कि आप लोग देहात में दिलचस्पी लें, देहात के विकास के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज लगाएं और इसके लिए उनको इंकम टैक्स में छूट दी जाएगी । क्या मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से इस बारे में कब चिट्ठी आई थी और अमीर लोग दिलचस्पी लेकर हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाएं इस दि ा में हरियाणा में क्या प्रगति हुई है ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, मैं इसका जवाब दे देता हूँ क्योंकि उस समय मैं मिनिस्टर था। स्पीकर साहब, इस स्कीम को भारत सरकार से आए हुए दो या अढ़ाई साल हो गए हैं। जब मैंने इस विभाग का चार्ज लिया था उस समय मैंने इस स्कीम को निकलवाया था लेकिन लैटर कोई इ पू नहीं हुआ था; बाद में स्कीम्ज की लाइन्ज पर अपने आफिसर्ज के साथ बैठकर एक स्कीम तैयार की और हरियाणा के बिजनैसमन को ऐप्रोच किया। इस स्कीम के तहत 75 परसेंट इंकम टैक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी और बाकी 25 परसेंट बिजनैसमैन को देना पड़ेगा। फाईल दबी पड़ी थी इसलिए इस पर दो अढ़ाई साल से अमल नहीं हुआ। जब से यह स्कीम निकाली है तब से बिजनैसमैन के साथ कंटैक्ट जारी है।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि चार जगह पर उद्योग काम कर रहे हैं और चार ऐप्लीके ांज अन्डर प्रोसैस हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर ये उद्योग लगने हैं उन जगहों को छांटने का क्राइटेरिया क्या रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष: यह तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर डिपेंड करता है, वे जहां चाहेंगे वहां पर लगाएंगे।

Thakur Bir Singh: The businessman has to adopt an area according to his choice.

श्री जय नारायण वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम दो अढ़ाई साल तक इम्पलीमेंट नहीं हुई, इसका क्या राज है ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, यह फाईल दबी हुई थी इसलिए इस स्कीम पर अमल नहीं हो सका। जब मैंने चार्ज लिया तो इस फाईल को निकलवाया और चौधरी देवी लाल जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ एक मीटिंग भी अरेन्ज की थी। उस वक्त जो आफिसर्ज इंचार्ज थे नैंगलीजेंस के बारे में उनके खिलाफ ऐकान भी लिया गया कि उन्होंने फाईल को क्यों दबा कर रखा हुआ था। अगर गवर्नमेंट के सामने निकाल कर लाते तो हरियाणा के बिजनैसमैन जो सारे हिन्दुस्तान में इंडस्ट्री लगा रहे हैं वे हरियाणा में भी लगा सकते थे और इस तरह से हरियाणा का काफी डिवैल्पमेंट हो सकता था।

Shri Mool Chand Jain: Speakder Sahib, the Hon. Minister has stated in his reply that-

“A detailed pamphlet on the subject is under issue. Advertisements are being given in the leading News Papers and a high level conference with big industrialists has been proposed”.

स्पीकर साहब, अभी तक कोई पैम्फ्लैट इतना नहीं किया गया है। अभी तक कोई ऐडवरटाइजमेंट भी नहीं हुई और न ही अभी तक इंडस्ट्रियलिस्टस के साथ कोई कांफ्रेंस की गई है।

स्पीकर साहब, उस वक्त सरकार में इस तरफ बैठे हुए भी कुछ लोग थे उनको तो ब्लेम करने की कोई बात नहीं है। इस सरकार को आए हुए नौ-दस महीने हो चुके हैं लेकिन इस दि 11 में अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस दि 11 में तेजी से काम भुरू हो जाएगा ?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, इस बारे में स्टेट लैवल पर एक कमेटी बनाई गई है। और फरीदाबाद में उस कमेटी की दो दिन की मीटिंग 18 तथा 19 जनवरी 1980 को हुई थी और उसमें इंडस्ट्रियलिस्टस से कंटेक्ट कायम किया गया और उनको मोटिवेट किया गया कि रूरल डिवैल्पमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, कुछ व्यापारी उसी गांव के रहने वाले हैं और अपना नाम कमाने के लिए और इंकम टैक्स का कंसेंशन लेने के लिए वे उसी गांव में इंडस्ट्री लगा लेते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी तजवीज सरकार के विचाराधीन है कि इंडस्ट्री तो व्यापारी लगाएं लेकिन जगह की सिलैक्टान गवर्नमेंट करे ?

राव राम नारायण: यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने रिटन रिप्लाय में लिखा है कि बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिये जा रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना भी प्रस्तावित है लेकिन मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि जनवरी में दो दिन फरीदाबाद में मीटिंग हुई थी। स्पीकर साहब, ये हाउस में जवाब गलत दे रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये कब तक अखबारों में विज्ञापन दे देंगे ?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, हम जल्दी ही इंडस्ट्रियलिस्ट्स की एक कांफ्रेंस बुला रहे हैं और उसकी अध्यक्षता हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे।

**Posts advertised by Central Cooperative Bank Ltd.,
Gurgaon**

***1643. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether any post were advertised by the Central Cooperative Bank Ltd., Gurgaon during the tenure of its Chairman who was appointed in 1978-79;

(b) if so, the name of the Newspaper in which the said advertisement appeared together with its circulation in the rural and urban areas separately;

(c) whether Government have received any complaint that the Newspaper referred to in part (b) having

negligible circulation in the rural areas the candidates belonging to the rural areas could not apply for the advertised posts; and

(d) if reply to part (c) above be in the affirmative whether there is any proposal to readvertise the above said posts in some other Newspaper; if so, the name thereof and, if not, the reasons therefore ?

Cooperation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) Yes.

(b) 'The Financial Express' dated 15-6-79. The extent of its circulation in rural and urban areas separately is not available.

(c) Yes.

(d) The posts are being readvertised in the Daily Tribune' with simultaneous notification to the District Employment Exchange, Gurgaon.

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय हिन्दी के अच्छे जानकार हैं, इसलिए ये हिन्दी में ही अपना उत्तर देते तो उचित था। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि इन पदों को दोबारा विज्ञापित करने की क्यों आवश्यकता हो रही है ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यकता इसलिए हुई कि हमारे पास एक रिप्रजेन्टे तन आया कि इन

पोस्टस की एडवरटाइजमेंट ठीक ढंग से नहीं हुई है और लोगों तक इस की सूचना ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई है। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' जो अखबार है, जिसमें यह विज्ञापन दिया गया था, यह सर्कुलेशन में कम था और इसीलिये बहुत कम आदमियों तक यह पहुंच पाया जिसके कारण बहुत से लोगों को इन पोस्टों की जानकारी नहीं हो सकी और पूरे आदमी इन पोस्टस के लिये ऐप्लाइ नहीं कर सके। पहले जो एडवरटाइजमेंट की गई थी, वह केवल गुडगांव कोआप्रेटिव बैंक के लिये की गई, अब फरीदाबाद जब से जिला बना है वहां पर भी सेंट्रल कोआप्रेटिव बैंक बनने के कारण पोस्टस की भर्ती की जानी हैं इसलिये इन दोनों के लिये भर्ती किये जाने के कारण दोबारा पोस्टस की एडवरटाइजमेंट करवानी आवश्यक हो गई।

चौधरी गया लाल: अध्यक्ष महोदय, 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' अखबार दिल्ली से निकलता है और हरियाणा में इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस अखबार में विज्ञापन देने के कारण कुछ नियुक्तियां हुई हैं कि नहीं ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कोई नियुक्ति नहीं हुई बल्कि इस बारे में पहली ही आदेश दिए जा चुके हैं और इन पोस्टस को री-एडवरटाइज किया जा रहा है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गुड़गांव सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक के लिये जिन लोगों को इंटरव्यू लैटर्ज इ पू कर दिये गये हैं, उसके बारे में सरकार क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

ठाकुर बीर सिंह: ये सब कौन्सिल कर दिये गये हैं और इन पोस्टस को फिर से री ऐडवरटाइज किया जाएगा। किसी ऐसे अखबार के द्वारा जैसा कि ट्रिब्यून है या कोई दूसरा अखबार जो अच्छी तरह से प्रचलित होगा, उसमें यह विज्ञापन दिया जाएगा ताकि गांवों के लोगों तक भी यह पहुंच सके।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' अखबार में इन पोस्टों के लिये विज्ञापन दिया गया जो कि बहुत कम प्रचलित है और जिसकी सर्कुले शन भी बहुत कम है जबकि नियमों के अनुसार सरकार को किसी ऐसे अखबार में विज्ञापन देना चाहिये जिसकी सर्कुले शन बहुत ज्यादा हो और वह अखबार ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में जाता हो। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह ऐसे अखबारों में विज्ञापन देकर यूं ही सरकार का पैसा क्यों बरबाद किया गया क्योंकि इसका लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है ? क्या इस बारे में कोई जांच करवाई जाएगी कि इसमें किस दोष है ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय यह विज्ञापन 15-6-1979 को दिया गया था और यह हमारे टाइम में नहीं हुआ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब 15-6-1979 को हम भी मिनिस्टर नहीं थे, चौधरी भजन लाल जी सहकारिता मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान आप सवाल पूछिये। कोई पुरानी हिस्टरी यहां पर नहीं लिखी जा रही है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो उस समय इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त के जो चेयरमैन थे वे माननीय चौधरी देवी लाल जी के सपुत्र चौधरी ओम प्रकाश के बड़े मित्र थे। उनका नाम श्री सुखबीर सिंह था, उन्होंने ही इन्हें चेयरमैन बनवाया था। उन्होंने यह ऐडवरटाइजमेंट करवाई थी। बाद में हमने इसको रोका और अब फिर से ऐडवरटाइजमेंट करवा रहे हैं ताकि सब लोगों को इंसाफ मिल सके।

श्रीमती सुशामा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अभी सहकारिता मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' की सर्कुलेशन इतनी नहीं थी जिसके कारण यह अखबार ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया और अब ट्रिब्यून में इन पोस्टस के लिये विज्ञापन दिया जा रहा है। मैं इन से यह जानना चाहती हूँ कि क्या ट्रिब्यून अखबार ऐसा है जो कि देहातों तक ज्यादा जाता है? क्यों ने हिन्दी और उर्दू के जो वरनैकुलर पेपर्स हैं, उनमें इन

पोस्टस के विज्ञापन दिये जाएं क्योंकि वे ज्यादातर देहाती इलाकों में जाते हैं और लोग उन्हें पढ़ते भी हैं ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, रूलज के मुताबिक एक ऐसे अखबार में विज्ञापन देना चाहिये जिसकी वाइड सर्कुले गन हो। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि इस स्टेट में कौन सा अखबार ज्यादा प्रचलित है और किस अखबार को ज्यादा पढ़ा जाता है। उसी अखबार में हम विज्ञापन देना ज्यादा जरूरी समझते हैं दूसरे अखबारों को भी विज्ञापन देते हैं लेकिन रूलज के मुताबिक एक ही अखबार को जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित हो, ऐडवरटाइजमेंट दी जाती है।

मास्टर िव प्रसाद: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी ऐसे अखबार में ऐडवरटाइजमेंट करने का विचार रखती है जिसकी सर्कुले गन स्टेट में सबसे ज्यादा हो और जिसको सबसे ज्यादा देहातों में पढ़ते हों ताकि वे लोग उसका फायदा उठा सकें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि विज्ञापन ऐसे अखबारों में दिया जाए जो कि देहातों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस बारे में हिन्दी और उर्दू के पेपर्ज का भी ध्यान रखा जाएगा।

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि मैंने डिपार्टमेंट को पर्टीकुलरली इस केस के लिये तो क्या बल्कि जनरल इंड्रवॉन्ज इतू कर दी है कि जब भी कोई पोस्ट भरनी हो वे उसकी ऐडवरटाइजमेंट लार्ज सर्कुलेशन वाले अखबारों में दिया करें।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहले ऐप्लाइ कर रखा है, क्या अब उन्हें दोबारा भी ऐप्लाइ करना होगा ? हो सकता है कि अब वे ऐज की डिस्क्वालिफिकेशन के कारण रह जाएं। क्या ऐसे कैंडीडेट्स के साथ कोई रियायत देने का सरकार विचार रखती है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले ही सरकारी नौकरियों के लिए 27 साल की ऐज को बढ़ाकर 30 साल कर दिया है और जिन बच्चों ने पहले ऐप्लाइ किया हुआ है, उनकी ऐप्लीकेशन को वैलिड माना जाएगा।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद एक अलग जिला बन गया है। इससे पहले गुड़गांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिये जो वैकैन्सीज निकाली गई थी, वह केवल उसी से सम्बन्धित थीं लेकिन अब सरकार री-ऐडवरटाइज करने जा रही है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फरीदाबाद के लिये अलग से ऐडवरटाइजमेंट किया जाएगा ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, दोनों जिलों के लिये अलग अलग ऐडवरटाइजमेंट किया जाएगा क्योंकि अब बाइफरके तन हो चुकी है।

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, उस समय के चेयरमैन ने जो इस प्रकार की फेवर करने के लिये एक छोटे से अखबार में यह विज्ञापन दिया था, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है क्योंकि यह काफी इल्लीगल बात थी ?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो इररैगुलैरिटी है, इल्लीगैलिटी नहीं है।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने चौधरी देवी लाल जी के समय के एक चेयरमैन साहब का हवाला देते हुए कहा कि उसी के कारण यह सब कुछ हुआ। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कहीं आज भी उसी तरह का कोई आदमी सरकार तो नहीं लगाने जा रही जिससे फिर इसी तरह से काम होते रहें ? (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not question and it has got not relevance.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये खुद ही हैं और कोई नहीं हैं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Question Hour is now over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों
के लिखित उत्तर

Opening of Liquor Shops on G.T. Road

***1630. Shri Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Government has banned the opening of liquor shops on the G.T. Road in the State; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to lift the ban referred to in part (a) above ?

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल):

(ए) जी हां, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा चलाये जाने वाले ठेकों को छोड़ कर कोई भी भाराब का ठेका जी० टी० रोड से 100 मीटर से कम दूरी पर स्थापित नहीं हो सकता।

(बी) जी नहीं।

Hospital Building at Darba Kalan

***1522. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the hospital building located at Darba Kalan in District Sirsa; if so, the time by which the renovation work is likely to be taken in hand; and

(b) the steps, if any, taken to renovate the staff quarters of the said hospital ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 1. नहीं ।

2. प्र न नहीं उठता ।

(ख) कोई नहीं ।

Hali Lake

***1513. Chaudhri Satvir Singh Malik:** Will the Minister for Irrigation and Power be please to state the total water in cusecs released to the Hali Lake at Panipat the year 1979-80 (upto 15th January, 1980) ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
वर्ष 1979-80 में 15-1-80 तक हाली झील, पानीपत के लिये 29 क्यूसिक डेज (2505600 घनफुट) पानी छोड़ा गया ।

Children born in Medical College Hospital, Rohtak

***1548. Chaudhri Sant Kumar:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of children born in Medical College Hospital, Rohtak during the period from 1st January 1979 to 31st December, 1979;

(b) the total number of delivery cases in which the children were born after operation;

(c) the total number of delivery cases which resulted in the death of the newly born child or his/her mother;

(d) the steps taken or proposed to be taken by the Government to avoid deaths to in part (c) in the Medical College Hospital, Rohtak in future; and

(e) whether the Gynae Department of the Medical College Hospital, Rohtak is adequately staffed ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 1600

(ख) 695

(ग) 1. नवजात बच्चे 137

2. प्रसूति स्त्रियां 11

(घ) 1. मैडीकल कालेज, रोहतक में प्रसूति केसिज को सम्भालने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। ऊपर भाग (ग) में वर्णित मृत्युएं चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण नहीं थी। वास्तव में, अधिकांश गर्भवति स्त्रियां अस्पताल में केवल उसी समय लाई जाती हैं जब ऐसे केसिज दाईयों की असावधानी के परिणामस्वरूप बच्चे को जन्म दिलवाने में कठिन हो जाते हैं। ऐसी मृत्युओं की घटनाओं की संख्या कम की जा सकती है यदि गर्भवति स्त्रियां उचित समय पर बच्चे के जनम से पूर्व तथा बच्चे के जन्मोपरान्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करती रहें।

2. प्र न उत्पन्न नहीं होता।

(च) जी हां।

Opening of 25 Bed Hospital in Karnal Constituency

***1533. Shri Preet Singh:** Will the Chief Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a 25 bed hospital at village Balu in Kalayat constituency of District Jind, if so, the time by which it is likely to be opened ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हां। फिर भी वित्त की कमी के कारण इस स्टेज पर निर्धारित समय नहीं बताया जा सकता।

New Sewerage System in Rohtak

***1598. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether the new sewerage system is being laid in Rohtak City; if so, the names of the localities where it is being laid alongwith the estimated expenditure to be incurred thereon and the extent to which the said work has so far been done ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): जी हां, अनुबन्ध में दी गई अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

अनुबन्ध

मल निकास सिस्टम में मुख्य सीवर एवं ब्रान्च सीवर सम्मिलित हैं मल निकास निम्नलिखित कालोनियों में बिछाया जा रहा है:—

(क)	वह कालोनी जहां मुख्य सीवर बिछाया जा रहा है :-	
	1	जाट कालेज होस्टल क्षेत्र
	2	गांधी नगर कैम्प (मडहटस)
	3	कैम्प कालोनी
	4	डी0एल0एफ कालोनी

	5	जगदी 1 कालोनी-1
	6	जगदी 1 कालोनी-2 (राम नगर)
	7	भीस्ती पूरा
	8	झझर रोड के क्षेत्र का कुछ भाग
	9	रेलवे सड़क क्षेत्र का भाग
	10	अनाज मंडी के पीछे का क्षेत्र
	11	रेलवे लाईन के साथ का क्षेत्र
(ख)	वह कालोनी क्षेत्र जहां ब्रांच सीवर बिछाया जा रहा है :-	
	1	रेलवे सड़क क्षेत्र
	2	आय नगर
	3	ग्रीन सड़क क्षेत्र
	4	डी0एल0एफ0 कालोनी
	5	माडल टारुन
	6	माडल टारुन का विस्तार क्षेत्र
	7	डी0एल0एफ0 सड़क क्षेत्र (उत्तरीय भाग)

8	किला सड़क क्षेत्र
9	बारा बाजार क्षेत्र
10	बाबरा मोहल्ला
11	किला मोहल्ला
12	सोनीपत सड़क क्षेत्र
13	झंग कालोनी
14	डेरी मोहल्ला (नया तथा पुराना)
15	भाोरे मारकीट
16	प्रताप मोहल्ला
17	सुभाश नगर का भाग
18	संत नगर
19	पुराना वार्ड नं0 6
20	पुराना वार्ड नं0 9
21	भगवान कालोनी
22	ब्राह्मण मंडी

	23	लक्ष्मी नगर
	24	चिनौद कालोनी
	25	आई0टी0आई0 के नजदीक के स्थान
	26	रविदास नगर का भाग
	27	विजय नगर
	28	देहली गेट बाजार क्षेत्र
	29	पुरानी सब्जी मंडी

इस योजना पर अनुमानित खर्चा 88.62 लाख रुपये है। जाट कालेज क्षेत्र के मुख्य सीवर के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Civil Hospitals and Civil (Allopathic) Dispensaries

352. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the districtwise number and names of Civil Hospitals and Civil (Allopathic) Dispensaries functioning in the State at present together with capacity of beds provided in each, separately;

(b) the districtwise number and names of Civil Dispensaries as referred to in part (a) above as on 31-3-77 in

the State, together with the capacity of beds provided in each one of them, separately; and

(c) the districtwise number and names of Civil Dispensaries as referred to in part (a) above, that are likely to be opened during the years 1980-81 and 1981-82, separately, together with the number of beds likely to be provided in each one of them ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क तथा ख): सूचना अनुबन्ध 1 व 2 में संलग्न है।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में खोले जाने वाले सिविल अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों की संख्या तथा नामों का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

अनुबन्ध-1

भाग (क)

जिले का नाम	अम्बाला		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	7		
नाम	1	राजकीय सामान्य	200

		अस्पताल, अम्बाला	
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, जगाधरी	25
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, नारायणगढ़	50
	4	मुकुन्द लाल सामान्य अस्पताल, यमुनानगर	50
	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, अम्बाला छावनी	56
	6	राजकीय सामान्य अस्पताल, कालका	25
	7	राजकीय सामान्य अस्पताल, छछरौली	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	13		

नाम	1	महिला डिस्पेंसरी, सढोरा	4
	2	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, बलदेव नगर, अम्बाला	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मोरनी	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कोट	2
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पंचकूला	4
	6	जिला टी0बी0: नियंत्रण केन्द्र, अम्बाला	36
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भाहजादपुर	20
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, नूरपूर	2

	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलानौर	2
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बराड़ा	4
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कालेसर (पग्गल में कार्य कर रही है)	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सबापुर	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, नाहरपुर	4
<p>नोट:— इनके अतिरिक्त हरियाणा एम0एल0ए0 प्लैट होस्टल डिस्पेंसरी, चण्डीगढ़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बाला के प्रासासनिक नियंत्रण में हैं।</p>			
जिले का नाम	भिवानी		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की	6		

संख्या			
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, भिवानी	300
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, लोहारू	25
	3	श्री सोहन लाल राजकीय सामान्य अस्पताल, दुराला	8
	4	राजकीय सामान्य अस्पताल, चरखी दादरी	50
	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, तो गाम	25
	6	राजकीय सामान्य अस्पताल, बवानी खेड़ा	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की	23		

संख्या			
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सिवाणी	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, चंग	2
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, महुदानी	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, वीरन	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बहल	4
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, नालवा	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अलखपुरा	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, उचीना	
	9	राजकीय ग्रामीण	4

		डिस्पेंसरी, सुई	
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, माधोगढ़	10
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, धनाना	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मनहेरू	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तलवण्डी रूका	4
	14	मोबाइल डिस्पेंसरी, भिवानी	
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दिनोंद	4
	16	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मानकवास	4
	17	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सन्तोखपुरा	4

	18	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सुहासरा	4
	19	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, छप्पर	4
	20	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भूशण	4
	21	टी0बी0: क्लीनिक, लोहारू	8
	22	जिला टी0बी0: नियंत्रण केन्द्र, भिवानी	25
	23	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, माई कलां	4
जिले का नाम	गुड़गांव		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	4		

नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, गुड़गांव	120
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, फिरोजपुर झिरका	25
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, नूंह	25
	4	प्रसूति अस्पताल, हैली मण्डी	4
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	10		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, वीवन	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बगरोला	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, उजीना	4

	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, फिगवां	3
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तावाडू	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, सोहना	10
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मखपुरा	4
	8	जिला टी0बी0: नियंत्रण केन्द्र, गुड़गांव	2
	9	स्कूल हैल्थ क्लिनिक, गुड़गांव	
	10	मोबाईल डिस्पेंसरी, नूंह	

नोट:- इनके अतिरिक्त हरियाणा हरियाणा भवन डिस्पेंसरी, नई दिल्ली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुड़गांव के प्रासन्निक नियंत्रण में हैं।

जिले का नाम	फरीदाबाद		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	3		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, पलवल	30
	2	बी०के० अस्पताल, फरीदाबाद	200
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, बल्लभगढ़	50
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	14		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तिगांव	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सूलपुर	4

	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, धोज	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सुलहेरा	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तपा-बिलोचपुर	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, होडल	8
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, हथीन	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अनंगपुर	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मोहना	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पल्ला	4
	11	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, सैक्टर-7,	4

		फरीदाबाद	
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कटेसरा	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अमरपुर	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पुनहेड़ा खुर्द	4
जिले का नाम	हिसार		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	6		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, हिसार	200
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, हांसी	50
	3	राजकीय सामान्य	50

		अस्पताल, फतेहाबाद	
	4	राजकीय सामान्य अस्पताल, आदमपुर	10
	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, टोहाना	50
	6	टी0 बी0 अस्पताल, हिसार	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	24		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, उकलाना	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बालसमन्द	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बड़ोपल	4
	4	राजकीय ग्रामीण	4

		डिस्पेंसरी, बास	
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अग्रोहा	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, बगराओ	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दौलतपुर	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सामैन	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बोथन कलां	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, गुराना	4
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कैमरी	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मामुपुर	4

	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दाता	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पिरथला	4
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मयोद कलां	4
	16	मिनी सचिवालय निवास कालोनी डिस्पेंसरी, हिसार	4
	17	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, चुली बागड़ियां	4
	18	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, हसनगढ़	4
	19	टी0बी0 क्लीनिक, टोहाना	8
	20	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कुला	4

	21	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, हिसार	
	22	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, पुट्ठी सामन	4
	23	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, पाबरा	4
	24	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, पुट्ठी मंगल खां	4
जिले का नाम	सिरसा		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	3		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, सिरसा	100
	2	राजकीय सामान्य तथा प्रसूति अस्पताल, मंडी डबवाली	28

	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, चोटाला	30
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	11		
नाम	1	जिला टी0बी0 कन्ट्रोल सैन्टर, सिरसा	2
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, रोड़ी	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, ऐलनाबाद	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलांवाली	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दड़बां कलां	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, दड़वी	4

	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, देसू जोधा	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, गौरी वाला	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, खारिया	4
	10	जैयना देवी भाहरी डिस्पेंसरी, ऐलनाबाद	11
	11	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, मलेकां	4
जिले का नाम	जीन्द		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	3		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, जीन्द	50
	2	राजकीय सामान्य	50

		अस्पताल, नरवाना	
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, सफीदों	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	8		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बालू	
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, छत्तर	
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दातरथ	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, जयजयवन्ती	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बाटा	4

	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, उचाना	7
	7	जिला टी0बी0 केन्द्र, जीन्द	
जिले का नाम	करनाल		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	2		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, करनाल	200
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, पानीपत	50
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	14		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मधुबन	4

	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, जुण्डला	2
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तरावड़ी	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, नौलथा	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मडलोडा	4
	6	होम फार एजड एण्ड इनफरमरी डिस्पेंसरी, पानीपत	
	7	महिला आश्रम डिस्पेंसरी, करनाल	
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कुंजपुरा	2
	9	फस्ट एड पोस्ट कम डिस्पेंसरी, उचाना लेक	

	10	स्कूल हैल्थ क्लिनिक, करनाल	
	11	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, करनाल	22
	12	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, सिंवाह	4
	13	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, जलमाना	4
	14	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डी	4
जिले का नाम	कुरुक्षेत्र		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	4		
नाम	1	लोकनायक जे0पी सामान्य अस्पताल,	50

		कुरुक्षेत्र	
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, भाहबाद	25
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, कैथल	73
	4	प्रसूति अस्पताल, रादौरा	14
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	11		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बबैन	4
	2	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, कुरुक्षेत्र	
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, ठसका मीरांजी	4

	4	राजकीय भाहरी डिस्पैंसरी, लाडवा	8
	5	राजकीय भाहारी डिस्पैंसरी, पुण्डरी	12
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, हबरी	2
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, पिपली	2
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, थानेसर	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, भागुल	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, इसमाईलाबाद	4
	11	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, अलाहर	

जिले का नाम	महेन्द्रगढ़		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	3		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, नारनौल	100
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, महेन्द्रगढ़	25
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, रिवाड़ी	50
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	17		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भौजावास	2
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बालका	4

		कलां	
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सिरौही बोली	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, सेहमा	
	5	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, नारनौल	16
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, धनाजीनाबाद	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, जाटूसाना	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मीरपुर	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दारुहेड़ा	2

	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बुधबाल	6
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, रामपुर	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अन्तड़ी	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बासडौडा	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, टंकरी	4
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बयाल	4
	16	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, फतेहपुरी	4
	17	मोबाईल डिस्पेंसरी, नारनौल	
जिले का नाम	रोहतक		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक)	7		

राजकीय) हस्पतालों की संख्या			
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, रोहतक	85
	2	कमला नेहरू अस्पताल, बहादुरगढ़	25
	3	इनफरवरी महिला आश्रम हस्पताल, रोहतक	10
	4	राजकीय सामान्य अस्पताल, झज्जर	25
	5	मैडीकल कालेज अस्पताल, रोहतक	1074
	6	चितरंजन दास मोबाईल अस्पताल, रोहतक	50
	7	राजकीय सामान्य अस्पताल, बेरी	48

सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	18		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सांधी	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मातनहेल	2
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मछरौली	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, डुजाना	8
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भालौट	4
	6	मडहट कालौनी डिस्पेंसरी, रोहतक	
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सिवाणी	4

	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बीरोहर	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, महम	8
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, गुरावर	4
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भम्बेबा	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलानौर	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कौसली	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, छुड़ानी	4
	15	जिला टी0बी0 क्लीनिक केन्द्र, रोहतक	
	16	भाहरी डिस्पेंसरी	4

		डिवाजी कालोनी, रोहतक	
	17	मोबाईल ओपथेमिलोजी क्लीनिक, रोहतक	
	18	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजगढ़	10
जिले का नाम	सोनीपत		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	2		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, सोनीपत	50
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, मोहाना	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की	11		

संख्या			
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दाबाता	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मुरथल	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, फरमाना	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, जाखौली	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पुरखास	4
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बुटाना	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बिदलान	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भुटाना जफराबाद	4

	9	राजकीय डिस्पेंसरी, माजरी	ग्रामीण मोई	4
	10	राजकीय डिस्पेंसरी,	ग्रामीण सीवणमल	4
	11	जिला नियंत्रण सोनीपत	टी0बी0 केन्द्र,	

नोट:- हरियाणा सरकार ने अपनी यादी क्रमांक 6912-1एच0बी0 1-76/21161 दिनांक 30-6-76 में सिविल अस्पतालों तथा सिविल/रूरल डिस्पेंसरियों के नाम राजकीय सामान्य अस्पतालों तथा राजकीय भाहरी/ग्रामीण डिस्पेंसरियों में बदल दिए हैं और यह संस्थान जैसे ऊपर वर्णन किया गया है। अन्य प्रकार के अस्पतालों/डिस्पेंसरियों जैसे कि ई0एस0आई0, नहर, जेल, पुलिस विभाग, सबसीडियरी डिस्पेंसरियां, भाहरी स्थानीय भासन या स्वैच्छिक संस्थाओं के संस्थानों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से भिन्न हैं।

ग्रामीण डिस्पेंसरियों में से कुछ में उपचार कार्य के अतिरिक्त, बीमारियों की रोकथाम के लिए अब कुछ

इनफरास्ट्रक्चर (Infrastucture) उपलब्ध किया जा रहा है तथा इन डिस्पेंसरियों को सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र का नाम दिया है ।

अनुबन्ध - 2

भाग (ख)

जिले का नाम	अम्बाला		बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	7		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, अम्बाला	200
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, नारायणगढ़	50
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, जगाधरी	25
	4	मुकन्द लाल राजकीय सामान्य अस्पताल, यमुना नगर	50

	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, अम्बाला छावनी	56
	6	राजकीय सामान्य अस्पताल, कालका	25
	7	राजकीय सामान्य अस्पताल, छछरौली	10
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	13		
नाम	1	महिला डिस्पेंसरी, सढौरा	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलानौर	2

	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मोरनी	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, कोट	2
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पंचकूला	4
	6	जिला क्षयरोग केन्द्र, अम्बाला	36
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भाहजादपुर	20
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, नूरपुर	2
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बराड़ा	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलेसर	4
	11	राजकीय ग्रामीण	4

		डिस्पेंसरी, नाहरपुर	
	12	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, बलदेव नगर, अम्बाला भाहर	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, खेड़ा पावर हाउस, जगाधरी	4

नोट:- इनके अतिरिक्त हरियाणा एम0एल0ए0 प्लैट होस्टल डिस्पेंसरी, चण्डीगढ़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बाला के प्रासासनिक नियंत्रण में हैं।

जिले का नाम	भिवानी	बिस्तरे
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	5	
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, भिवानी
		200

	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, लोहारू	25
	3	श्री सोहन लाल राजकीय सामान्य अस्पताल, दुराला	8
	4	राजकीय सामान्य अस्पताल, चरखी दादरी	50
	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, तो गाम	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	23		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सिवाणी	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, चंग	2

	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, महुदानी	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, वीरन	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बहल	4
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, नालवा	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, अलखपुरा	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, उचीना	
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, सुई	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, माधेगढ़	10
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, धनाना	4

	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मनहेरू	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, तलवण्डी रूका	4
	14	मोबाइल डिस्पैंसरी, भिवानी	
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, दिनोंद	4
	16	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मानकवास	4
	17	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, सन्तोखपुरा	4
	18	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, सुहासरा	4
	19	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, छप्पर	4

	20	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भूशण	4
	21	टी0बी0: क्लीनिक, लोहारू	8
	22	जिला टी0बी0: नियंत्रण केन्द्र, भिवानी	25
	23	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, माई कलां	4
जिले का नाम	गुड़गांव	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	7		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, गुड़गांव	120
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, फिरोजपुर	25

		झिरका	
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, नूंह	25
	4	प्रसूति अस्पताल, हैली मण्डी	4
	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, पलवल	30
	6	बी०के० अस्पताल, फरीदाबाद	200
	7	राजकीय सामान्य अस्पताल, बल्लभगढ़	50
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	24		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, वीवन	4

	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बगरोला	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, उजीना	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, फिगवां	3
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तावाडू	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, सोहना	10
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मखपुरा	4
	8	जिला टी0बी0: नियंत्रण केन्द्र, गुड़गांव	2
	9	स्कूल हैल्थ क्लीनिक, गुड़गांव	
	10	मोबाईल डिस्पेंसरी,	

		नूंह	
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तिगांव	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सूलपुर	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, धोज	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सुलहेरा	4
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, तपा-बिलोचपुर	4
	16	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, होडल	8
	17	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, हथीन	4
	18	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अनंगपुर	4

	19	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मोहना	4
	20	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पल्ला	4
	21	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, सैक्टर-7, फरीदाबाद	4
	22	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कटेसरा	4
	23	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अमरपुर	4
	24	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पुनहेड़ा खुर्द	4

नोट:- इनके अतिरिक्त हरियाणा हरियाणा भवन डिस्पेंसरी, नई दिल्ली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुड़गांव के प्रासासनिक नियंत्रण में हैं।

जिले का नाम	हिसार	बिस्तरे	
-------------	-------	---------	--

सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	6		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, हिसार	200
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, हांसी	50
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, फतेहाबाद	50
	4	राजकीय सामान्य अस्पताल, आदमपुर	10
	5	राजकीय सामान्य अस्पताल, टोहाना	50
	6	टी० बी० अस्पताल, हिसार	25
सिविल (सार्वजनिक)	21		

राजकीय) डिस्पैंसरियों की संख्या			
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, उकलाना	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बालसमन्द	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बड़ोपल	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बास	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, अग्रोहा	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पैंसरी, बंगरान	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, दौलतपुर	4
	8	राजकीय ग्रामीण	4

		डिस्पैंसरी, सामैन	
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बोथन कलां	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, कैमरी	4
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मामुपुर	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, दाता	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, पिरथला	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मयोद कलां	4
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, चुली बागड़ियां	4

	16	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, हसनगढ़	4
	17	टी0बी0 क्लीनिक, टोहाना	8
	18	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कुला	4
	19	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, पुट्ठी सामन	4
	20	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, पाबरा	4
	21	सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र, पुट्ठी मंगल खां	4
जिले का नाम	सिरसा	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	2		

नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, सिरसा	100
	2	राजकीय सामान्य तथा प्रसूति अस्पताल, मंडी डबवाली	28
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	9		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, चोटाला	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, रोड़ी	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, ऐलनाबाद	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलांवाली	4

	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दड़बां कलां	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, दड़वी	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, देसू जोध्या	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, गौरी वाला	4
	9	जैयना देवी भाहरी डिस्पेंसरी, ऐलनाबाद	11
जिले का नाम	जीन्द	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	3		

नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, जीन्द	50
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, नरवाना	50
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, सफीदों	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	8		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बालू	
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, छत्तर	
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दातरथ	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी,	4

		जयजयवन्ती	
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बाटा	4
	6	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, उचाना	7
	7	जिला टी0बी0 केन्द्र, जीन्द	
जिले का नाम	करनाल	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	2		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, करनाल	200
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, पानीपत	50
सिविल (सार्वजनिक)	10		

राजकीय) डिस्पैंसरियों की संख्या			
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मधुबन	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, जुण्डला	2
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, तरावड़ी	4
	4	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, नौलथा	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मडलोडा	4
	6	महिला आश्रम डिस्पैंसरी, करनाल	
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, कुंजपुरा	2
	8	फस्ट एड पोसट कम डिस्पैंसरी, उचाना	

		लेक	
	9	स्कूल हैल्थ क्लिनिक, करनाल	
	10	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, करनाल	22
जिले का नाम	कुरुक्षेत्र	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	4		
नाम	1	लोकनायक जे0पी सामान्य अस्पताल, कुरुक्षेत्र	50
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, भाहबाद	25
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, कैथल	73

	4	प्रसूति अस्पताल, रादौरा	14
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	11		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बबैन	4
	2	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, कुरुक्षेत्र	
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, ठसका मीरांजी	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, लाडवा	8
	5	राजकीय भाहारी डिस्पेंसरी, पुण्डरी	12

	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, पिपली	2
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, थानेसर	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भागुल	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, इसमाईलाबाद	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अलाहर	
जिले का नाम	महेन्द्रगढ़	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	3		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, नारनौल	100

	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, महेन्द्रगढ़	25
	3	राजकीय सामान्य अस्पताल, रिवाड़ी	50
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	17		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भौजावास	2
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बालका कलां	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सिरौही बोली	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, सेहमा	

	5	जिला टी0बी0 नियंत्रण केन्द्र, नारनौल	16
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, धनाजीनाबाद	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, जाटूसाना	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मीरपुर	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, दारुहेड़ा	2
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बुधबाल	6
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, रामपुर	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, अन्तड़ी	4

	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बासडौडा	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, टंकरी	4
	15	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बयाल	4
	16	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, फतेहपुरी	4
	17	मोबाईल डिस्पेंसरी, नारनौल	
जिले का नाम	रोहतक	बिस्तरे	
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या	7		
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, रोहतक	85

	2	कमला नेहरू अस्पताल, बहादुरगढ़	25
	3	इनफरवरी महिला आश्रम हस्पताल, रोहतक	10
	4	राजकीय सामान्य अस्पताल, झज्जर	25
	5	मैडीकल कालेज अस्पताल, रोहतक	1074
	6	चितरंजन दास मोबाईल अस्पताल, रोहतक	50
	7	राजकीय सामान्य अस्पताल, बेरी	48
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	16		

नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सांधी	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मातनहेल	2
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मछरौली	4
	4	राजकीय भाहरी डिस्पेंसरी, डुजाना	8
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भालौट	4
	6	मडहट कालौनी डिस्पेंसरी, रोहतक	
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, सिवाणी	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, बीरोहर	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, महम	8

	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, गुरावर	4
	11	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, भम्बेबा	4
	12	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कलानौर	4
	13	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, कौसली	4
	14	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, छुड़ानी	4
	15	जिला टी0बी0 क्लीनिक केन्द्र, रोहतक	
	16	मोबाईल ओपथेमीलोजी क्लीनिक, रोहतक	
जिले का नाम	सोनीपत	बिस्तरे	
सिविल	2		

(सार्वजनिक राजकीय) हस्पतालों की संख्या			
नाम	1	राजकीय सामान्य अस्पताल, सोनीपत	50
	2	राजकीय सामान्य अस्पताल, मोहाना	25
सिविल (सार्वजनिक राजकीय) डिस्पेंसरियों की संख्या	10		
नाम	1	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, डबेटा	4
	2	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, मुरथल	4
	3	राजकीय ग्रामीण डिस्पेंसरी, फरमाना	4

	4	राजकीय भाहरी डिस्पैंसरी, जाखौली	4
	5	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, पुरखास	4
	6	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बुटाना	4
	7	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, बिडलान	4
	8	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, भुटाना जफराबाद	4
	9	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, मोई माजरी	4
	10	राजकीय ग्रामीण डिस्पैंसरी, सीवणमल	4

नोट:- हरियाणा सरकार ने अपनी यादी क्रमांक 6913-1एच0बी0 1-76/21161 दिनांक 30-6-76 में सिविल

अस्पतालों तथा सिविल/रूरल डिस्पेंसरियों के नाम राजकीय सामान्य अस्पतालों तथा राजकीय भाहरी/ग्रामीण डिस्पेंसरियों में बदल दिए हैं और यह संस्थान जैसे ऊपर वर्णन किया गया है। अन्य प्रकार के अस्पतालों/डिस्पेंसरियों जैसे कि ई0एस0आई0, नहर, जेल, पुलिस विभाग, सबसीडियरी डिस्पेंसरियां, भाहरी स्थानीय भासन या स्वैच्छिक संस्थाओं के संस्थानों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से भिन्न हैं।

ग्रामीण डिस्पेंसरियों में से कुछ में उपचार कार्य के अतिरिक्त, बीमारियों की रोकथाम के लिए अब कुछ इनफ्रास्ट्रक्चर (Infrastucture) उपलब्ध किया जा रहा है तथा इन डिस्पेंसरियों को सबसीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र का नाम दिया है।

Loans from Financial Corporation to Industrial Units

***353. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise number and names of Industrial Units in the State, which got loans from the Haryana Financial Corporation during the period from 1966-67 to 1979-80 (to date) together with rate of interest in ease, separately; and

(b) the district wise number and names of Industrial Units in the State, as referred to in part (a) above, which are defaulters together with the amount of loans given, amount in

default and the action; if any, so far taken for recovery of the same in each case, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उसके मुकाबले में लाभ कम होगा।

Industrial Units and Industrial Cooperative Societies

***354. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise number and names of Industrial Units in the State, which got loans from the Haryana Financial Corporation during the period from 1966-67 to 1979-80 (to date) together with rate of interest in case, separately; and

(b) the district wise number and names of Industrial Units in the State, as referred to in part (a) above, which are defaulters together with the amount of loans given, amount in default and the action; if any, so far taken for recovery of the same in each case, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 1966-67 से 1979-80 तक लगभग 9700 इकाईयों/औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी है। इकाई/औद्योगिक

सहकारी समितिवार सूचना एकत्रित करने में जितना समय तथा परिश्रम लगेगा उसके मुकाबले में लाभ कम होगा।

(ख) ऋण लौटाने में दोशी इकाईयों/औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या 767 है और उनके जिम्मे 49.91 लाख रुपये बकाया हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है। इस राशि की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है। इकाई/औद्योगिक सहकारी समितिवार सूचना एकत्रित करने में जितना समय तथा परिश्रम लगेगा उसके मुकाबले में लाभ कम होगा।

परिशिष्ट "क"

क्रम संख्या	जिला का नाम	इकाईयों की संख्या	राशि (रुपयों में)
1	अम्बाला	107	11,30,921.74
2	कुरुक्षेत्र	53	3,01,155.32
3	करनाल	83	5,46,847.14
4	जीन्द	25	1,48,192.23
5	रोहतक	39'	3,63,756.64

6	सोनीपत	37	2,64,759.50
7	गुड़गांव	72	3,01,951.80
8	फरीदाबाद	4	19,957.50
9	भिवानी	51	3,73,600.84
10	हिसार	145	7,83,345.12
11	सिरसा	73	5,01,484.18
12	महेन्द्रगढ़	78	2,54,589.29
	जोड़	767	49,90,561.30

**Agricultural in the possession of Rehabilitation
Department**

355. Chaudhri Ram Lal Wadhwa; Will the Minister for Agriculture be please to state-

(a) the district-wise acreage of Agricultural land in possession of the Rehabilitation Department in the State on 31-3-1977 and 29-2-1980, separately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to dispose of the land as referred to in part (a) above in the State; if so, the details

thereof togetherwith the date/dates by which the aforesaid land is likely to be disposed of ?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) पुर्नवास विभाग के पास दिनांक 31-3-77 तथा 29-2-1980 को निपटान के लिए उपलब्ध ग्रामीण / अहरी मतरूका कृशि भूमि का जिलावार विवरण संलग्न अनुबन्ध 'ए' तथा 'बी' में अलग अलग दिया गया है।

(ख) ग्रामीण / अहरी मतरूका भूति का निपटान सिका उल्लेख ऊपर पैरा 'क' में किया गया है, विभागीय नियमों/अनुदे गों तथा डिसपलेस्ड परसन्ज (कम्पनसै इन एण्ड रिहेबलीटे इन) एक्ट, 1954 की प्रोवीजन्ज के अनुसार किया जा रहा है, जिनका विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध 'सी' में दिया गया है। क्योंकि मतरूका भूमि की खोज/निपटान एक लगातार विधि है और इसके लिए विभिन्ना स्तरों पर व्यवहारिक औपचारिकताओं की आव यकता है। इसलिए कोई नि चि चल तिथि/तिथियां नहीं दी जा सकती, जिसि तक सारी भूमि का निपटान सम्भव हो सके।

ANNEXURE-A

Statement showing district-wise details of Agricultural Evacuee Lands available on 31-3-1977

Name of	RURAL	URBAN

Distt.					
	Cultivate d in Standard Acres	Banjar in Ordinar y Acres	Ghair Mumkin in Ordinar y Acres	Pure Evacuee in Ordinar y Acres	Ghair Mumkin in Ordinar y Acres
Ambala	766	559	1760	144	
Kurukshetra	384	61	68	259	
Karnal	1359	1177	298	20	
Gurgaon	318	342	587	66	52
Bhiwani	566	363	101	2	
Hissar	1311	46	1166	125	
Rohtak	191	558	1347	20	27
Sonepat	127	46	493	1	3
Jind	62	3	20		
Sirsa					
Narnaul	19	7	127	42	
G. Total	5003	3162	5967	679	82

ANNEXURE-B

**Statement showing district-wise details of Agricultural
Evacuee Lands available on 29-2-1980**

Name of Distt.	RURAL			URBAN	
	Cultivated in Standard Acres	Banjar in Ordinary Acres	Ghair Mumkin in Ordinary Acres	Pure Evacuee in Ordinary Acres	Ghair Mumkin in Ordinary Acres
Ambala	785	433	1589	137	
Kurukshetra	344	106	671	55	
Karnal	657	169	136		
Gurgaon	330	168	575	40	40
Bhiwani	393	151	228		
Hissar	604	71	852	61	
Rohtak	58	20	40	18	
Sonepat	132	93	288	12	
Jind	60	37	20		
Sirsa	53	19	49	2	
Narnaul	6	7	66	22	

G. Total	3452	1274	4514	347	40
----------	------	------	------	-----	----

ANNEXURE-C

Details for the disposal of Evacuee Land

These lands are being disposed of by:-

(i) allotment to unsatisfied claimants from West Pakistan;

(ii) transfer at fixed to tenants/occupants since Kharif, 1960;

(iii) by negotiation to Government Department/institutions if required by them for Public purposes; and

(iv) in restricted auction to the member of Scheduled Castes except the followingh categories which are sold in open acution:

(a) Lands retrieved by the Directory organization set up by the State Rehabilitation Department of security/preparation of accout of each land allottee;

(b) Lands already sold but sale of which has been set aside by competent authority;

(c) lands which are suburdan, potential, residential or commercial sites or in the garden colonies; and

(d) small fragments of land not exceeding one acre surrounded by holdings of owners who are not members of Scheduled Castes.

Each Harijan family is allowed to purchase the rural evacuee land upto 5 Standard Acres including his own holdings, if any. The earnest money of 12½% is recovered from them at the fall of hammer and the balance price i.e. 87½% in 15 equal half yearly instalments bearing no interest. Recovery starts from the first harvest falling after the expiry of one year from the date of delivery of possession of the land.

The Harijans who are in continuous cultivating possession of the rural evacuee agricultural land from kharif, 1960, or earlier, are entitled to purchase such lands by transfer upto 5 standard acres including their own holding, if any, at the concessional price of Rs. 2500/- per standard acre whereas for others the rates are 5000/- for the first two standard acres and Rs. 5200/- for the next three standard acres.

Urban evacuee agricultural lands are being disposed of by and large in open auction in accordance with the provisions of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954, Rules framed thereunder and the instructions issued by the Government from time to time.

Mini-Buses

337. Shri Bhagi Ram; Will the Minister for Transport be pleased to state whether it is a fact that five Mini

Buses have been allotted to the Haryana Roadways Depot at Sirsa; if so, the reasons therefor together with the routes on which these are plying at present ?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): जी नहीं ।

Declaration of Ellenabad as Sub-Tehsil

338. Shri Bhari Ram: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Ellenabad as Sub-tehsil in District Sirsa; if so, the time by which it is likely to be declared as such ?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): मामला सरकार के विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा, इस बारे समय नहीं बताया जा सकता ।

Facility of Drinking Water

349 Shri Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad:

Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the district-wise name of villages where drinking water has been provided in the State during the period from 1-4-1978 to 31-3-1979 and from 1-4-1979 to 31-1-1980 in the State; and

(b) the district-wise names of villages proposed to be supplied drinking water during the period from 1-2-1980 to 31-3-1980 ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) 1. 1-4-1978 से 31-3-1979 तक जिलावार गांवों के नाम जहां पेय जल सुविधा प्रदान की गई है।

जिले का नाम		गांव का नाम		गांव का नाम	
1	अम्बाला	1	मानक ताबारा	2	बटवाल
		3	धनधारू	4	अमराला
		5	कजामपुर	6	खतोली
		7	सुखद निपुर	8	जोहलूवाल
		9	चरनिया	10	कर्णपुर

		11	किरतपुर	12	गरीरान
		13	हंगोली	14	हंगोला
		15	समानवा	16	बगवाली
		17	बगवाला	18	थरवा
		19	भाहजहांपुर	20	हरोली
		21	सामलहेरी	22	धनाना
		23	गोबिन्दपुर	24	तसरोली
		25	तसरोला	26	मकन्दपुर
		27	रसीदपुर	28	भगवानपुर
		29	औरीया	30	मानका
		31	रामपुर सरी	32	बाना मदनपुर
		33	मियांपुर	34	मुगल माजरा
		35	छिछि माजरा	36	फिरोजपुर
		37	कथमाजरा	38	माजरी
		39	इंगो माजरा	40	दोधाली

2	भिवानी	41	सिवाना माजरा	42	तालू
		43	पालावास	44	कलावास
		45	बदराई	46	नागल माला
3	फरीदाबाद	47	कैलगांव	48	खण्डवाली
		49	जाजरू		
4	गुडगांव	50	अकबरपुर नातुल	51	पंडरी
		52	किरा	53	अल्दुका
		54	छछेरा	55	बजरका
		56	छापरा	57	गढ़ी हरसू
		58	लाखूवास	59	कमन्दा
		60	जोतिका	61	फिरोजोधर
5	हिसार	62	बाधावर	63	धाद
		64	नारनौद	65	हाजमपुर
		66	बदचा पर	67	मोहला
		68	बियाना खेरा	69	हेबातपुर

		70	गमरा	71	जालोपुर
		72	दादुपुर		
6	जीन्द	73	फतेहगढ़		
7	करनाल	74	पट्टी कलयाना		
8	महेन्द्रगढ़	75	पवनर	76	खुर्मपुर
		77	जेतपुर	78	मंगल उगरा
		79	मंगल तारा	80	रधुनाथ पुरा
		81	रामसी माजरा	82	निखरी
		83	माजरी दोदा	84	संगवारी
		85	बुधाला	86	लाढूवास गुज्जर
		87	दरियावास	88	माजरा गुरदास
		89	दोवाना	90	भाहाजपुर खालसा
		91	पदनीवास	92	धालीवास

		93	पिथरवास	94	लूडाना
		95	मुकन्दपुर	96	गढी
		97	सदूवास	98	बलानी
		99	गुरावारा	100	गगूहा जट
		101	तेहला	102	मुकन्दपुर
		103	दुचाना	104	बादोपुर
		105	अरोद	106	मोरी
		107	गोमला	108	ऊंचा
		109	नंगल जमालपुर		
9	रोहतक	110	मदीना गिदराना	111	मदीना कोरसन
		112	सुबाना	113	गढी
10	सिरसा	114	मिठी सुरेरा	115	खारी सुरेरा
		116	आसा खेरा	117	तेजा खेरा
		118	भारू खेरा	119	सुखरनवाला
		120	जन्दवाला	121	अबूब भाहर

			सिनोईन		
		122	सकतो खेरा	123	आलीका
		124	मसतीयां	125	डबवाली
		126	खेवाली	127	आनन्दगढ़
		128	चकरीयां	129	रोहनवाली
11	सोनीपत	130	जखोली		

(2) 1-4-79 से 31-1-80 तक जिलावार गांवों के नाम जहां पेय जल सुविधा प्रदान की गई।

अम्बाला	1	भैरों की सैर	2	रतपुर
	3	अबदूलपुर	4	राजीपुर झाजरा
	5	भवाना उपरला	6	दमदमा
	7	भोगपुर जंगी	8	पिंजौर
	9	रामपुर जंगी	10	काना उपरला
	11	खेरा	12	नानकपुर
	13	रामनगर	14	मल्ला

		15	नन्दपुर	16	किदारपुर
		17	प्योरवाला	18	धान्दरु
		19	फिरोजपुर	20	भोगपुर
		21	बेरपुर	22	गढ़ी कोटहा
		23	रोहना	24	देबर
		25	सुलतानपुर		
भिवानी		26	मन्धाना	27	बलयाली
		28	बदेसरा		
फरीदाबाद		29	मदनाका	30	जैनपुर
		31	मदालपुर	32	भामपुरा
		33	करनेरा	34	खेरोका
		35	पुथली	36	अलूंका
		37	जनचौली	38	बिचपुरी
		39	सनपालकी		
गुड़गांव		40	भौंडसी	41	सिलानी

		42	सनचौली	43	झरसा
		44	उलेठा	45	हलालपुर
		46	रोओका	47	हसनपुर सोहना
		48	कालीका	49	खलीलपुर
		50	माहूवास	51	भिरवाली
		52	गुड़गांव		
हिसार		53	दरयापुर	54	जांडली कलां
		55	जांडली खुर्द	56	डिंगसारा
		57	मनावाली	58	सिरधन
		59	चन्द्रावाल	60	खाजौरी जटीं
		61	बुरक	62	कुतिया खेरी
		63	तेलांवाली	64	बन्दहेरी
		65	चौधरीवाली	66	घुरसाल
जीन्द		67	बाटा		
करनाल		68	निसंग		

कुरुक्षेत्र	69	उमरी	70	पबनावा
महेन्द्रगढ	71	चिलरू	72	नौलजा
	73	धोलेरा	74	अमरपुर जौरसी
	75	दनचौली	76	करौली
	77	भोखपुर फिाकारपुर	78	राजपुरा खालसा
	79	किाानगढ	80	बालावास जामनपुर
	81	नंगल रनमोखी	82	खेरी आलमपुर
	83	चन्दा वास	84	कसौला
	85	कतलाना खातुवास	86	पोटी
	87	खेरी मोटला	88	रामबास
	89	बागीपुर	90	घेरलुवास
	91	बाकोपुर	92	कसौली

रोहतक	93	असदपुर खेरा	94	कोका
	95	कुलाना		
सिरसा	96	खेरिया	97	दुखेरा
(ख) (1) 1-2-80 से 29-2-80 तक जिलावार गांवों के नाम जहां पेय जल सुविधा प्रदान की गई।				
अम्बाला	1	भाहपुर	2	गोरखनाथपुर
	3	सितोमाजरा	4	नवाना नगर
	5	खोखरा	6	लेहरू नदी
	7	मोरनवाला (मोरांवाला)	8	सुन्दर पुर
	9	कामी		
भिवानी	10	बरसी	11	हरीता
	12	भेरी	13	बड़ा ब्राह्मणा
	14	बड़ा रंगरां		
गुड़गावां	15	गोपालपुर		
हिसार	16	पाबरा	17	किनाला

	18	कानोह	19	फरीदपुर
जीन्द	20	अलेवा	21	धतरात
रोहतक	22	बादसा	23	मुंडाखेरा
	24	इसमेलपुर	25	अहीर

(2) मास मार्च, 1980 में विभिन्न जिलों के सम्भवतया 68 गांवों में पेय जल सुविधा प्रदान की जायेगी ? इस समय के नाम तथा जिलावार ब्यौरा निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता क्योंकि जल वितरण सामग्री जैसे कि पाईप, सीमेंट, मीनरी, बिजली के कनेक्शन तथा नहरी पानी के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

भाक प्रस्ताव

15.00 बजे

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सी०एम० त्रिवेदी जी के निधन पर एक भाक प्रस्ताव पेश करता हूँ।

यह सदन भूतपूर्व राज्यपाल श्री सी०एम० त्रिवेदी के 14 मार्च 1980 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता है।

श्री सी०एम० त्रिवेदी का जन्म 2 जुलाई 1893 को हुआ। उन्होंने बम्बई तथा आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। वह 1917 में इण्डियन सिविल सर्विस के लिये चुने गये। विभिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात् उन्होंने 1937 से 1942 तक तत्कालीन केन्द्रीय प्रान्तों एवं बराड़ की सरकार के मुख्य सचिव के पद का दायित्व निभाया। जुलाई, 1942 से जनवरी 1946 तक उन्होंने भारत सरकार के 'युद्ध विभाग' (वार डिपार्टमेंट) में सचिव के पद पर कार्य किया।

श्री त्रिवेदी ने उड़ीसा, पंजाब तथा आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल पदों को भी सुभोगित किया। वह आयोजना आयोग के सदस्य भी रहे।

श्री त्रिवेदी को कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1931 में ओ०बी०आई०, 1935 में सी०आई०ई० और दिसम्बर 1945 में के०सी०एस०आई० से सम्मानित किया गया वर्ष 1956 में पद्मभूषण से अलंकृत किया गया।

श्री त्रिवेदी के निधन से देश एक कुल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन भाोक ग्रसत परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो भाोक प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। श्री त्रिवेदी के साथ मेरा भी

और मैं समझता हूँ कि इस हाउस के और कई माननीय सदस्यगण का निजी संबंध रहा है। जब वे पूर्वी पंजाब के गवर्नर थे तो उसने मेरी कई दफा मुलाकात होती थी। श्री त्रिवेदी बहुत लायक आई०सी०एस० अफसरों में से थे। वे न सिर्फ बहुत इन्टेलिजेंट थे बल्कि बहुत बड़े दे आ भक्त भी थे। यह उनके लिये भी और हमारे लिये भी कितने गर्व की बात है कि ब्रिटिश राज के जमाने में भी उनको मुख्तलिफ मौकों पर सम्मानित किया। वास्तव में ऊंचे सरकारी कर्मचारियों में वे बहुत ही ऊंचा दर्जा रखते थे। ऐसे व्यक्ति के निधन पर कुदरती तौर पर यह हाउस इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करेगा।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है प्रतिपक्ष के नेता ने उसका अनुमोदन किया है। मैं भी अपने दल की ओर से उसके बारे में कुछ भाव्य कहना चाहता हूँ। मैं 1957 में जब पहली बार पंजाब विधान सभा में चुन कर आया तो मेरे आने से पहले वे वहाँ पर राज्यपाल नियुक्त थे। मैंने उस वक्त उनके द नि किये थे। स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन काल में एक योग्य प्र शासन अधिकारी के दायित्व का निर्वाहन करते हुए उस समय की सरकार की प्र ांसा प्राप्त की और फिर स्वाधीनता के बाद इस प्रदेश में राज्यपाल के नाते बड़ी कु ालता से काम किया। जबकि उस समय बंटवारे के कारण लाखों आदमी बेघरबार थे और सरकार पर कार्य का बहुत बोझा

था उस समय उन्होंने मंत्रिपरिषद का भलीभांति मार्गदर्शन करते हुए इस प्रदेश की सेवा की। 1975 में गुजरात में, जहां के एक छोटे से कस्बे के वे रहने वाले थे, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते गया था। वहां जाकर मुझे पता लगा कि त्रिवेदी जी यहां रहते हैं। मैं वहां उनके दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनको अपना परिचय करवाया तो मुझे पास बैठा कर उन्होंने प्रदेश की जनता के बारे में और प्रदेश के विकास के बारे में बड़ी रूचि से पूछा। उनके निधन से हमें बहुत दुःख है लेकिन विधाता का निर्णय अटल है। आने वाले ने एक दिन जरूर जाना है। फिर भी एक अच्छे प्रशासक और अच्छे भारत माता के सपूत के जाने से दुःख होना स्वाभाविक है। इन भावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मैंम्बर साहेबान, इसमें कोई भाव नहीं कि श्री सी०एम० त्रिवेदी जी ने अंग्रेजों के जमाने में भी और आजादी मिलने के बाद भी इस प्रदेश की बहुत सेवा की है। वे बहुत महान व्यक्ति थे। जब मैं पहली दफा फौज में सन् 1943 में भरती हुआ तो उस समय मैं कागजों पर सी०एम० त्रिवेदी, सैक्रेटरी, मिनिस्टरी आफ डिफेंस का नाम पढ़ता था। उसे पढ़कर हमारा बहुत उत्साह बढ़ता था और हम सोचा करते थे कि हमारा हिन्दुस्तानी भाई भी इतने ऊंचे पद पर है। उनके निधन पर जो हाउस में फीलिंग्स जाहिर की गई हैं। मैं भी उनके साथ अपने आप को शामिल करता

हूँ और यह मेरी डियूटी है कि जो हाउस की फीलिंगज हैं उनको मैं उनकी फैमिली तक पहुंचाऊँ। अब मैं हाउस से रिकवैस्ट करूँगा कि उनकी याद में दो मिनट के लिये खड़े होकर मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में अंधे व्यक्तियों पर अभिकथित लाठी चार्ज सम्बंधी चर्चा

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, कल अन्धों के ऊपर लाठियां चलाई गईं जिनको दिखता भी नहीं है। (गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। डा० साहब जो अन्धों वाली बात कर रहे हैं यह दिल्ली का मामला है और हरियाणा असेम्बली में इसका जिक्र नहीं हो सकता। (गोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, वे अन्धे हरियाणा के थे और उनको पीटा गया (गोर) कल दिल्ली में जो अंधों पर लाठी चार्ज हुआ

* * * * *

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा प्रान्त के बारे में कोई बात है तो ये आपको उसके बारे में नोटिस दें। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बगैर आपकी इजाजत के बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए (गोर)

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं विघ्न)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, रूल 84 का नोटिस मैं आपकी सेवा में * * * * * (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं यह रिकार्ड नहीं होगा। आपसे मेरे दो निवेदन हैं। एक तो जब मैं खड़ा हूँ, आप कृपा करके बैठ जाएं। दूसरे आप अपना वाल्यूम वाला बटन थोड़ा नीचा रखें। साहेबान जो मुख्य मंत्री जी ने एक प्वांयट आफ आर्डर रेज किया है उसके ऊपर मेरा फैसला यह है कि जो ला एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम हरियाणा स्टेट से बाहर है उसका इस असैम्बली से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उस विषय पर अभी तक मेरे पास कोई नोटिस आया है। ज्यों ही मेरे पास इसके बारे में कोई नोटिस आएगा मैं उस पर फैसला कर दूंगा। (गोर एवं विघ्न)

कामरेड भांकर लाल: अध्यक्ष महोदय * * * * *
* * * (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

स्वामी अग्निवे 1, एम0एल0ए0 की अभिकथित गिरफ्तारी

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, कल फरीदाबाद में स्वामी अग्निवे 1 को गिरफ्तार किया गया। (गोर)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब हाउस चल रहा हो, उस समय कोई मैम्बर अगर हरियाणा के अन्दर गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले पर यहां सदन में बहस होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आप मुझे लिख करके दीजिए। उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। कुछ माननीय सदस्य यहां हाउस में गलत बयानी करते हैं, कि स्वामी अग्निवे 1 जी को गिरफ्तार किया गया है। यह बात बिलकुल गलत है। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, स्वामी अग्निवे 1 जी कल फरीदाबाद में गये। वहां एक फैंकअरी के इर्द गिर्द 500 गज के दायरे में धारा 144 लगी हुई थी। उन्होंने वहां के वर्कर्स को भड़काने की कोशिश की और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके पास जाकर उनको समझाया और समझा कर उनको बाहर छोड़ दिया और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की इसलिए की ताकि उनका नाम अखबारों में आ जाएं और लेबर की * * * * कर सकें (गोर एवं विघ्न)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, the Hon. Minister has said * * * * (Interruptions)

Mr. Speaker: Any thing which reflects on the conduct of the hon. Member will not be recorded. मैम्बर साहेबान जब भी कोई हरियाणा विधान सभा का मैम्बर गिरफ्तार या डिटेन होता है तो उस सम्बन्ध में इन्टीमे गन स्पीकर के पास आती है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरे पास अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने * * * * हासिल करने के लिए ऐसा किया है। यह ऐक्सपेंज होना चाहिए (गोर)

Mr. Speaker: All right, Hon. Members this matter be now closed. (Interruptions)

चौधरी भजन ला: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने धारा 144 तोड़ने की कोशिश की और पुलिस ने उनको समझा कर बाहर कर दिया। इसके अलावा और कोई किसी प्रकार की बात नहीं हुई। (गोर एवं विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी एक इतू हाउस के सामने आया कि एक सम्मानित सदस्य गिरफ्तार हुए हैं या नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपने बता दिया है कि आपके पास कोई ऐसी इत्तलाह नहीं आई है तो इस बात को बार बार क्यों चैलेंज किया जा रहा है। (गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: No. This is not a challenge.

चौधरी हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, डालिया सीमेंट फ़ैक्टरी, चरख दादरी बंद है। दो तीन दिन से मजदूर लेबर कालोनी में सरकार के हुकम से पानी और बिजली बंद कर दी गयी है। उनके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गयी है। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप इसका नोटिस दे दें। मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा। अगर ऐडमिट होने के काबिल हुआ तो ऐडमिट कर लूंगा। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वांयट आर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि गिरफ्तार करने में और उनको कस्टडी में रखने में क्या अन्तर है ? (गोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि उनको थाने में रखा गया। मैंने तो यह कहा है कि उन्होंने धारा 144 को तोड़ने की कोशिश की थी।

Mr. Speaker: There is no point of order involved in it.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने तो यह कहा है कि उनको गिरफ्तार करने में और कस्टडी में रखने में क्या अन्तर है (गोर)

श्री अध्यक्ष: साहेबान, प्वांयट आफ आर्डर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है कि गिरफ्तार हुआ या उसको पकड़ कर कहीं ले गए। This is a matter of law and I know least about law. If there is any point of order concerning the Rules of the House I can give my ruling on that. फरीदाबाद में चूंकि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ इसलिए मैम्बर साहब ने जो यह पूछा कि What is the difference between arrest and keeping in police custody, has got nothing to do with these Rules and, as such no point of order is involved. मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर कोई

मैम्बर गिरफ्तार होता है तो स्पीकर के पास डायरेक्ट एस0पी0 या एस0एच0ओ0 से सबसे पहले खबर आनी चाहिए। लेकिन मेरे पास इस सम्बन्ध में ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। इससे मैं यही अन्दाजा लगाता हूँ कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर इसमें मुझे कोई गलती मिलेगी तो I will recommend that strictest action may be taken against the concerned police officer.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपसे बड़े अदब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने बिलकुल बजा फरमाया। स्पीकर साहब, आप हमारे इस हाउस के कस्टोडियन हैं। इस हाउस की प्रिविलेज को आपने कायम रखना है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अगर हम में से किसी को पुलिस 4 घंटे या 5 घंटे कस्टडी में रखे तो यह अरैस्ट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: अगर कोई मैम्बर यह समझता हूँ कि उसके साथ किसी किस्म की ज्यादाती हुई है तो he is welcome to make a complaint to me directly or if he is not in a position to write a complaint to me some other member may do so on his behalf. I must get it in writing and I will then get the facts confirmed, get a report and thereafter give a decision, if any, required in the matter.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।
मार्किटिंग बोर्ड के * * * * *

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह भी रिकार्ड नहीं होना चाहिए। हाउस में डैकोरम और कायद से बात होनी चाहिए। (व्यवधान)

Mr. Speaker: It should not be recorded. (Interruptions)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री साहब ने ठीक कहा है कि हाउस में डैकोरम होना चाहिए। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। मान लो हरियाणा के ऐम्पलाईज का डैपुटे इन, फार्मर्ज का डैपुटे इन, अंधों को डैपुटे इन यानी किसी भी वर्ग का डैपुटे इन, अगर हरियाणा से बाहर जाकर, पंजाब की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में या दिल्ली की राजधानी में अनी मांगें मनवाने के लिए ऐजीटे इन करता है और उन पर यहां लाठी चार्ज हो तो क्या ऐसा मामला हरियाणा विधान सभा में नहीं उठाया जा सकता है ? इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं उठा सकते। अगर हरियाणा की टैरिटरी के बाहर ऐक इन होता है, किसी दूसरी ऐडमिनिस्ट्र इन के तहत दूसरी पुलिस द्वारा अगर ऐक इन लिया जाता है, तो उसका हरियाणा विधान सभा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, क्या किसी दूसरी गवर्नमेंट को ऐक इन लेने के लिए हमारी सरकार नहीं कह सकती ? (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: That matter is closed. I have given about half an hour on this point.

ध्यानाकर्षण सूचना—

आमतौर पर राज्य के सूखा क्षेत्रों तथा विशेषतया मेहम के

15 गांवों में तालाबों में पानी सूखने सम्बंधी

श्री अध्यक्ष: मुझे श्री हरस्वरूप बूरा, एम0एल0ए0 की तरफ से, स्टेट के ड्राई एरिया में आम तौर पर और मेहम क्षेत्र के 15 गांवों में विशेषतया जोहड़ों में पानी सूखने के बारे में काल अटैन्शन नोटिस मिला है। मैं इसको मन्जूर करता हूँ। माननीय सदस्य अपना नोटिस पढ़ दें।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याधिक सार्वजनिक महत्व तथा हाल ही में घटित विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेहम क्षेत्र के 15 गांवों में विशेषतया तथा आमतौर पर हरियाणा के खुक क्षेत्रों में जहां नहरें कम हैं या तो तालाब सूख गए हैं या सूखने जा रहे हैं। यद्यपि ग्रीष्म मौसम अभी भुरु भी नहीं हुआ है लेकिन वर्षा न होने के कारण तथा नहरें कम चलने की वजह से तालाबों में पानी नहीं रहा। पशु बीमार होने लग गए हैं तथा मरने भी लगे हैं। स्थिति वहां पर और भी गम्भीर है जहां बहुत खुक क्षेत्र हैं।

मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि तालाबों को भरने के लिए तथा हर दूसरे महीने में एक सप्ताह नहरें, डिस्ट्रीब्यूट्रीज तथा रजबाहे आदि विशेषतया इसी काम के लिये अधिक चलाई जावें ताकि पंजु रखने वालों को बर्बादी से बचाया जा सके।

मैं चाहूंगा कि सरकार इसी सत्र के दौरान अपना वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: क्या सिंचाई तथा बिजली मंत्री इसका अभी जवाब देना चाहेंगे या बाद में ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): मैं इसका परसों जवाब दूंगा।

वाकआउट

डा० मंगल सैन: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० का मामला और हथनी कुंड का मामला विधान सभा में उठाया गया है और ये दोनों ही जगहें हरियाणा की सीमा के बाहर हैं। ये दोनों ही मामले आपने एडमिट किए हैं। दिल्ली में जो लाठी चार्ज हुआ है, वह भी ऐसा ही मामला है, इसको आप क्यों एडमिट नहीं करते ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): ये मामले हरियाणा के बाहर के मामले नहीं हैं, अन्दर के मामले हैं। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वांयट आफ आर्डर।
स्पीकर साहब

श्री अध्यक्ष: डा0 साहब ने जो प्वांयट रेज किया है पहले उसका जवाब देने दीजिए। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन का हरियाणा की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं कि एस0वाई0एल0 और हथनी कुंड के मामले हरियाणा की टैरिटरी के बाहर के मामले हैं। इनको तो यह भी पता नहीं कि हमारी स्टेट की बात है या बाहर की बात हैं (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: क्या हथनी कुंड स्टेट के बाहर नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी समझ के अनुसार एस0वाई0एल0, हथनी कुंड और नाथपा झाकरी प्रोजैक्टस का स्टेट की डिवाइलपमेंट से बहुत नजदीकी सम्बंध है और इनको बाहर का मामला कतई नहीं कहा जा सकता। अगर चन्द आदमी स्टेट के बाहर जाते हैं और उन पर दूसरी स्टेट की पुलिस द्वारा कोई ऐक्ट हो, ला एंड आर्डर की प्रोब्लम हो तो डैफिनेटली इसका स्टेट की डिवाइलपमेंट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, यह बाहर की स्टेट का मामला है।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, अगर आप कहें कि डिवाइलपमेंट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो आ चर्य की बात है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: That is my ruling and no further discussion on it now. Dr. Sahib, please sit down.
(Interruptions)

Shri Baldev Tayal: Speaker, Sir, I want to submit to the Hon'ble Chair only one thing.

Mr. Speaker: About what ?

Shri Baldev Tayal: I am not challenging your ruling but I want to submit that this House is as much concerned ...
(Interruptions)

Mr. Speaker: The discussion on this matter stands closed. I am sorry, I will not entertain any more point on this. My orders are very clear. (Interruptions)

Shri Baldev Tayal: Mr. Speaker, Sir, I may submit for your consideration, if you kindly allow me. Sir, this August House is as much concerned with each and every man of this State/Country as any body else as far as the democratic rights or human rights are concerned. For example

Mr. Speaker: I have heard you. Please sit down, when I am on my legs. I am sorry to say that I entirely disagree with the contention of the hon'ble Member, Shri Baldev Tayal, that this State Assembly is concerned with each and every person of the State of Haryana. If for example, a person goes to London, Kuwait, Singapur, Hong Kong or to say other States like Kerala, West Bengal and commits dacoity, it cannot certainly be, by any stretch of imagination a concern of this Assembly. This matter is finally closed and there will be no further discussion on it.

चौधरी राम लाल वधवा: फिर तो एज ए प्रोटैस्ट हम वाक आउट कर रहे हैं। (जोर)

Shri Baldev Tayal: Sir, I may submit that I was not at all referring to the ruling given by you nor do I want to challenge it. I simply want to make a submission on a general point

Mr. Speaker: If you want my ruling on any point, give ti to me in writing. (Interruptions)

Shri Baldev Tayal: Mr. Speaker kindly *** **

Mr. Speaker: Nothing will be recorded. That chapter has been closed.

(इस समय जनता पार्टी तथा लोकदल के उपस्थित सदस्य वाक आउट कर गए)

वर्ष 1980-81 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, the House will resume general discussion on the Budget for the year 1980-81. Shrimati Sushma Swaraj, who was in possession of the House when it adjourned on the 15th March, 1980, may please resume her speech and try to finish it up in five minutes.

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, चैम्बर की बात वैसे यहां करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको

याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने मुझे 25 मिनटस देने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष: केवल पन्द्रह मिनटस मैंने कहे होंगे। Any how, you had spoken for 20 minutes the other day, which was perhaps the lonigest time taken by any member.

Shrimati Sushama Swaraj: All right, Sir, I will try to cover up the reamaining points quickly.

अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को जब सदन स्थगित हुआ उस में वित्त मंत्री महोदय के बजट में सरकारी कर्मचारियों को जो राहत दी गई है उनके बारे में बोल रही थी। अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में काफी से ज्यादा उन राहतों का जिक्र किया गया है जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान उन कर्मचारियों की तरफ दिलाना चाहूंगी जिनसे आप स्वयं संबंधिता हैं। (विधन) वह हैं विधान सभा के कर्मचारी। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र आपसे इन्ती गुजारि ा करता चाहती हूँ कि जब कभी किसी वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है या सरकार की तरफ से राहत दी जाती है तो ये बेचारे कर्मचारी हमे ा छूट जाते हैं। पता नहीं संख्या में ये इतने कम हैं कि ये अपनी आवाज नहीं उठा सकते। 12-12, 15-15 साल से कई ऐसे कर्मचारी लगे हुए हैं जिनको आज तक कोई सिलैव ान ग्रेड नहीं मिला।

Mr. Speaker: The question regarding the employees of the Vidhan Sabha came up earlier also when I had given an assurance to the House that I will take up the matter with the Government and get it resolved to the best of my ability. therefore, so far as the employees of the Vidhan Sabha Secretariat are concerned, you please leave it to me.

श्रीमती सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी कि दस साल से ऊपर जिन कर्मचारियों की सर्विस हो गई है, उन्हें आप सिलैव इन ग्रेड दिलवाने की कृपा करें। (विधन)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं यह जो योजनाओं का ब्यौरा हमें दिया गया है इसमें से हाउसिंग योजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ पैसों का प्रावधान किया गया है (विधन)

श्री अध्यक्ष: साहेबान, सुशमा स्वराज बोली रही हैं। कृपया कोई इंट्रूप्शन न करें।

श्रीमती सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, 4 करोड़ 63 लाख रुपये इन योजनाओं के तहत रखे गए हैं। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि जब ये योजनाएं बनाते हैं तो किस तरह से प्राथमिकता निर्धारित करते हैं ? अध्यक्ष महोदय इस 4 करोड़ 63 लाख रुपये की ब्रेक अप अगर आप देखें तो इसमें एल0आई0जी0एच0 स्कीम के तहत 15 लाख और 48 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा। अगर इस 15 लाख रुपये की ब्रेक अप हम करें तो ज्यादा से ज्यादा 102 लोगों को ऋण मिल सकता है। इसी

तरह से अगर हम 48 लाख रुपये की ब्रेक अप करें तो ज्यादा 300 लोगों को ऋण मिल सकता है। फिर एम0आई0जी0एच0 स्कीम के तहत 18 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 27500 रुपये तक ऋण देंगे। अगर इसकी भी हम ब्रेक अप करें तो केवल 66 लोगों को ऋण दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि चार तारीख को प्र न काल के दौरान यहां एक सवाल आया था और उसके जवाब में हाउसिंग मिनिस्टर ने बताया था कि कितनी ऐप्लीके ान्ज आज स्टेट में पैडिंग हैं। उन आंकड़ों को अगर हम जोड़ें तो 4387 ऐप्लीके ान्ज हैं जो आज के दिन एल0आई0जी0एच0 और एम0आई0जी0एच0 स्कीम के तहत लोन लेने वालों की पैडिंगे हैं। इसके बरअक्स ऋण दिया गया तो इस बार 366 लोगों का दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इसी रफ्तार से राज्य सरकार चलेगी तो यह कब तक लोगों को आवास की सुविधा जुटा पाएगी। अध्यक्ष महोदय, रोटी, कपड़ा और मकान तीन बुनियादी आवश्यकताएं इन्सान की हैं। रोटी और कपड़े के बाद इन्सान की जरूरत मकान की होती है लेकिन जिस रफ्तार से सरकार चल रही है कि तीन सौ या चार सौ से ज्यादा लोगों को यह ऋण नहीं देती तो कब यह उन 4387 ऐप्लीके ान्ज को निकालेगी और आगे आने वाले ऐप्लीकैन्टस को कब लोन दिया जाएगा, यह मेरी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड का भी यहां जिक्र आया है। 12 लाख रुपये का ऋण इसे दिया गया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पिछले दो वर्षों से इसे राजनीति का अड्डा बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक भी कालोनी हमारे हाउसिंग बोर्ड ने पिछले दो वर्षों में नहीं बनाई है। अध्यक्ष महोदय, आप यह सुन कर हैरान होंगे कि एक तरफ तो बजट में प्रावधान किया गया है कि हाउसिंग बोर्ड को ग्रामीण आवास योजना के लिए 40 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड इस योजना को कार्यानिवत करने वाले चीफ इंजीनियर की पोस्ट को ऐबोलिश कराने जा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह कितनी हैरानी की बात है। आज चारों तरफ हाउसिंग कालोनीज के लिए पैसा जमा है। मेरी अपनी कांस्ट्रक्शंस में साढ़े सोलह लाख रुपया जमा है। चीफ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूँ कि 22 तारीख को जब ये वहां गए थी तो इन्होंने आवासन दिया था कि तीस दिन के अन्दर हाउसिंग कालोनी का काम भुरू करवा देंगे। केवल आठ दिन बाकी हैं लेकिन अभी तक हाउसिंग कालोनी की जमीन का फ़ैसला नहीं हुआ, नींव का पत्थर रखने वाली बात तो दूर रही।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हम जो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं।

श्रीमती सुशमा स्वराज : केवल आठ दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए मैं आपको आपका वायदा याद दिलाना चाहती हूँ।

(घंटी) अध्यक्ष महोदय, बोलना तो बहुत था परन्तु चूंकि समय की कमी है इसलिए आखिर में एक बात कह कर अपना स्थान ले लूंगी। पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्य में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कभी गोहाना में सुजाता काण्ड की आवाज सुनाई पड़ती है और कभी खानपुर में सामूहिक बलात्कार की घटना घटती है। कभी हांसी में मजदूर औरतों पर अत्याचार किए जाते हैं, कभी डाहिना में बाबरिया औरत का कत्ल किया जाता है और कभी रोहतक में एक विधवा के साथ पुलिस के सिपाही द्वारा बलात्कार की नाकाम कोर्त की जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके रिकवैस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने चौधरीवास की घटना की जांच के लिए सदन के आनरेबल मैम्बर्ज की एक समिति गठित की है, उसी तरह से सदन की महिला सदस्यों की समिति गठित करने की कृपा करें क्योंकि महिला केवल महिला के सामने ही अपना दुखड़ा बात सकती है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सुशामा जी ने कई बार इस बात की चर्चा की है। ये कभी गोहाना का जिक्र करती हैं और कभी दूसरे इंसिडेंट का जिक्र करती हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। (विघ्न) लेकिन फिर भी जहां कहीं भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं चाहे छोटा इंसिडेंट हुआ है या बड़ा इंसिडेंट हुआ है। हमने उनके बारे में पूरी कार्यवाही की है। जिस आदमी ने कानून अपने हाथ में लेने

की कोशिश की है या कानून की उल्लंघना की है, उस आदमी को सख्त से सख्त सजा दी गई है। (विधन) इन्होंने रोहतक के सिपाही का जिक्र किया। उस सिपाही को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद चालान किया गया। कोई रियायत नहीं बरती गई। कोई आदमी गलती करता है तो उसके खिलाफ फौरन एक्टान लेते हैं। ये ऐसी बातें बार बार इसलिए कहती हैं कि अखबारों में नाम आ जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर महोदय को पता नहीं क्या हो गया है। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि अखबारों में नाम आ जाये। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड अप करें।

श्रीमती सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सरकार कोई एक्टान नहीं ले रही है। एक्टान तो चौधरीवास के केस में भी हो रहा है। उसके बावजूद भी हमारी सदन की समिति गठित की गई।

चौधरी भजन लाल: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब आपकी ओर से कोई समिति नहीं बनायी गई। मेरे सामने जब एक बात आयी तो चौधरीवास के लिए मैंने कुछ आदमियों की समिति का गठन किया लेकिन आपने यहां हाउस में कोई ऐसी समिति नहीं बनायी। जिस आदमी ने जुल्म किया था फौरन उसे गिरफ्तार किया गया। हो कसता कि असली मुलजिम न

पकड़ा गया हो। मैंने बाकायद नान आफि टायल कमेटी बनायी। वह कमेटी वहां मौके पर जा कर देख कर आयी है।

श्री अध्यक्ष: जहां तक इस बात का संबंध है कि कोई समिति गठित की है या नहीं, मैंने कोई समिति नहीं बनायी। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराज : स्पीकर साहब, अगर आप ट्रेजरी बेंचिज पर बैठी हुई बहिन भान्ति राठी और भाकुन्तला भगवाड़िया को उस कमेटी में रखें तो हमारी तरफ से भी कोई स्त्री उस कमेटी में भामिल करनी चाहिए। (विघ्न) महिलाओं पर अभी खानपुर में केस हुआ, रोहतक में रेप का केस हुआ। इसी प्रकार हांसी के अन्दर रेप का केस हुआ। इस प्रकार से एक ही महिला के साथ ऐसा केस नहीं हुआ कई के साथ हुआ। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेती हूँ।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान बहुत से सदस्य अभी बोलना चाहते हैं। चार दिन से बजट पर बहस चल रही है। हमने पहले 15 मिनट हर मैम्बर के लिए फिक्स किये थे परन्तु सभी मैम्बर 20-25 मिनट ले रहे हैं। आज हम अगर 10 या 15 मिनट देंगे तभी सभी मैम्बर साहेबान बोल पायेंगे। अगर हाउस की सेंस है तो 15 मिनट के बाद जब भी घंटी बजे, मैम्बर साहब अपनी स्पीच खत्म कर दें। ऐसा करने से सभी मैम्बर साहेबान को मौका मिल

जायेगा। अगर उसी तरह से 20-25 मिनट तक बोलते रहे तो सबको मौका नहीं मिलेगा।

आवाजें: 15 मिनट ठीक है।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री सुरेन्द्र सिंह(तो ताम): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1980-81 के बजट पर बहस चल रही है। क्वै चन आवर के बाद आज सदन में चौधरी गंगा राम ने बड़े जोर जोर से चिल्ला कर कहा कि वहां पर यह हो गया (विघ्न) आज सुबह से ही दिल्ली की चर्चा हाउस में चल रही है। एक स्वामी जी तो यहां हाउस में बैठे हैं और दूसरे का पता नहीं कहां कनाट प्लेस में घूम रहे हैं। उस स्वामी जी का हरियाणा से कोई सम्बंध नहीं है क्योंकि उनका पूरा हुलिया ही मालूम नहीं है कि वे कहां के रहने वाले हैं लेकिन फिर भी जब उनके भगवा कपड़ों को देख कर जनता ने वोट दे दिये तो उनको ठीक तरह से रहना चाहिए। फिर भी वे अपनी हरकतों से बाज न आयें और यह सोचते रहें कि भगवा कपड़े पहनने से उन्हें लाइसेंस मिल गया है तो यह गलत बात है।

चौधरी संत कंवर: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैम्बर हाउस में हाजिर नहीं हैं उसके बारे में हाउस में कुछ नहीं कहा जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं तो यही कह रहा था कि स्वामी आदित्यवे । जी तो खदर कपड़े पहनते हैं और वे टैरीलोन के कपड़े पहनते हैं । वह भी थाइलैंड से लाये हुए (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे लोक दल के भाईयों ने बजट पर चर्चा करते हुए किसानों की बहुत सी समस्याओं को हाउस के सामने रखा और उनके समाधान भी बताये । मैं भी किसानों की समस्यायें हाउस में रखना चाहूंगा । जब यहां हरियाणा में लोक दल की सरकार थी तो यहां पर कोई भी काम नहीं हो सका । अगर हमारी सरकार खाद और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाये, हथनी कुंड का बेराज बनाए और लोक दल के भाई गांवों में किसी प्रकार की मारधाड़ आदि न कराये तो हरियाणा की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और प्रदेश उन्नति के पथ पर जा सकता है । इसी प्रकार से मारपीट चलती रहे तो हम अपने आपको मजबूत नहीं कर सकते । (विघ्न)

हमारी कांग्रेस सरकार का तीस साल का राज रेल की तरह से स्मूथ चलता रहा और इन्होंने तो अढ़ाई साल के अन्दर ही पता नहीं क्या कर दिया ? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इनको राज चलाना नहीं आया और न ही जनता के काम करने आये । जब चौधरी देवी लाल की यहां सरकार थी तो मैं एक ही बात करता था (विघ्न) वे मेरे ताऊ हैं । मैं उनकी पहले भी इज्जत करता था और आज भी करता हूं । मैं उनसे एक ही बात कहा करता था, दलाल साहब और अन्य साथियों को भी भायद याद होगा कि मैं

क्या कहता था ? अगर इन लोगों को याद न हो तो मैं बता देता हूँ। जब चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे तो मैंने कहा था कि यह कुर्सी आदमी को फैंक फैंक कर मारती है। यह आदमी की ताकत और जोर पर डिपैन्ड करता है कि वह उस कुर्सी को सम्भाले रखें। वे सच्चे मन से राज चलाना चाहते थे लेकिन जो उनके साथी हैं उन्होंने राज नहीं चलने दिया। बड़ी अजीब कहानी है। 76 एम0एल0एज0 का बहुमत हो और फिर राज नहीं चल सका, इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है ? ऐसे ही राज को फैंक कर चे गये, सम्भाला नहीं गया लेकिन अब ये याद रखें कि इनको राज नहीं मिलेगा। इनको जनता ने देख लिया है। (विघ्न) अब मैं किसानों की तरफ ही आ रहा हूँ। उनके बारे में मेरे विरोधी पार्टी के भाई भी काफी बोले हैं। लेकिन पिछले अढ़ाई सालों में जनता सरकार ने हरियाणा प्रान्त कि किसानों की समस्याओं को इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा कर रख दिया है कि उन पर एकदम से कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल काम है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज पानी की बड़ी भारी समस्या है। सन् 1966 में जब हरियाणा का जन्म हुआ तो उस समय हरियाणा एक डैफिसिट स्टेट थी। हरियाणा को उस समय जितने अनाज की जरूरत होती थी वह भी पूरी नहीं हो पाती थी। 1967-68 के बाद लगभग 5-6 साल के अन्दर ही हरियाणा प्रान्त की सरकार ने किसानों के लिए तरक्की के बहुत साधन जुटाये उनके लिए ट्यूबवैल लगाये गए, नहरों के जरिए उनके लिए पानी उपलब्ध करवाया गया और अन्डरग्राउंड पानी को निकाल कर 3125 क्यूसिक से भी ज्यादा

पानी का प्रबन्ध किया गया। लैण्ड लैवलिंग का भी बहुत काम हुआ। इसके साथ ही साथ यह भी पूरी पूरी कोर्णा की गई कि किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध हों ताकि पैदावार बढ़े।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज की सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या रावी-ब्यास वाटर की है। मैं इसके बारे में खुद सोच रहा था कि इस समस्या का हल करना हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे भी बड़ा सीरियस मसला और भी है। हथनी कुण्ड बैरज का मसला भी बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं पिछले दिनों अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए तो यह था कि वर्ष 1954 और 1974 में जो ऐग्रीमेंट हरियाणा सरकार से हुआ था उसको निभाती। यह तभी हो सकता है जब दोनों सरकारों की अन्डरस्टैंडिंग हो, अच्छा आपस में तालमेल हो। 1954 में यह समझौता हुआ था कि हथनी कुण्ड से 1/3 भाग पानी उत्तर प्रदेश को लेगी और 2/3 भाग हरियाणा सरकार को मिलेगा। इसके बाद वर्ष 1974 में हरियाणा प्रान्त और उत्तर प्रदेश का एक और ऐग्रीमेंट हुआ था कि हथनी कुण्ड बैरज को बनाने का काम तो अकेली हरियाणा सरकार करेगी लेकिन ओखला का कार्य उत्तर प्रदेश करेगी। इसी प्रकार से पानी के डिवीजन का भी फैसला हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा सरकार को इस बात को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। यदि हथनी कुण्ड बैरज का काम रूक गया तो आज हमें जितना

पानी वैस्टर्न जमुना कैनल से मिल रहा है उतना पानी भी नहीं मिलेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत में कुछ खराबी नजर आती है। पहले तो केवल कन्स्ट्रक्शन पर ही झगड़ा था। हरियाणा सरकार तो यह चाहती थी कि इस बैरज को 70-75 मीटर ऊपर बनाया जाये लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसको 100-150 मीटर नीचे बनाना चाहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार धमकी दे रही है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस हथनी कुण्ड बैरज के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करे। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या चाहती है ? हम अपना डैम जहां चाहे मर्जी में आये बनाये। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हरियाणा के लोगों को जमुना कैनल से पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के गुड़गांवा कैनल की एक समस्या है। गुड़गांव कैनल के झगड़े के संबंध में हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता है और उत्तर प्रदेश के लोगों को हरियाणा में आना पड़ता है। इस तरह दोनों ओर के लोगों को काफी कठिनाई होती है। डिप्टी स्पीकर साहब अढ़ाई साल की अवधि के दौरान चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने हरियाणा की बहुत बुरी हालत कर दी।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त 1967-68 में महेन्द्रगढ़, झझर, भिवानी और हिसार के रेतीले इलाके के लिए

लगभग 11 लाख एकड़ जमीन को पानी देने का प्रबन्ध करने के लिए बहुत सा काम किया था। जिस इलाके में नहरों के जरिए पानी नहीं पहुंचता था वहां पर लिफ्ट इरीगे इन स्कीम चालू की गई। वे बहुत कामयाब स्कीमें रही हैं। हरियाणा के अन्दर जुई कैनाल बहुत कामयाब रही है लेकिन खेद इस बात का है कि वहां पर जो अफसरान हैं वह इस बात पर कतई गौर नहीं करते हैं। कि वहां कितनी मात्रा में जमीन की सिंचाई होनी चाहिए। भायद इरीगे इन मिनिस्टर साहब को भी इस बात का पता नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इरीगे इन मिनिस्टर साहब से इस बात का जवाब चाहूंगा कि लिफ्ट इरीगे इन स्कीम पर खर्चा कितना होता है और उनको कितना पानी दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे आता है कि मिनिस्टर साहब मेरी इस बात को नोट करेंगे। वे खर्चे को वर्क आउट करेंगे और इस बात का भी जवाब देंगे कि लिफ्ट इरीगे इन स्कीम पर कितना खर्च होता है और कितनी रिटर्न आती है और सरकार इसके बारे में अपनी तरफ से क्या कार्यवाही कर रही है ?

डिप्टी स्पीकर साहब, आप घंटी पर हाथ रख रहे हैं परन्तु मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह जो लिफ्ट इरीगे इन स्कीम चालू की गई थी यह इसलिए चालू की गई थी ताकि जहां जमीन ऊंची है वहां पर पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि लैंड लैवलिंग का काम कोई दूसरा डिपार्टमेंट करता है। बिजली का काम कोई दूसरा महकमा करता है और सिंचाई का

काम कोई और डिपार्टमेंट करता है। इसलिए मैं आपके जरिए सिंचाई तथा बिजली मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो मेन कैनल के साथ साथ माईनर के साथ साथ या सब माईनर के साथ साथ जमीन ऊंची है उसकी लैंड लैवलिंग सम्बन्धित महकमे से जल्द से जल्द करवाई जाये ताकि उस जमीन को भी ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके। यदि इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाता है तो जमीन को पानी तो ज्यादा मिलेगा ही , साथ ही साथ किसानों की भी पैदावारी बढ़ेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब किसानों की बात बात आती है तो मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि किसानों के बारे में इस बजट स्पीच में कोई चर्चा तक नहीं की गई और न ही गवर्नर ऐड्रेस में किसानों के भले के लिए कोई बात सोची गई। हकीकत यह है कि हरियाणा प्रान्त अपने किसानों के लिए अच्छे बीजों का भी प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है।

16.00 बजे

आज हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छी किस्म के बीज उतनी मात्रा में तैयार नहीं कर सकती जितने की तमाम हरियाणा को चाहिए। इसलिये मैं हरियाणा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अच्छे बीजों का प्रबन्ध करे। आज तक 1966 से लेकर जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम किये गये, चाहे वह सड़कों के थे, नहरों के थे, या वाटर वर्क्स के थे, उनके लिये जितनी

जमनी किसानों की एक्वायर की गई है, उसको मुआवजा आज तक भी कई किसानों को नहीं दिया गया है। इसके बारे में हमारा एक डैपुटे इन भी चीफ सैक्रेटरी साहब से मिला था। चीफ सैक्रेटरी साहन हमें यह बताया कि वहां पर यानी एल0ए0ओ0 की पोस्ट पर कोई भी अफसर काम करके खुद नहीं है। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि चाहे वह आई0ए0एस0 अफसर लगाये, किसी एच0सी0एस0 अफसर को लगाये या किसी दूसरे तरीके से यह काम करवाये लेकिन उसको किसानों की जमीन का मुआवजा जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी देना चाहिए। सरकार सुओ मोटो तो यह काम करती नहीं है। इसलिये मेरी गुजारि है यही है कि वह इलाके महेन्द्रगढ़ जैसे जहां पर अकाल पड़ा हुआ है। बिजली की भी कमी है और पानी की भी कमी है वहां पर चारे की भी कमी है वहां के लोगों के लिये खासतौर पर इस बात का प्रबन्ध किया जाये कि उनको जमीन के मुआवजे के पैसे जल्दपी से जल्दी मिल सकें। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, जितनी नहरें बनाई गई थीं या लिफ्ट इरीगे इन कैनालज बनाई गयीं थीं उनके नाम भी बदल दिए गए हैं। जवाहर लाल नेहरू कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल, बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कैनाल वगैरा जितनी भी नहरे हैं, उनके पुराने नाम रख दिये जायें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ राठी साहब जरा गौर से सुन लें।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। अभी मेरे दोस्त ने किसानों की उपलब्धि की काफी बात की है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: जरा मेरी बात तो पूरी सुन लें। यह जो जुई कैनल ताजेवाला से बनाई गयी है मैं भी वहां पर गया था अफसर भी मेरे साथ थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह: यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। मैंने आपके ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं लगाया है।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: जरा धीरज रखें उस वक्त समस्या यह थी कि वहां पर कन्सौलीडे ान तो हुआ ही नहीं था। खालों को किसान एक दूसरे के खेत में से ले जाने नहीं देते थे। इसलिये सारे का सारा पानी खराब हुआ। कन्सौलीडे ान तो आपके पिताजी के राज में नहीं करवायी गयी। परन्तु अपने आने के 15 दिन अंदर वहां पर स्टाफ भेजा और कन्सौलीडै ान करवायी। यह आज किसान के हित की बात करते हैं
(व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: मलिक साहब, आप बैठिए। यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: इन्होंने बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कैनाल का नाम बदल दिया। मेरा कहना यह है कि इनके ओरीजनल जो भी नाम हैं, वे रखे जाने चाहिए। उसी तरह से एक चक्रवती लेक थी, उसका नाम भी अब बदल दिया गया है उसे भी दोबारा बदल कर चक्रवर्ती लेक किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप वाइन्ड अप कीजिये

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं वाइन्ड अप ही कर रहा हूँ। आजकल अनएम्पलायमेंट बहुत ज्यादा है और अनएम्पलायड लोगों की लिस्ट सबके पास है। कोई भी सदस्य यह मानने के लिए मेरे विचार से तैयार नहीं होगा कि एनरोलमेंट ठीक तरीके से हो रही है। उसमें भी कोई कायदा कानून नहीं चल रहा है कि यहां से ही भर्ती होनी चाहिए। आपको पता है कि बहुत से आदमी हमारे यहां बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रान्त में आज भी आदमी एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बगैर, करीब करीब सभी महकमों में लगाये जो रहे हैं। कोई राजस्थान के लगाए हुए हैं तो कोई उत्तर प्रदेश से भी ले लिये जाते हैं। (गेम भोम की आवाजें) वे आदमी न तो एम्पलायमेंट एक्सचेंज के थ्रू आते हैं और न ही बाकायदा इन्टरव्यू के थ्रू आते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह तरीका ठीक नहीं है। इसको बन्द किया जाना चाहिए।
(व्यवधान व भाोर)

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मेरी तो इतनी से गुजारि । है कि आनरेवल मैम्बर इतना अहम मसला यहां पर उठा रहे हैं लेकिन मुझे यह प्वायंट आउट करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि ज्यादातर मिनिस्टर्ज यहां हाउस से एबसैंट हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यहां पर बैठा हुआ हूं और नोट भी कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं बैंकों के चुनाव की बात के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। ... (व्यवधान व भाोर) ये जो बैंको के चुनाव हुए हैं इसमें एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी है। मान लिया किसी बैंक के 10 डायरैक्टर्ज का चुनाव हुआ और 7 डायरैक्टर्ज एक तरफ हैं और तीन डायरैक्टर्ज दूसरी तरफ हैं तो तीन डायरैक्टर्ज ऐसी कोि । । करेंगे और ऐसा अरेजमेंट करेंगे कि तमाम आफिसर्ज का वोट भी ले लिया जाये। यह बात जमहूरियत के खिलाु हैं (अपोजी ।न की तरफ से थम्पिंग) आप लोगों ने यह प्रथा चलायी थी। मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार को ऐसी कमिटमेंट करनी चाहिए कि वह इस पालिसी को ठीक नहीं समझती और इसे आगे के लिए बन्द करेगी। मै। यह चाहूंगा कि इस पालिसी को बदला जाये कि सरकारी अफसरोसं का चेयरमैन के चुनाव में दखल हो, मैं इस बात को गलत मानता हूं। इसके

अलावा हरियाणा में जितनी भी कारपोरेट एंज हैं, जब मेरे भाई बीरेन्द्र सिंह जी तकरीर कर रहे थे तो उनके बारे में मुझे भी कुछ आंकड़े पाने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने यह बताया है कि कोई भी कारपोरोन फायदे में नहीं चल रही है। करोड़ों रुपया उनमें खर्च हुआ है। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: आप वाइन्ड अप कीजिये। (व्यवधान व भाोर) 28 मैम्बर आज तक बोले हैं, 16 अपोजी एन के और 12 रूलिंग पार्टी के बोले हैं। (व्यवधान) टाईम भी अपोजी एन ने ज्यादा लिया है। अभी कल का टाईम पड़ा है सबको टाईम मिल जायेगा। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब जाते समय टाईम फिक्स करके गए थे और यह कह कर गए हैं कि अब के बाद टाईम फिक्सड हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये सरकार से एक बात और बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर ट्रैक्टर पर एक प्रति एत सेल्ज टैक्स है जबकि हरियाणा के अंदर 6 फीसदी है। जिन भाईयों को ट्रैक्टर की जरूरत होती है वे आज कल पंजाब से लाते हैं क्योंकि यहां पर 6 फीसदी सेल्ज टैक्स होने से ट्रैक्टर महंगा मिलता है। आपको यह तो पता है कि हरियाणा के किसानों को भी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। वे

ट्रैक्टर लैने के लिये पंजाब की मलोट मंडी जाते हैं वाह पर 1000 ट्रैक्टर एक महीने में बिक जाते हैं। क्योंकि राजस्थान और हरियाणा वाले वहीं से ट्रैक्टर लेकर आते हैं। इस तरह से वहां पर सेल्ज टैक्स की रिकवरी भी ज्यादा होती है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह ट्रैक्टर पर सेल्ज टैक्स को घटा कर 6 फीसदी की बजाये 1 फीसदी कर दे। मेरे विरोधी भाई ने एक बहुत अच्छी बात की। दादरी सीमेंट फ़ैक्टरी की करीब एक या दो साल से बहुत खसता हालत है। खासतौर पर जनता सरकार के आने के बाद से। डिप्टी स्पीकर साहब, तीन दिन हुए उस फ़ैक्टरी की बिजली भी कट गयी और पानी भी बंद कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अब समाप्त कीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह: बहुत अच्छा जी। मैं आपके जरिये सरकार से यह गुजारि । करूंगा कि वह इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप करे। (विघ्न) इसे एक सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर करके टेक ओवर करे ताकि वहां पर मजदूर को रोजगार मिले। धन्यवाद।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है इसके लिए मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बजट हाउस के सामने आया है इसमें कोई टैक्स नहीं लागया गया है यह ठीक बात है लेकिन आगे टैक्स लगाने का डर मौजद है।

डिप्टी स्पकीर साहब, इस बजट के अंदर छोटे मोटग व्यापारियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। यह अच्छी बात है लेकिन अगर किसानों को भी कुछ रियायतें यह सरकार दे देती तो और भी अच्छी बात होती। इस बजट में कहा गया है कि हम आबपा की के लिए ज्यादा पानी देंगे और उसका प्रबन्ध यह सरकार जल्दी ही करेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने इलाके में कुछ जगहें ऐसी बता सकता हूं जहां पर मीठा पानी है। वे जगहें हैं इसमालपुर, बाडसा, लोयदादरी और सोधी। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इन जगहों पर एम0आई0टी0सी0 ट्यूबवैल्ज लगा दें तो यहां से काफी गांवों को मीठा पानी दिया जा सकता है।

चौधरी मेहर सिंह राठी: वहां पर पानी की स्कीम मंजूर कर दी है और आज ही चिट्ठी भेज दी है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई राठी साहब कह रहे हैं कि चिट्ठी भेज दी है और वहां पर स्कीम मंजूर कर दी है। यह बहुत अच्छी बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक बिजली का ताल्लुक है मैं मानता हूं कि बिजली की कमी है लेकिन इस बारे में मेरी रिक्वैस्ट है कि बिजली का डिस्ट्रिब्यूशन इस ढंग से किया जाए कि किसानों को दिन में बिजली दी जाए और इंडस्ट्रीज की रात को बिजली दी जाए। अगर किसानों को रात को बिजली दी जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रात में

सर्दी होती है, सांप बिच्छू वगैरह का डर रहता है। रात में खाल टूट जाते हैं। इंडस्ट्री वाले रात को काम करवा सकते हैं क्योंकि उन्हें रात में काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। किसानों को काफी दिक्कत आती है। रात को खाल टूट जाने से पानी काफी जाया जो जाता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसानों को दिन में ही बिजली दी जानी चाहिए (व्यवधान) राठी साहब कह रहे हैं कि दिन में बिजली दे देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, कह तो यह रहे हैं कि लेकिन हकीकत यह है कि पिछले हफ्ते जब मैं घर पर था तो भाम को रोटी खाने के टाइम पर रोज बिजली चली जाती थी। इनको चाहिए कि कम से कम भाम को राती के टाइम पर तो बिजली देनी ही चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में एक याकुपुर गांव हैं वहां पर इन्होंने गुड़गांव से बिजली दी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसका गुड़गांव से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक झज्जर से है। तहसील झज्जर है, बी0डी0ओ0 का दफ्तर झज्जर में है, मार्किट कमेटी झज्जर है लेकिन इन्होंने बिजली का कनेक्शन गुड़गांव से दे दिया है। मैंने इनको यह जबानी भी कहा था और आज यहां हाउस में भी कह रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हकीकत है कि इस गांव का गुड़गांव से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बजट के अंदर किसानों को बहुत बड़ी रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहा गया है लेकिन वास्तव में बात यह है कि अगर किसान को अपने खाल की मरम्मत के लिए कट्टा सीमेंट चाहिए तो वह भी नहीं मिलता। रोज

किसान को बी0डी0ओ0 और तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं सिर्फ एक कट्टा सीमेंट के लिए। लेकिन अगर किसी सरमायेदार को अपनी कोठी के फर्श को ठीक कराने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए सीमेंट चाहिए तो उसको जितना सीमेंट चाहिए वह मिल जाएगा लेकिन किसान को अपने ट्यबवैल की मरम्मत या खाल की मरम्मत करनी हो तो उसको कह दिया जाता है कि सीमेंट स्टोक में नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब आज डीजल की हालत भी बहुत खराब है। आज किसान की जवान लड़कियां, लड़के और बहुएं डीजल के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। और उनको डीजल नहीं मिलता। उन बेचारों को ब्लैक में डीजल खरीदना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर किसान को डीजल भी ब्लैक में लेना पड़े तो उसका गुजारा कैसे होगा ? दूसरी तरफ हमारी सरकार पैदावार बढ़ाने की बात करती है। मुझे समझ नहीं आता कि किसान को पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक चीजें नहीं मिलती और यह सरकार पैदावार बढ़ाने की बात करती है। ये किस तरह से पैदावार बढ़ाएंगे ? इनको गांवों के किसान और मजदूरों का कोई ख्याल नहीं है। स्वामी जी जैसे मोड़े को कभी कहीं घुमाने ले जाते हैं और दूसरी तरफ किसानों को डीजल नहीं मिलता। मिट्टी का तेल नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता और सीमेंट नहीं मिलता। डिप्टी स्पीकर साहब, आज तो हालत यह है कि राठी साहब, जब भी कोई पोलिटिकल तबदीली होती है तो अपना भेष बदल लेते हैं अपना धर्म बदल लेते हैं और सब से ज्यादा हंसते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी ने कहा कि इज्जत

तो आनी जानी चीज है आदमी ढीठ होना चाहिए (व्यवधान) वजीर तो मेरे 'भाई बन रहे हैं' लेकिन ऐसी वजारत को तो मैं लागत देता हूँ। आज इन लोगों के ऊपर गांव का बच्चा बच्चा हंस रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बजट पर ही बोलें (व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, खाद के बारे में मैं अपनी बात एक मिनट में बता देता हूँ। जिस मौसम में खाद की जरूरत होती है उस मौसम में तो खाद मिलती नहीं है और कर्जा की भावना में जबरदस्ती खाद दी जाती है। अगर किसी किसान को आठ सौ रुपए का कर्जा दिया जाता है तो पांच सौ रुपया कर्जा दे दिया जाता है और तीन सौ रुपए का खाद दे दिया जाता है। उस किसान को उस खाद की जरूरत नहीं होती है उस किसान को दस रुपए सस्ते दाम पर वह खाद का कटटा बाजार में दुकानदार को देना पड़ता है (व्यवधान) मैं यही तो कह रहा हूँ। आप लोग कुछ तो डरो * * * * * आप लोग चौधरी देवी लाल के वक्त में भी मिनिस्टर थे, चौधरी भजन लाल के वक्त में भी मिनिस्टर हो और कोई मिनिस्टरी आ जाएगी तब भी आप ही लोग मिनिस्ट्र होंगे। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए डिप्टी स्पीकर साहब, ये लोग हंस रहे हैं। आप लोग इन बेकारा की बातों को छोड़ो। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब मैं खाद की बाबत कह रहा था कि किसानों को जब जरूरत होती है तो खाद

मिलता नहीं और जब जरूरत नहीं होती तो उसको जबरदस्ती खाद दिया जाता है (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग अपना दामन पाक कर लो। गांव के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन इलैक्ट्रिक लाइन डिकलेयर हो जाएंगे उस दिन लोग आपके पीछे रहेंगे और आप लोग छुपत रहोगे। आपको चाहिए तो यह था कि जो गलत कानूनी है जो चीज किसान के हित में नहीं है, जो कमियाँ हैं, उनमें सरकार रिलीफ दे। जैसे किसान को सीमेंट नहीं मिलती। आपको चाहिए कि उसकी यह तकलीफ दूर करें लेकिन आपका इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज अगर राठी साहब को फैक्टरी बनानी पड़े तो पांच सौ कट्टे सीमेंट के पहुंच जाएंगे लेकिन अगर उदय सिंह को अपने खाली मरम्मत के लिए अपने ट्यूबवैल की मरम्मत के लिए एक कट्टा सीमेंट की जरूरत हो तो उसको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ अच्छा काम कर जाओ। सबको इस दुनिया से एक न एक दिन जाना है। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी छोटू राम ने गांव के किसान के लिए, मजदूर के लिए कुछ कानून बनाए और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक उनको याद किया जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन झगड़ों को छोड़ कर जनता की भलाई, गांव के किसान और मजदूर की भलाई के काम करना सीखो। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं महकमा जंगलात के बारे में कहना चाहता हूँ। राठी साहब, के पास यह महकमा है। डिप्टी स्पीकर साहब, झज्जर सब डिविजन में सड़कों पर इन्होंने कीकर के पेड़ लगा दिए हैं जब कि वहां

भी काम के पेड़, सफेदे के पेड़ लग सकते थे क्योंकि ये छायेदार पेड़ हैं। कीकीर कोई छायादार पेड़ नहीं है, उससे तो कांटे वगैरह ही फैलते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एक बहुत जरूरी महकमे के बारे में कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फैक्ट्रियों की बावत भी कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि हम देहातों में फैक्ट्रियां लगाने जा रहे हैं। जब हम फैक्ट्रियों के बारे में यहां पर सरकार की तरफ से सुनते हैं। तो हमारा सिर भार्म से झुक जाता है। जितने भी हमारे नवयुवक देहातों में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उनको कोई रा-मैटीरियल नहीं मिल रहा है। कोई प्लासटिक की फैक्टरी लगा रहा है, कोई साबुन की फैक्टरी लगा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि एक नवयुवक ने साबुन की फैक्टरी लगाई लेकिन वह बेचारा 9 रुपये किलो के हिसाब से रा-मैटीरियल रोहतक से ले जाकर अपना काम चलाता है और उसको बीच में से कुछ नहीं मिलता और न इन बेचारों का माल किसी मंडी में ही लिया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टरी लगाने के लिये सरकार की तरफ से किसी भी नौजवान को किसी प्रकार की सबसिडी नहीं दी जा रही है। बिरला की फैक्ट्रियां है, उनको 60-70 लाख रुपये की सबसिडी दी जा रही है और वे अरबों रुपया सरकार से कमा रहे हैं लेकिन एक गरीब किसान के बेटे को जो कि छोटी छोटी फैक्ट्रियां देहातो में

लगाकर बैठे हैं, उनको सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सबसिडी व सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं कितने अनर्थ की बात है ? जो भाई आता है, मिनिस्टर बनता है और हार डलवा कर चल देता है, इतना कर देता है कि भाई गले में हार डाल दो और फिर जब चुनाव आता है तो कह देते हैं कि इलैक्शन के लिये पैसा दो लेकिन इस प्रकार की अगर कोई किसान का बेटा सहायता मांग लेता है तो सरकार की तरफ से साफ जवाब मिला जाता है। इस तरह से इन मिनिस्टरों ने लूट मचा रखी है। यहां पर ये सामने बैठने वाले भाई फिर चौधरी देवी लाल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उस जैसा तो इस हरियाणा में कोई ही पैदा होगा। आप सब उसकी वजारत में वजीर रहे हैं। (व्यवधान) * *

* * * * *

(गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आपका समय हो गया, अब आप खत्म कीजिये।

चौधरी उदय सिंह दलाल: बस डिप्टी स्पीकर साहब, एक दो बातें कहकर मैं खत्म करता हूं। मैं यहां पर सेल्ज टैक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तायल साहब ने मेरे से वायदा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी लेकिन मैं आपकी मारफत इस हाउस को और राठी साहब को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने एक केस के बारे में सरकार को पहले ही लिखा है कि एक चने का ट्रक दिल्ली ले जाया गया और उसमें 600 रुपये

की सेल्ज टैक्स की चोरी हुई हैं। इसके बारे में एक विजीलेंस के अधिकारी ने तहकीकात की है और रिपोर्ट दी है कि हरियाणा स्टेट का ऐसी चोरियों के कारण लगभग 1 लाख 11 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक ही ट्रक इस टाइम पर बादली से गुजरा और उस ट्रक की कोई वहां पर चुंगी चौकी पर एन्टरी नहीं हुई। (गोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ऐसे केसिज पर पैनल्टी लगाई जाए तो कई लाख रुपये की सेल्ज टैक्स की चोरी का पता लग सकता है। वे केस इसलिये दब गये क्योंकि वे आदमी राठी साहब के साथी थे, राठी साहब के दोस्त हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यह सेल्ज टैक्स की चोरी वाली बात झूठी हो तो मैं एम0एल0ए0 की सीट छोड़ने के लिये तैयार हूँ। या फिर ये छोड़ दें। (गोर एवं व्यवधान) (घांटी) मैं कई बार यह बात इन लोगों के नोटिस में ला चुका हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इन्होंने कभी मेरे नोटिस में यह बात नहीं लायी। (गोर एवं व्यवधान)

आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ठीक है। सेल्ज टैक्स की चोरी हुई है। (गोर)

चौधरी मेहर सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहब, ये सिद्ध कर दें। मेरे नोटिस में यह कभी नहीं लाए। (विघ्न) कौन दोस्त, किसका दोस्त, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दालाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर * * * * *

चौधरी मेहर सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहब, हमें इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि कौन आदमी है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राठी साहब, आप तारीफ रखिये (गोर) दालाल साहब, आप वाइंड अप करें। आपका समय हो चुका है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दालाल: डिप्टी स्पीकर साहब,

* * * * *

* * * * *

श्री उपाध्यक्ष: यह जो कह रहे हैं, रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं व्यवधान) श्री भगमल जी, आप बोलिये। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहब, यह गलत इलजाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। यह नाकाबले बरदात है, पहले भी कई गलत इलजाम लगाते रहे हैं, मेरे सामने इन्होंने कभी यह

बात नहीं कहीं (गोर एवं व्यवधान) * * * * *

* * * * *

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये मिनिस्टर आपके आर्डर से बोल रहे हैं या यूं ही हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: ये ऐसे ही किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उस * * * * *

चौधरी मेहर सिंह राठी: उस आदमी ने इसकी इलैक्शन में मुखलिफत की होगी, तभी इसको उससे चिड़ है। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: साहेबान, आप बैठिये, मैंने भागमल जी को बोलने के लिये कह दिया है।

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बोलते हुए यह चेलैन्ज दिया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और दूसरी तरफ चौधरी उदय सिंह दलाल जी ने कुछ सच्ची बातें यहां हाउस के सासमने रखीं और कहा कि अगर यह बात झूठी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो राठी साहब दे दें। तो मेरती आप से रिकवैस्ट है कि यह मामला बड़ा सीरियस है

पहले भी जब इस तरह की बात कभी हाउस के सामने आती थी, तो मामले प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिये जाते रहे हैं। इसलिये यह मामला भी आप प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दें ताकि सच्चाई सामने आ जाए। (व्यवधान एव भाोर)

Mr. Deputy Speaker: This is not on the record of the Assembly. (Interruptions) You please give it to me in writing, if you so like. I will then examine it.

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ** * * * *

श्री उपाध्यक्ष: यह जो कुछ कह रहे हैं, यह रिकार्ड न किया जाए। भागमल जी आप बोलें।

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह मामला बड़ी सीरियस है और आप फरमा रहे हैं कि यह रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, वे मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री जगननाथ): डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें सीरियस क्या बात है ? मिनिस्टर साहब ने तो केवल इतना ही कहा है कि चौधरी उदय सिंह दलाल ने हमारे नोटिसा में कभी कोई ऐसा मामला नहीं लाया।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी भागमल जी आप बोलें। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भागमल (सढौरा— अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो बजट वित्त मंत्री श्री बलवन्त राय तायल ने इस हाउस में पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट स्पीच में सरकार की तरफ से कुछ आवासन भी दिये गये हैं कि बैकवर्ड क्लासिज भाडयूल्ड कास्टस और भाडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को रियायतें दी हैं और उनके इंस्ट्रूस्ट को वाच किया जाएगा। मैं आपके द्वारा इस हाउस में यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पिछले 30 सालों से बड़े बड़े नारे लगाये हैं, आंसू बहाये हैं कि गरीब हरिजनों और बैकवर्ड लोगों के लिए हर तरह का संरक्षण दिया जाएगा। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है और अब अगले दस साल और इसी कमी को दूर करने के लिये मांग लिये गये हैं। यह तो डिप्टी स्पीकर साहब, गरीब हरिजनों के साथ धोखा है, यून ही लोगों को बहकाया जा रहा है। आज यह हरियाणा का बजट भी यहां पर प्रस्तुत है। इसमें भी कोई ऐसी स्कीम काई प्रावधान हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए नहीं है, जिससे कि उन्हें ऊपर उठाया जा सके और वे बेचारे सुख का सांस ले सकें। डायरेक्टर वैलफेयर आफ भाडयूल्ड कास्टस एंड बैकवर्ड क्लासिज की तरफ से एक लेटर जो मुझे मिला है, उसका नम्बर 23986 दिनांक 10-12-79 है। उसमें

हरिजनों के संरक्षण के बारे में बताया है कि क्लास वन में 3.4, क्लास टू में 3.9 और क्लास थ्री में 7.5 परसेंट संरक्षण है जबकि होना चाहिए 20 परसेंट। डिप्टी स्पीकर साहब अफसोस की बात यह है कि 30 साल पिछले गुजर गये हैं और 10 साल और इनको हरिजनों की भलाई के लिये मिल रहे हैं लेकिन यह संरक्षण कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा और चाहूंगा कि वह हाउस में एक वायदा दे कि कम से कम इस साल तो जरूर इस संरक्षण को पूरा किया जाएगा। अब तक इनको जो संरक्षण दिया गया है वह तो केवल दिखाने को है। बैकवर्ड क्लासिज के बारे में वैसे तो बहुत बातें हो रही हैं कि उनके लिये हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको रिजर्वे इन का भी पूरा कोटा दे दिया जाए तो उनकी हालत सुधार सकती है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी राम कि इन पदासीन हुए) इसलिये मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले पर ठंडे दिल से सोचे। पीछे मेरे एक भाई ने बैकवर्ड कम्युनिटी के बारे में एक रैजोल्यू इन दिया था। ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से भी और इस तरफ से भी उस रैजोल्यू इन पर अच्छी अच्छी बातें कही गई थी लेकिन जब उस रैजोल्यू इन पर वोटिंग की मांग की गई तो ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से ऐसा रवैया अख्तियार किया गया कि उस पर वोटिंग नहीं होनी चाहिये। इसलिये जो उनके आंस बहा रहे हैं वे सिर्फ दिखावे के हैं असल में उनके साथ इनकी सिम्पथी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से रिकवैस्ट करूंगा कि जिस तरीके से वह हरिजनों का ध्यान रखती है उसी

तरीके से वह बैकवर्ड क्लासिज का भी ध्यान रखें। इसके बाद मैं एक बात के लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि उसने भाडयूल्ड कास्टस के आठवीं क्लास के ऊपर के लड़कों का स्कालरशिप बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लड़के और लड़कियाँ भी हैं जो कम्पीटीशन में आकर स्कालरशिप लेते हैं उनका स्कालरशिप अभी नहीं बढ़ाया गया है। उनको इस समय बहुत थोड़ा स्कालरशिप मिल रहा है। अगर उनको इतना थोड़ा स्कालरशिप देना है तो उनको कम्पीटीशन में बैठने का क्या फायदा? इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज को यह सुविधा दी गई है वहाँ उन लड़कों और लड़कियों को भी यह सुविधा दी जाए। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा हाउस में एक बात और रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पीओडब्ल्यूडीओ और इरीगेन डिपार्टमेंट्स में काफी वर्कचाजर्ड ऐम्पलाइज है। वे लोग बीस बीस साल से लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उनको रैगुलर नहीं किया गया। रैगुलर न करने के कारण उनको जब भी चाहो हटाया जा सकता है। सरकार ने पे-कमीशन बिठा कर बाकी सब कर्मचारियों को फायदा दिया है लेकिन चूँकि ये वर्कचाजर्ड कर्मचारी हैं इसलिए यह फायदा उनको होने वाला नहीं है। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनको जल्द से जल्द रैगुलर किया जाए। जो कमेटी पे कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठी है वह उनके ग्रेडज के बारे में जरूर ध्यान दे ताकि इनके साथ जो बे-इंसाफी हो रही है। वह दूर हो सके। इसी तरह से हमारे बहुत सारे

जे0बी0टी0 टीचर्ज 1970 से ट्रेनिंग लिये बैठे हैं। और जब कभी सिलैक्टान की बात आती है तो उनको सिलैक्ट नहीं किया जाता। अब उनकी उमर भी तीस साल की होने वाली है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जब आगे कोई सिलैक्टान किया जाए ताकि जो लोग 10-12 साल से बेकार बैठे हैं उनको नौकरी मिल सके।

चेयरमैन साहब, आपको पता है कि मेरी कांस्टिचुएँसी सढौरा है। वह एक ऐसा गांव है जहां 19वीं भाताब्दी में लाहौर के बादप दूसरी म्युनिसिपल कमेटी बनी थी। वह जगह गुरु गोबिन्द सिंह और बन्दा बहादुर से जुड़ी हुई है। वह एक हिस्टारिकल प्लेस है लेकिन आज उस जगह की हालत बहुत बुरी है। पानी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर दो तीन ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं। अगर आप वहां से पानी की एक बालटी भरें तो थोड़ी देर बाद देखें कि बालटी में नीचे मिट्टी बैठी होती है। ऐसा पानी पीने से अब तक उस एरिया में 3-4 डैथस हो चुकी हैं। एक मरीज को पी0जी0आई0 में दाखिल करवाया गया है। उसकी जांच करने से पता चला है कि उसकी किडनी खराब हो गई है। मैं सरकार का और खासकर हैल्थ डिपार्टमेंट का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि वे वहां जाकर चैक करें। चार डैथ होने के बाद भी आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की कि उस पानी में क्या कमी है। वहां पर जो टैंक है और हैंड पम्प हैं उनका पानी पीने के काबिल नहीं है। इसलिये इस ओर ध्यान देकर वहां के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। वहां पर जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर है उसके पास पूरी दवाइयां नहीं हैं। जब उनके पास मरीज जाते हैं

तो उनको दाखिल नहीं किया जाता। लेडीज को लेबर के केस में जाना पड़ता है लेकिन वहां पर पूरा इन्तजाम नहीं है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर स्पै ाल इन्तजाम किया जाए। वहां पर एक 30 बैड के हस्पताल के लिये कागज जा चुके हैं और वह मंजूर भी हो चुका है लेकिन अभी तक काम भुरु नहीं हुआ है। इसके अलावा हालांकि वह बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है लेकिन न तो उसके ब्लाक हैडक्वार्टर बनाया गया है और न ही तहसील बनाई गई है। उस बैल्ट में ऐसे गांव हैं अगर उसको तहसील बना दिया जाए तो वह जस्टी फाइड है। जगाधरी को जिला बनाना सरकार के विचाराधीन है इसके साथ साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इसको तहसील बना दिया जाए ताकि वहां के लोगों को अम्बाला और नारायणगढ़ न जाना पड़े। मैं आपका भुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारा इलाका भी कालका और नारायणगढ़ जैसा है। इस इलाके के लिये हरिजनों की चौपालों के लिये एक प्रावधाना रखा गया है। ऐसे ही नारायणगढ़ और कालका के लिये भी है। लेकिन कालका और नारायणगढ़ में सरकारी की तरफ से 75प्रति ात ग्रांट दी जाएगी और सढौरा और छछरौली में 50 प्रति ात दी जाएगी। पीछे चीफ मिनिस्टर साहब वहां गये थे और उनके सामने यह समस्या लाई गई थी। उन्होंने वहां पर वायदा किया था कि इस इलाके में भी 75 प्रति ात ग्रांट दी जाएगी लेकिन अभी तक वह दी नहीं गई है। वह बैकवर्ड इलाका है और लोगों के पास छोटे छोटे घर हैं। वे लो 50 प्रति ात पैसा नहीं दे सकते इसलिये अगर 75 प्रति ात

ग्रांट दे दी जाए तो उन गरीब लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। (घंटी) चेयरमैन साहब, मेरा हलका नदियों से भरा पड़ा है। जब बरसात होती है तो पहाड़ी इलाकों से पानी आकर नीचे लोगों को नुकसासन पहुंचाता है। जब बरसात खत्म हो जाती है तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। पानी गहरा होने की वजह से वहां पर ट्यूबवैल्ज नहीं लग सकते हैं। (घंटी अगर एक आध जगह लग भी जाता है तो बिजली की कमी है। इसलिये जिस तरह से छोटे छोटे बांध बना कर एक्सपैरिमेंटस किये जा रहे हैं और उनसे लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है उसी तरह से इस तमाम बैल्ट में छोटे छोटे बांध बनवाए जाएं। इस पर ज्यादा खर्च नहीं होगा और इससे फ्लड की पोजी न भी ठीक हो जाएगी। बांध बांधने से पानी सिंचाई के काबिल हो सकता है। और जमींदारों को फायदा होगा। चेयरमैन साहब, मैं कहना तो और भी चाहता था लेकिन आप चूंकि बार बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं इस बजट के बारे में केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो इस सरकार ने वायदे किये हैं यदि सरकार उन वायदों को ठीक तरह से पूरा करती है और जो इसमें 40-50 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है अगर इस घाटे को सरकारी बीच में कोई ऐक्स्ट्रा टैक्स न लगा कर पूरा कर लेती है तो मैं इस सरकार को बधाई दूंगा। लेकिन चेयरमैन साहब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह सरकार इस घाटे को बिना टैक्स लगाये पूरा नहीं कर सकेगी। बल्कि यह टैक्स जरूर लगाएगी। चेयरमैन साहब, यदि यह सरकार यह वायदा करे कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो मैं इस बजट का समर्थन

करता हूँ वरना मैं इस बजट का विराध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री भाम ेर सिंह (नरवाना): चेयरमैन साहब, मेरे लोकदल के और जनता पार्टी के भाईयों ने खास करके जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, चौधरी उदय सिंह दलाल और हमारे विपक्ष के नेता बाबू मूल चन्द जैन जी, इन्होंने बजट पर चर्चा करते हुए जो इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का नक्शा खींचा है, जो आज डिफिकल्टीज हैं, चाहे डीजल की है, चाहे कैरोसीन की है और चाहे सीमेंट की हैं इन सब चीजों की कमी के लिए आज की कांग्रेस (आई) सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चेयरमैन साहब मैं अपने विरोधी भाइयों से नम्र भावना से अर्ज करना चाहता हूँ कि जरा आप अपने अंदर झाँक कर देखें और इस बात को टटोलें कि इनस्टैबिलिटी की जो दशा है उसके लिए दरअसल कौन जिम्मेदार है ? चेयरमैन साहब, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार इस देश में सत्ता में आई तो उस समय देश की अर्थ व्यवस्था यह नहीं थी, जो आज है। पिछले दो अढ़ाई साल के अर्से के दौरान जो जनता पार्टी का भासन रहा उसके कारण आज की अर्थ व्यवस्था बहुत बिगड़ी है। चेयरमैन साहब, इनस्टैबिलिटी की सारी जिम्मेदारी जनता पार्टी की सरकार की है क्योंकि उसमें जो घटक थे, वे आपस में लड़ और उसका नतीजा यह हुआ कि देश का जो प्रशासन था उसका ध्यान जनता की समस्याओं की तरफ

नहीं रहा। चेयरमैन साहब, उसके साथ साथ इन्स्टबिलिटी के जो दूसरे नतीजे निकले उनसे दे 1 की अर्थ व्यवस्था बिगड़ गई। कोयले की जो खाने थीं उनसे कोयला निकलना बंद हुआ और अर्थ व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण बहुत सी हड़ताले हुई, जिस वजह से डीजल की भी कमी हुई। जो हमारी रेलवे है उसका ढांचा ठीक तरह नहीं चला। इसकी वजह से जो हमारे थर्मल प्लांटस हैं उनमें कोयला पहुंच नहीं पाया। इस वजह से थर्मल प्लांटस बिजली भी ज्यादा नहीं हो सकी जिसकी वजह से हमारे कृषि उत्पादन के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा क्योंकि ट्यूबवैल्ज को पूरी बिजली के साधन नहीं जुटाए जा सके। चेयरमैन साहब, बिजली की कमी के कारण जाहं कृषि उत्पादन कम हुआ उसके साथ साथ कारखानों का भी उत्पादान कम हुआ। इस उत्पादन के गिरने के कारण दे 1 में चीजों की कीमतें और बढ़ गई और इस वजह से कंज्यूमर प्राइस इन्डैक्स भी बहुत ऊंचा बढ़ गया। चेयरमैन साहब, इस अवधि में जितनी प्राइस बढ़ी है इसकी मिसाल मेरे ख्याल में पिछले 30732 साल में नहीं मिलेगी। चेयरमैन साहब, इस आर्थिक अव्यवस्था का कारण मैंने पहले कहा दरअसल में राजनीति इन्स्टैबिलिटी ही थी। इसलिए जो आज बाद में कांग्रेस (आई) की सरकार है वह इसके लिए कतई तौर पर जिम्मेदार नहीं है बल्कि जनता पार्टी के ये मेरे साथी ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। चेयरमैन साहब, मैं उदाहरण के तौर पर एक बात हाउस में बताना चाहता हूं कि 1978 में भारत सरकार ने श्री जगजीवर नाम जी की अध्यक्षता में चीनी की पालिसी निर्धारित

करने के बारे में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि चीनी का मुकम्मल तौर पर डी-कंट्रोल कर दिया जाअए और उसके फलस्वरूप चीनी का डी-कंट्रोल किया गया। हमारे देा के जो अर्थ भास्त्री थे उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि अगर चीनी को डी कंट्रोल करके खुली मार्किट पर छोड़ दिया जाएगा तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। चेयरमैन साहब, उसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े समय के लिए चीनी तो सस्ती हो गई लेकिन किसानों को उनके भूगरकेन की कीमत पूरी नहीं मिली जिसकी वजह से किसानों ने निराशा होकर भूगरकेन की फसल बोने में दिलचस्पी नहीं ली और उसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। कि चीनी का क्या भाव है ? तो इन सारी चीजों के लिए उस समय की जनता पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। चेयरमैन साहब, जो हमारे बजट में लगभग 31 करोड़ का घाटा है और इस घाटे में वेतन आयोग की रिपोर्ट की वजह से 15 करोड़ और जड़ने वाला है। इस घाटे का मेन कारण उस समय की जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं और जनता पार्टी इस इनफ्लेन को रोकने का एक ही तरीका है कि सख्त कंट्रोल किया जाए और उस पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, उसको व्यापक बनाया जाए। इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन के खर्च हैं उनमें बहुत ज्यादा इकौनोमी बरतने की जरूरत है। अगर मेरे इन दो तीन सुझावों पर गौर किया जाए तो किसी हद तक इनफ्लेन को असर को रोका

जा सकता है और दे 1 के लोगों को चीजों की कमी से राहत मिल सकती है। चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाजत से इन तीन प्वायंट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। जहां तक इन चीजों को सख्ती से कंट्रोल करने का ताल्लुक है इसके लिए कानून बने हुए हैं और सरकार कानून के मुताबिक सख्ती से कार्यवाही करे लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि सरकार के रास्ते में दिक्कत क्या है ? चेयरमैन साहब, मैं यह बात कहने से कोई संकोच नहीं करूंगा कि भायद ऐसा करने की पोलिटिकल बिल न हो। अगर सरकार सख्ती से इन कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही करे तो इसमें कामयाबी हासिल करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कन्हैया लाल पोसवाल पदासनी हुए) चेयरमैन साहब, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि परसों जब मैं अपनी कांस्टिचुएँसी में गया तो मुझे बताया गया कि एक दुकानदार की सिविल सप्लाइ के महकमे के अफसरान ने चीनी बूरा और खण्डसारी की कुछ बोरियां पकड़ी हैं। जो कि स्टोक की हुई थी। उन अफसरान ने बूरा और खण्डसावरी के स्टोक के बारे में तो मुकद्दमा दर्ज कर लिया लेकिन चीनी का स्टोक उसमें नहीं दिखाया बल्कि उसे एक हलवाई के जुम्मे लगा दिया। इसी तरह से एक पेट्रोल पम्प पर छापा मारा गया उस पेट्रोल पम्प पर कुछ गड़बड़ नहीं था। अपना केस ठीक रखने के लिए उन्होंने रिपोर्ट में यह लिखा कि उस पेट्रोल पम्प पर तेल तो था लेकिन वह बेचने से इन्कार करता था। इसके दूसरी तरफ एक दूसरा पेट्रोल पम्प था

उसके खिलाफ कोई ऐकान नहीं हुआ। इसके खिलाफ लोगों ने जलूस भी निकाला था। चेयरमैन साहब, मैं एक बात 15 रोज पहले सिविल सप्लाइ मंत्री के नोटिस में लाया था, मैंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि अगर सरकार यह चाहती है कि जरूरी आर्टिकल्ज की स्केरसिटी खत्म हो, आर्टिफिशियल महंगाई कंट्रोल की जाए तो सरकार को मन बनाकर, नीयत बनाकर इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जो इस किस्म की हेराफेरी करते हैं। दरअसल जो लोग ऐसे कामों में इंडल्ज करते हैं, उनके खिलाफ चार मामले दर्ज करके या 50 मामले दर्ज करके माम नहीं चलेगा। इस पालिसी से सरकार का काम नहीं चलेगा और जो डिजायर्ड इफैक्टस हैं, वे हासिल नहीं होंगे। सबसे पहली मुख्य बात है कि वितरण प्रणाली को सुदृढ किया जाए। चेयरमैन साहब, हाउस में एलान किया गया कि जिस गांव की आबादी दो हजार से ज्यादा है उस गांव में सरकार को आप्रेटिव कंज्यूमर्ज स्टोर्ज खोलना चाहती है। सरकार का जो इरादा है इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि केवल दो हजार की आबादी का ही सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि हर उस मुहल्ले में जहां हरिजन बैकवर्ड भाई रहते हैं, भाहरों में कारखानों के मजदूर भाई, गांव के मजदूर, खेती-मजदूर, छोटे किसान या सरकारी मुलाजिम यानी जहां इन तबकों की एकत्रित पापुलेशन है, यह पापुलेशन चाहे 80 घरों की है, चाहे 100 घरों की है, वहां सरकार को दुकानों खोलनी पड़ेंगी और बहुत जल्दी खोलनी पड़ेंगी। ये

दुकानें ठीक प्रकार के आदमियों के माध्यम से खोलनी पड़ेंगी ताकि चीजों की स्केरसिटी की वजह से और महंगाई की वजह से लोगों में जो बेचैनी है, उसको काबू किया जा सके।

तीसरी बात मैं पालिटिकल लीडरि 1प के बारे में कहना चाहूंगा। पोलिटिकल लीडरि 1प, यानी हमारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ऐडमिनिस्ट्रे 1न से संबंधित बड़े बड़े लोग अपनी तरफ से काम करने का जो नमूना पब्लिक के सामने पे 1 करते हैं, लोग उसी पर अमल करते हैं। जन साधारण इन लोगों के कामों की तरफ देखती है। सरकार को आउस्टैरिटी मैयर्ज अपनाने चाहिए और सरकारी खर्चों में कमी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री समझदार आदमी हैं। मुझे मालूम है कि उनको ऐसी चीजों की लालुपता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास बड़ी बरें हैं, चाहे उन कारों का ज्यादा खर्चा भी न होता हो, फिर भी दिखावे के लिए ये कारें और कोठियां उन्हें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनको देखकर समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, आफिसर लोग हैं, उनके सामने जब आउस्टैरिटी की बात आती है तो वे अमल नहीं करते। इसलिए मेरी गुजारि 1 है कि छोटी कारें और छोटे बंगलों का प्रयोग मंत्री करें। मंत्रिमंडल की रूप रेखा को ही खूबसूरत बनायें ताकि दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। इन तीन बातों पर अगर सरकार अमल करेगी तो सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। सरकार की बात का लोगों को यकीन होगा और सरकार लोगों के दिल और दिमाग में उतरैगी। जब सरकार की बात का

लोगों पर असर होना भुरू होगा तो उसका कीमतों पर भी असर पड़ेगा। यानि सारे कामों पर असर पड़ेगा। चेयरमैन साहब, ये बातें मैं अपनी पार्टी की सरकार होने के नाते कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन बातों को ज्यादा महसूस करता हूँ और इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि मेरी यह प्योर भावना है कि जिस पार्टी से मैं संबंधित हूँ। उसका इम्मेज, उसका नक्शा खूबसूरत हो ताकि हम गौरव के साथ अपना सर ऊंचा कर के चल सकें। चेयरमैन साहब, थोड़ा टाईम होने के कारण मैं बहुत जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव खर्चा कम करने के बारे में है। सरकारी खर्चा कम करने का एक और तरीका भी है। सरकार ने एक काम करने के लिए कई कई एजेंसियां बनाई हुई हैं। मैं उन सारी एजेंसियों का नाम याद नहीं रख सकता लेकिन ये एजेंसियां एक ही काम करती हैं। किसान को ट्यूबवैल लगाने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए कर्जा मिलता है। कर्जा लैंड डिवैल्पमेंट बैंक के इलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी देता है, दूसरे फाइनेंशियल बैंक्स भी कर्जा देते हैं और ये जमीन की लैवलिंग के लिए, मकान बनाने के लिए और ट्यूबवैल लगाने के लिए भी कर्जा देते हैं। एक ही काम के लिए तीन एजेंसियां काम करती हैं। इसी तरह मुफाल एस0एफ0डी0ए0, लैंड रिक्लेमेन्ट एंड डिवैल्पमेंट कारपोरेट वगैरह कई एजेंसियां हैं जो एक ही तरह का काम करती हैं। चेयरमैन साहब, पिछली सरकार चाहे वह जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे लोक दल की सरकार थी, जो भी हो, मैं हर बजट सेशन में सुझाव देता था कि इन एजेंसियों

के खर्चे में कमी की जा सकती हैं। खर्चा कैसे ज्यादा होता है, यह बताने जा रहा हूँ। हर एजेंसी का, हर कोरपोरेट का अलग बोर्ड होता है और उस बोर्ड का अलग चेयरमैन होता है। इनके अपने अपने रैस्ट हाउसिज हैं। और उन रैस्ट हाउसिज में एस्टेबलिशमेंट है। इन एजेंसियों से किसान को बड़ी भारी दिक्कत है। एक एजेंसी के छोड़ कर दूसरी एजेंसी में जाना पड़ता है। कर्जे के लिए दरखास्त देनी पड़ती है। अगर एक ही एजेंसी हो तो बहुत सा खर्चा कम हो सकता है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार की थोथी बातों को सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। मैंने चौधरी देवी लाल को कहा था कि किसान का नाम जितना आप लोगों ने उछाला है, जितनी डिसेन्स आपके किसान की की है, उतीन किसी ने नहीं की और किसान को मेन स्ट्रीम से दूर लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त मैंने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन आज मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी की सरकार है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, मेरे सुझावों पर जरूर अमल करेगी। अब मैं कोऑपरेटिव अदारे, पंचायती राज के अदारों के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, आप गांव से ताल्लुक रखते हैं, आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरिएंस रहा है, इन अदारों के द्वारा गांव के लोग तरक्की के कामों में हिस्सा ले सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सैंकंड लाईन की जो लीडरशिप है, उसमें ये अदारे अपना रोल अदा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों अदारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोऑपरेटिव अदारों में

पालिटिकल दखल बहुत ज्यादा है। चेयरमैन साहब, आपको तजुर्बा है, कोई भी चुनाव चाहे वह कोआप्रेटिव बैंक का है, चाहे किसी कारपोरेट का है, बिना पालिटिकल दखल से पूरा नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि जो ठीक आदमी है वह इलैव इन लड़ने से डिस्हर्टन हो जाता है, घर बैठ जाता है। इसके इलावा सरकारी आफिसर्ज की तबदीलियां बहुत ज्यादा होती हैं, चाहे वे कोआप्रेटिव भूगर मिल के हो, चाहे हैफेड के हों। चेयरमैन साहब, आई०ए०एस० आफिसर्ज और एच०सी०एस० आफिसर्ज को मैनेजिंग डायरेक्टर आदि लगाने की प्रथा पिछले कई सालों से चली आ रही है जिसका नतीजा यह है कि उनकी तीन, चार या छः महीने से ज्यादा वहां पास्टिंग नहीं होती। क्योंकि वे परमानेंटली वहां पर नहीं ठहरते। इस तरह से कोआप्रेटिव सैक्टर बड़ा निगलैक्टिड है। पंचायती राज का भी बहुत बुरा हाल है, इसका कोई पूरा डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर पंचायत, डिप्टी सैक्रेटरी भी होते हैं, इसलिए वे सैक्रेटरी में बैठते हैं। वहां तो एक डिप्टी डायरेक्टर और ज्वॉयंट डायरेक्टर का छोटा सा आफिस है। आज किसी को यह पता नहीं कि गांव के स्तर पर जो कर्मचारी है उसकी ट्रांसफर कौन करेगा ? उनकी सविर्स कंडी नन्ज कहां से रेगुलेट होंगी किसी को पता नहीं। कभी फाईल डायरेक्टरेट में जाती है तो कभी सैक्रेटरी में आती है। इसके लिए सरकार को थ्री टायर सिस्टम अपनाना पड़ेगा। जिला परिशद और पंचायत समितियों को बना कर उनके चुनाव करवा कर पूरी पावर जिला लैवल तक की जिला परिशद को दी जाए। आज गांव में एक

पटवारी रहता है, एक ग्राम सेवक रहता है। एक सब इंस्पैक्टर ऐग्रीकल्चर रहता है, एक बिजली का कर्मचारी होता है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है। कहने का मतलब यह कि 7-8 वर्कर्स भिन्न भिन्न महकमों के गांव में रहते हैं। सब डिविजन और जिला लैवल पर कोई ऐसा आफिसर नहीं है जो एक कोऑर्डिनेटर का काम करें। चेयरमैन साहब, ब्लॉक डिवैल्पमेंट की स्कीम जब बनी थी, इसका परपज यह था कि इंटेग्रेटेड एप्रोच गांव के कामों की तरफ हो। काऑर्डिनेटर के रूप में बीडीओ होगा। भुरु भुरु में आपने देखा होगा कि सारे महकमों के कर्मचारी एक बिल्डिंग में बैठते थे और गांव के लोगों को वहां जाकर अपने काम करवाने में सहूलियत होती थी। आज किसी को पता नहीं कि वह अपने काम के लिए कहां जाए। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

चेयरमैन साहब, वेतन आयोग की रिपोर्ट को ऐग्जामिन करने के लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई है। उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इस समय इसमें तीनों आफिसर्स आईओएस के हैं। इससे नौन आईओएस लोगों में बड़ी बेचैनी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें चौथे मैम्बर के रूप में या तो ऐग्जामिनर लोकल फंडज अकाउंट्स को ले लिया जाए या प्रिंसिपल अकाउंट्स कालेज को ले लिया जाए ताकि कमेटी को टैक्नीकल राय भी मिल जाए और दूसरे लोगों को सैटिसफैक्शन भी हो जाए। (विघ्न) मैं चेयरमैन साहब, एक बात बेरोजगारी और

हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूँ। हरिजनों को जमीन देने की बात बहुत देर से चली आ रही है। यह बड़ा भारी पोलिटिकल मसला है। मेरी सरकार से दरखास्त है कि चाहे वह नजूल की जमीन है, कस्टोडियन जमीन है, सरकारी जमीन है या कोई दूसरी जमीन है, सरप्लस जमीन को छोड़कर और किसी जमीन के अधिकार मलिकयत हरिजनों को अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जिसकी वजह से लगातार मुकद्दमाबाजी में और रि वतखोरी में हरिजनों का सारा टाईम और रुपया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब हमारी सरकार जल्दी ही इस मसले को हल करेगी।

चेयरमैन साहब, बेरोजगारी के मसले के बारे में मैं यह कहूंगा कि सरकार सबको रोजगार तो नहीं दे सकती है लेकिन बेरोजगारों से खिलवाड़ करना तो बंद कर सकती है। मैंने पीछे भी यह सुझाव दिया था कि ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज गांव में भी खोले जाएं, रूरल ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज के दफतर बड़े बड़े गांव में खोले जाएं। मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में कहा कि गांव में जाकर के नाम रिकार्ड करेंगे लेकिन वह प्रैक्टिकल बात नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं यह भी दरखास्त करूंगा कि जब कभी कोई पोस्ट ऐडवरटाइज हो, उसका इन्टरव्यू और इम्तहाचन होने के बाद रिजल्ट निकालने के लिए कोई टाईम निर्धारित होना चाहिए चाहे वह पन्द्रह दिन का हो या एक महीने का हो। प्रायः देखा गया है कि एस0एस0एस0 बोर्ड और सर्विस कमी 1न 6—6 महीनें तक, एक एक साल तक रिजल्ट आउट नहीं करते। लोग

इन दफतरों के चक्र काटते फिरते हैं केवल यह पूछने के लिए कि कब फैसला होगा। सिफारि ां पर सिफारि ां चलती हैं, लिस्टों पर लिस्टें बदली जाती हैं आज सर्विस कमी ान और एस0एस0एस0 बोर्ड के ऊपर बेरोजगार लोगों का कोई कांफिडेंस नहीं है।। मेरी सरकार से यह गुजारि ा है कि यह बड़ा सीरियस मैटर है। आप कृपया सर्विस कमी ान और एस0एस0एस0 बोर्ड में बेरोजगारों का कांफिडेंस क्रिएट करें। इसके अलावा मेरी यह भी प्रार्थना है कि एक तो किसी पोस्ट के लिए ऐप्लाइ करने के लिए जो फीस रखी जाती है वह माफ होनी चाहिए और दूसरा इन्टरव्यू के लिए आने जाने का किराया उनको दिया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, यह बात कहकर आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति: चौधरी संत कंवर।

श्री भागी राम: चेयरमै साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि यहां बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, आपसे कैसे इजाजत लेनी पड़ती है ?

श्री सभापति: आपने इजाजत दुरुस्त ली। कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए और मैंने कहा कि श्री संत कंवर जी बोलेंगे। (हंसी) आप घबराएं नहीं, आपको भी समय मिलेगा।

(विधन) एक अपोजी इन की तरफ से बोल रहा है और एक ट्रैजरी बेंचिज की तरफ से बोल रहा है।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ): चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत भुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। (विधन)

श्री सभापति: मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी स्पीच देंगे और अच्छी सुजै इन्ज भी देंगे। (विधन) नो इन्ट्रू इन प्लीज।

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, * * * सरकार के वित्त मंत्री द्वारा यह जो 48 पृशठो का कागज का पलन्दा यहां पे आ किया गया है। इसके ऊपर मैं भी अपनी बात दस पन्द्रह मिनट में खत्म करना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, बड़े दुःख की बात है कि इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए यह बजट पे आ किया है। इस बजट में 31 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। 15 करोड़ रुपये का और घाटा पे कमी इन की रिपोर्ट से होगा। कुल मिला कर यह 46 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

चेयरमैन साहब, इस बजट के अंदर से तरफ तो यह लिखा गया है कि नैचुरल कैलेमिटीज से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है लेकिन दूसरी तरफ बड़े अफसोस की बात है कि उनको सहूलियत देने की कोई बात इसके अन्दर नहीं लिखी गई है। उल्टा तीन करोड़ रुपये का कट वित्त मंत्री जी ने ऐग्रीकल्चर

पर लगाया है जबकि दूसरी पूंजीवाद को बढ़ाव दिया है क्योंकि पूंजीपतियों से चुनाव में पैसे लिए थे। (विघ्न)

श्री सभापति: आपके पास कोई हिसाब होगा ?

श्री सभापति: चेयरमैन साहब, इन्होंने बहुत सारी सहूलियतें व्यापारियों को दी हैं। सबसे बड़ी छूट तो यह है कि दो लाख रुपये तक की सेल के सेल्ज टैक्स का हिसाब किताब अब वे स्वयं रखेंगे। (विघ्न) चेयरमैन साहब, सात किस्म की रियायतें व्यापारियों को दी गई हैं दूसरी तरफ एक भी पैसा किसानों की भलाई के लिए इन्होंने इस बजट के अंदर पिछले साल के बजट के मुकाबले में ऐड नहीं किया है, उल्टा तीन करोड़ रुपये का कट लगाया है।

इसी तरीके से चेयरमैन साहब इन्होंने हैल्थ के मद में 60 लाख रुपये का कट लगाया है। स्वास्थ्य के बारे में ये कहते तो बहुत कछ हैं लेकिन आज ही आपने सुना होगा एक सवाल के जवाब में हमारे मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारी हमारी औरतें बच्चा पैदा होते ही मर जाती हैं, उन्हें कोई मैडिकल सुविधा नहीं मिल पाती। इसके बावजूद भी वित्त मंत्री जी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज दूर दराज के गांव में एक भी ऐसा हस्पताल नहीं है जहां हमारी बहू बेटियां बच्चा होने के समय में मैडिकल सुविधा प्राप्त कर सकें।

चेयरमैन साहब, अब मैं इस सदन का ध्यान एक विशेष बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे कई साथियों ने खास तौर स्वामी जी ने इस सरकार की बड़ी बड़ाई की है। चौधरी देवी लाल की वे बुराई करते रहे। चेयरमैन साहब, बहुत सारे इलाकों में, खास तौर पर मेरे इलाके में इस साल भी ओले पड़े और पिछले साल भी ओले पड़े थे। (विधन) मेरे इलाके में 15 गांव में पिछले साल ओले पड़े और 15-20 गांव में इस बार ओले पड़े। सरकार को हमने चिट्ठियां भी लिखीं लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई रियायत नहीं दी। आज तक यह भी डिकलेयर नहीं किया कि हम उगाही माफ कर देंगे। इस किस्म की सरकार जो किसान मजदूर को तहस नहस कर रही है, वह चल नहीं सकती। जितना इस सरकार का वकाचर है उसके बारे में आपको पता ही है। मैं इस बात वित्त मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इतनी लंबी कारें हरियाणा में पहले कभी नहीं थी लेकिन मंत्रीगण आजकल गांवों में लंबी लंबी कारे लेकर जाते हैं। गांवों के लोग उनको देखना भी पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि यह डिफैक्टर्ज की सरकार है इसलिए उनकी भाकल देखना जनता पसन्द नहीं करती।

चेयरमैन साहब, बेरोजगारी बराबर बढ़ रही है। आज गरीब आदमी अपना पेट बांध कर अपने बच्चों को स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाता है लेकिन वे पढ़ लिख जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। जो लोग सरकार में होते हैं या जिन के हाथ में

ताकत होती है उनके बच्चों को नौकरी मिल जाती है या उनके बच्चों को मिलती है जो रि वत देते हैं या सिफारि ा करवाते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीब आदमी के बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि बेरोजगार जब सड़कों पर आ जायेंगे तो इस सरकार को एक दिन भी चलने नहीं देंगे। इस बजट स्पीच में बेरोजगारी हटाने के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। चौधरी देवी लाल की सरकार ने जो गरीबों के लिए गांवों में सुविधायें प्रदान की थीं, वे भी इन्होंने भाहर के रहने वालों के हाथों में सौंप दी। चौधरी देवी लाल की सरकार के टाईम पर यह हिदायत जारी की गई थी कि गांवों का रहने वाला बेरोजगार युवक इंडस्ट्र लगा सकता है। सरकार ने पहले इसीलिए यह अंकु ा लगाया था कि भाहर के रहने वाले बड़े सयाने होते हैं और अमीर भी होते हैं। इसलिए उनको वहां आज़ा न दी जाये। दूसरे ऐसा करने से गांवों के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाता था लेकिन इस सरकार ने वह सब खत्म कर दिया। आज जिन गरीब नौजवानों ने गांवों में इंडस्ट्रीज लगायी थी वे बच नहीं सकती क्योंकि तायल साहब और दूसरे मंत्री जी अपने भाहर के रहने वालों को गांवों में भेज देंगे और वे ही वहां इंडस्ट्री लगायेंगे। इसलिए उन लोगों को इजाजत देकर सरकार ने गलत काम किया है।

चेयरमैन साहब, इस सरकार ने डीजल का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया है। सूखे के टाईम पर किसान ब्लैक में छः छः

रुपये लीटर तेल लेते रहे। बिजली आती ही नहीं। यह सरकार कहने को कहती है कि आठ घंटे तक बिजली देते रहे हैं जबकि एक एक और दो दो घंटे बिजली मिलती थी।

चेयरमैन साहब, एस0वाई एल0 के बारे में कांग्रेस (आई) सरकार ने नारा दिया है कि हम पानी लेकर आयेगे। हम अपनी लोक दल की पार्टी की तरफ से एलान कर चुके हैं कि अगर एस0वाई0एल0 का पानी लेने के लिए यह सरकार जो भी आन्दोलन चलायेगी हम उसका साथ देंगे लेकिन यह सरकार किसी प्रकार का कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। एस0वाई0एल0 का पानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के पचास भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाद कोई और टैक्नीकल अडचन आयेगी जिसके कारण फिर रूकावट पड़ेगी। इसलिए इस पानी को लेने का तो एक ही तरीका है कि पंजाब के दिल्ली जाने के सारे रास्ते रोक दिये जायें। पंजाब वाले हमारे भाई हैं, आज से कुछ साल पहले हमारा एक ही प्रान्त था लेकिन जिस तरह से पंजाब वाले कर रहे हैं वह अच्छा नहीं। पंजाब के अंदर पानी बेकार जा रहा है, समुद्र में जा रहा है लेकिन हमारे हरियाणा की जमीन पानी के लिए तरस रही है, किसानों पानी के लिए हाहाकार मचा रहा है लेकिन वे इस पानी को देने के लिए तैयार नहीं। इस नहर की खुदाई का हरियाणा के पास एक ही तरीका है कि पंजाब के तमाम रास्ते जो हरियाणा से दिल्ली को जाते हैं दस दिन के लिए रोक दिये जायें तो अपने आप ही वह इस पानी को देंगे।

जब तक उनके साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तब तक वे पानी देने वाले नहीं हैं।

चेयरमैन साहब, दो तीन बातें इस सरकार ने बड़ी अच्छी की है जैसे हरिजननों के लड़कों को दस रुपये महीना वजीफा देना आरम्भ कर दिया है और दूसरे बाल्मिकीयों की पचास रुपये महीने के हिसाब से तन्ख्वाह में बढ़ौतरी की है।। बहिन भांति जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 300 लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए कहा है। बड़ी अच्छी बात की है।

चेयरमैन साहब, आपका पता है कि जब नयी नयी जनता सरकार बनी तो उसमें हमारे स्वामी परमानन्द (स्वामी आदित्यवे 1) भाराब के बड़े विरोधी थे। उन्होंने एम0एल0ए0 होस्टल में भूख हड़ताल भी की थी। बड़ा भारी स्टैप लिया था। जब हम एम0एल0ए0 होस्टल में मिलने के लिए गये तो हमने कहा कि स्वामी जी आप अकेले ही भूख हड़ताल पर बैठे रहे तो भी हम तमाम आपके साथ होंगे क्योंकि भाराब बन्दी होनी चाहिए लेकिन स्वामी जी बीच में भूख हड़ताल खत्म करके चले गये। पहले यही स्वामी जी सै।न में रैजोल्यू।न सरकार के खिलाफ लाते थे लेकिन अब उनको कुछ पता नहीं है कि भाराब बन्दी भी होनी चाहिए या नहीं। पहले वे 300 गांवों में लिखवा कर रैजोल्यू।न भेजा करते थे, बहुत अच्छी बात करते थे लेकिन आज उनकी हालत यह है कि वे भाराब बेचने के लिए भी तैयार हैं। दलाल

साहब ने बताया है कि विदेशों में मार्किट की तलाश में हैं। (हंसी) चेयरमैन साहब, स्वामी तो सभी के होते हैं इसलिए उनको सब भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए।

अब मैं चेयरमैन साहब, आपके द्वारा कुछ सुझाव भी सरकार को देना चाहता हूँ। पहला सुझाव तो यह है कि जो यह इतना बड़ा मंत्रिमंडल है इसको छोटा किया जाये। जो इतनी लंबी लंबी कारें लिए फिर रहे हैं, इनको बदलवाया जाये। ये मिनिस्टर कारों के काबिल नहीं हैं इनको तो स्कूटर दिये जाने चाहिए। (हंसी)

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि जितने भी कार्पोरेट्स और बोर्ड हैं इनकी मैन्टेन्स पर बड़ा भारी खर्चा हो रहा है। इन खर्चों को कम करना चाहिए। बोर्ड और कार्पोरेट्स में एम0डी0 की मेज पांच पांच हजार रुपये की है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके हैड आफिसिज दिल्ली में हैं। उनका सारा सैल्सटैक्स हमें आना चाहिए लेकिन वह दूसरी स्टेटस को जा रहा है। सरकार को इस बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को कोई कमेटी बनानी चाहिए, वह इस बारे में विचार करके उनके हैड आफिसिज को यहां हरियाण में लाये। अगर उनके दफतर हरियाण में आ जाये तो हमारा बजट घाटे में नहीं रहेगा।

इन भावों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ क्योंकि यह बजट पूँजीपतियों का है और गरीबों को मरने वाला है और आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर—अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, वर्ष 1980—81 का हरियाण का जो बजट हमारे वित्त मंत्री श्री बलवन्त राय तायल जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बजट को फाईनैन्स डिपार्टमेंट के जिन ऐक्सपर्ट्स ने बनाया वे सब के सब दाद के मुस्तहक हैं। जनता सरकार का वर्ष 1977—78 का पहला बजट श्री सतवीर सिंह मलिक जी ने पेश किया था (विधन) जो बजट मलिक साहब ने पेश किया था उसका जैन साहब ने क्लिटिसिज्म किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह व्यपार विरोधी बजट है और पुराने आंकड़े इकट्ठे करके इसे तैयार किया गया है। उन्होंने यह कहा था कि इस बजट का मैं समर्थन तो करता हूँ परन्तु यह जरूर कहूंगा कि यह प्लानिंग के साथ तैयार नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 1979—80 का बजट बाबू मूल चन्द जैन जी ने पेश किया था। जैन साहब खुद जानते हैं कि हमारी विधान सभा के सदस्यों ने उसे किसान विरोधी बजट बताते हुए बजट की प्रतियां फाड़ डाली थीं। उसके बाद का अर्थात् वर्ष 1980—81 का बजट हमारे वित्त मंत्री श्री बलवन्त राय तायल जी ने पेश किया है। कई दिनों से इस बजट पर चर्चा चल रही है। इस बजट हमारी कांग्रेस 'आई' के

लोगों ने पसन्द किया है। इस बजट के अन्दर केवल 31.14 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। मेरी हरियाणा के मुख्य मंत्री जी से गुजारि है कि इस घाटे को अपने खर्चा में कमी करके और सेंटर सरकार से पैसा लेकर पूरा करें।

चेयरमैन साहब, हरियाणा प्रदेश का कृषि प्रान्त है। इस प्रदेश के अन्दर पिछले दो तीन सालों से बाढ़, सूखे और अकाल से तबाही हो रही है। कहीं पर ओले पड़े हैं तो कहीं पर सूखा पड़ा है। सूखे से लगभग 165 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है। सूखा पड़ने के कारण किसानों को आबियाना में छूट दी गई है और उनके कर्जों की वसूली को रोगा गया है। बाल्मीकियों के लिए हमारी सरकार ने 50 रुपये प्रतिमास के हिसाब से बढ़ाये हैं। मजदूरों की मजदूरी 6 रुपये से बढ़ा कर 8 रुपये कर दी है। बैकवर्ड क्लासिज के लिए रिजर्वे इन 5 प्रति शत से बढ़ाकर 10 प्रति शत कर दी है।

आप जानते हैं कि बिजली की कमी सारे भारतवर्ष में रही है। बिजली की ही कमी नहीं रही अपितु डीजल, तेल आदि की भी काफी मात्रा में कमी रही है। इराक से काफी मात्रा में तेल आ रहा है। मुझे आशा है कि तेजी की कमी पूरी हो जायेगी। आपको भी मालूम है कि बिजली अधिक पैदा करने के लिए थर्मल प्लांट चालू किए गए हैं। पिछले दिनों पानीपत के अन्दर 110 मैगावाट का एक थर्मल प्लांट चालू किया गया। दूसरा प्लांट भी लगभग तैयार है और आशा है कि वह भी भीघ्र चालू हो

जायेगा। इसी प्रकार से फरीदाबाद और यमुनानगर के अन्दर भी थर्मल प्लांट चालू किए जा रहे हैं हरियाणा के अन्दर बिजली की जो कमी चली आ रही है यह कमी इन प्लान्टों के चालू हो जाने के बाद दूर हो जायेगी। हमारे पिछले साल की योजना 210 कराड़ रुपये की थी। इस सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए 240 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है।

श्री मूल चन्द मंगला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। कैप्टन मांगे राम बजट पर बोल रहे हैं। जवाब तो वित्त मंत्री महोदय दे देंगे।

कैम्टन मांगे राम: चेयरमैन साहब, अब मैं बिजली बोर्ड के बार में कुछ अर्ज करता हूँ। बिजली बोर्ड के अन्दर एक सिक्योरिटी विंग है। जिसके अभी तक पे-स्केल रिवाईज नहीं किए गए हैं। (विधन) अगर कर दिए गए हैं तो अच्छी बात है क्योंकि इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। इस श्रेणी में ज्यादातर ऐक्स सर्विसमैन हैं। इसलिए उनके पे-स्केल अब य रिवाईज किए जाएं।

चेयरमैन साहब, अब मैं इन्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि झज्जर को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित किया जाये। इस एरिया को देखनके लिए बड़े बड़े डायरेक्टर साहब और बड़े बड़े ऐक्सपर्ट आये थे। उन्होंने वि वास दिलाया था कि झज्जर को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोशित कर दिया जायेगा। लेकिन खेद है कि इस क्षेत्र को अभी

तक बैकवर्ड घोशित नहीं किया गया है। हरियाणा के दूसरे इलाकों को देखते हुए झज्जर को भी भीघ बैकवर्ड घोशित भीघ किया जाये। जिस प्रकार से धारुहेड़ा और नवादा को सरकार ने बैकवर्ड घोशित किया है उसी प्रकार से झज्जर क्षेत्र को भी किया जाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, आपको मालूम है कि झज्जर तहसील के अन्दर ज्यादातर फौजी हैं और वे सिवाही रेंक से पें इन लेकर आते हैं। उन पें इन से उनके बच्चों का गुजारा नहीं चलता। खर्चे बढ़ जा रहे हैं और उस पें इन से उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके लिए सर्विसिज में अधिक रिजर्वे इन होनी चाहिए। अगर उनकी एज भी ज्यादा होती है तो उसमें रिलैक्से इन होनी चाहिए। कोई व्यक्ति फौज से 40-45 वर्ष की आयु के करीब ही रिटायर होकर आता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी एज में सर्विस के लिए रिलैक् इन होनी चाहिए। सर्विसिज में जो भाार्ट फाल है वह भी पूरी होनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, झज्जर म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में मुझे बड़ा खदसा है। वहां की सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब हमारे मिनिस्टर लोग वहां पर जाते हैं तो उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों को देखा गया होगा। उन सड़कों की बहुत बुरी हालत है। चेयरमैन साहब गुडयानी वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जानी थी जिसके अन्दर कासनी, सुरहती, खेड़ी ढांकला, सुबाना आदि गांव

आते हैं, लेकिन वह स्कीम अभी तक चालू नहीं की गई। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि उस स्कीम को जल्द से जल्द चालू किया जाये।

चेयरमैन साहब, अब मैं ऐजुके ान के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। झज्जर तहसील सैनिकों की तहसील है। वहां का एरिया बाढ़ से इफैक्टिड है। मेरे हल्के के अन्दर पिछले वर्ष के दौरान 2 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल और दो प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूल बनाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि झज्जर तहसील सैनिकों की तहसील होने की वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए जाएं।

चेयरमेन साहब, मेरे हल्के में सबसे कम सड़कें बनी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तालाब से छूछकवास और अहमदपुर, पड़तल, सरोल, भीड़ावास ग्राम वाली सड़कें बनाई जाएं।

चेयरमैन साहब, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कहना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट श्री जगन नाथ जी के पास हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि सालहावास और नाहड़ के एरिया में बसें चालू करने के लिए कम से कम चार बसें दी जायें क्योंकि हरियाणा में 200 बसें और आ रही हैं दूसरे मेरी यह भी प्रार्थना है कि झज्जर से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से झज्जर के लिए बसें चलनी चाहिए ताकि झज्जर के लोगों को चण्डीगढ़ आने जाने में

कठिनाई न हो। इसी तरह से कोसली जो कि राव राम नारायण जी के हल्के सालहावास के साथ लगती है और नयी सब तहसील भी बन गयी है, यहां से चण्डीगढ़ और वाईस वर्सा के लिये एक बस जरूर लगानी चाहिए। (व्यवधान) (घंटी)
चेयरमैन साहब, बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक बड़ा झगड़ा है। झज्जर के थाने की बिल्डिंग फ्लड की वजह से बिल्कुल टूट गयी है और वह बिल्डिंग बिल्कुल तबाह हो चुकी है इसलिये इथी भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये वरना यहां के पुलिए वालों को भगौड़ों की वजह से सजा सकती है। इसी तरह से अनाज मंडी की बाबत भी मैं कहना चाहता हूं वपहां पर सीवरेज और सड़क का सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। प्लाटस भी 188 के करीब काट दिये गये हैं। अगर 20-25 प्लाटस यहां के लोकल बिजनेसमैन को रीजनेबल रेटस पर दे दिये जायें तो यहां पर आउटसाईड वाले लोग भी आकर प्लाट खरीदेंगे और वह मंडी डिवैल्प हो जायेगी। (व्यवधान व भाोर) इसके अलावा एक और मामला है। यह जो सो ल वैल्फेयर डिपार्टमेंट है, राठी साहब इसके वजीर हैं, जो कि यहां पर बैठे हुए हैं। सो ल वैल्फेयर के लिए बजट तो काफी बढ़ाया गया है लेकिन पता नहीं क्यों पहले जो जनता सरकार के टाईम पर दो तीन स्कीमों चल रही थीं व बन्द कर दी गयी हैं। एक स्कीम भाडयूल्ड कास्टस लोगों को ड्रिकिंग वाटर प्रोवाइड करने के बारे में थी। इस स्कीम के तहत तीन हजार रुपया नया कुंआ खोदने के लिये मिलता था। वह भी खत्म कर दी गयी है। इसके अलावा 500 रुपये कुओं की रिपेयर

सबसिडी के तौर पर दिया जाता था जो कि अब बन्द कर दिया गया है इसके अलावा मकानों की कंस्ट्रक्शन के लिये पहले 2000 रुपये मिलते थे अब वे घटाकर 1000 रुपये की दिये गये हैं। इसके अलावा रोहतक में सिर्फ 25000 रुपया इन्ट्रैस्ट फ्री लोन स्कीम के तहत बांटा गया है जो कि बहुत ही कम रकम है। मैं चाहूंगा इसके कम से कम 2 लाख किया जाये। गवर्नमेंट मैडीकल कालेज तथा हस्पताल रोहतक की पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सिज में हरिजनों के लिए रिजर्वे इन नहीं है। मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि यह रिजर्वे इन भाडयूल्ड कास्टस के लिए भीघ्र से भीघ्र करवाने की कृपा करें। चेयरमैन साहब, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मैं सरकार की बुराई तो नहीं करता लेकिन जो सच्ची बात है वह अगर कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है। फूड एण्ड सप्लायज डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को क्लर्क और जूनियर आडीटर्ज के पदों से पीयन्ज के पदों पर विर्ट कर दिया गया है। 6-7 साल की सर्विस इन बेचारों की इन पोस्टों पर हो गयी है लेकिन फिर भी इनकोम रिवर्ट कर दिया गया है। वे भाडयूल्ड कास्टस लोग हैं जिनको 7 साल तक जूनियर आडीटर्ज और क्लर्क की पोस्टों पर काम करते हुए हो गयह हैं लेकिन अब इनको यह कहा गया है कि क्योंकि इनका नाम एस0एस0एस0 बोर्ड ने एप्रूव नहीं किया, इसलिये इनको रिवर्ट किया जा रहा है। यह कितनी ज्यादाती की बात है जबकि उनकी अप्वायंटमेंट के वक्त ऐसी कोई भार्त नहीं रखी गयी थी। इन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट भी कर रखी है। इन्हें अब यह कहा जा रहा है कि आप पीरन वाली

तनखाह ले लो। (विघ्न) ये कहते हैं कि रिजेर्वे इन इन प्रोमो इन वाली पालिसी अपना रहे हैं, मैं कहता हूँ कि रिब इन इन प्रोमो इन वाली बात चल रही है। इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करूँगा कि वह इन गरीब भाडयूल्ड कास्टस लोगों की तरफ ध्यान दें और इनको पुनः जूनियर आडीटर और क्लर्क की पोस्टों पर लगाया जाये।

श्री सभापति: अब आप वाइन्ड अप कीजिये। (घंटी)

कैप्टन मांगें राम: चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): चेयरमैन साहब, पिछले चार दिनों से वर्य 1980-81 का जो बजट है, उस पर होने वाली बहस में मेरे साथियों ने और अपोजी इन बैचिज वालों ने हिस्सा लिया। जैसे किसी ने बजट को देखा, उसी तरह की अपनी अपनी राय दीं सबसे पहले चेयरमैन साहब, अपोजी इन के लीडर ने इस बजट पर बहस का उदघाटन किया। इन्होंने कई विधान सभाओं के अन्दर कई बार बजट पे 1 किये हैं, घाटे के भी और नफे के भी किये हैं।

चौधरी भजन लाल: नफ का कोई नहीं किया।

लाला बलवन्त राय तायल: चलो घाटे के ही किये होंगे। मैंने यह जो घाटे का बजट पे 1 किया है। मेरा यह ख्याल था कि जैन साहब मेरी मदद करेंगे यह सुझाव देकर कि इस घाटे

को कैसे पूरा किया जाये। मैं इनसे सुझावों की उम्मीद रखता था। यह बाप चेरमैन साहब जानते हैं कि आज हरियाणा के अन्दर जितने टैक्स लगे हुए हैं, अगर उन्हीं को ठीक तरीके से वसूल/इकट्ठा कर लिया जाये तो भायद हमें कोई भी नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैन साहब का पहला ख्याल तो यही था। लेकिन जब टैक्सों की बात करते हैं तो इन के दिमाग में पहले तो हलवाई आते हैं। अगर हलवाई इनसे खुशामद कर कराके पीछा छोड़ा भी लें तो फिर इनके दिमाग में चेरमैन साहब वे लोग या व्यापारी आते हैं जो आज हरियाणा के अन्दर बाहर से थोड़ा बहुत सामान थैलों में लाकर 10-15 रुपये मजदूरी के कमा लेते हैं, उनको पकड़ने के लिये इनके दिमाग में बात आती है। चेरमैन साहब, मैं एक मिसाल आपकी मार्फत हाउस में देना चाहता हूँ। जब कोई बच्ची के लिए दूध नहीं छोड़ता। यही कोर्नर करता है कि चूहंटी से दूध निकाल लें। इसी तरह से जैन साहब की यह प्रोजेक्ट है कि हम उन लोगों को भी पकड़ें जो थैलों में थोड़ा बहुत सामान लेकर आते हैं। रेलवे वालों के प्रिमिसिज के अन्दर तो हम घुस नहीं सकते क्यों कि उनकी अपनी फोर्स होती है। इनका कहना यह है कि हम उन लोगों की भी तलाशी लें जिस तरह से पुरानी राजाओं की एस्टेट्स में तलाशी हुआ करती थी। इस तरह से भी हम पैसा इकट्ठा करें। भायद हम इस तरह से एक लाख या दो लाख इकट्ठा ही कर पायें लेकिन उस एक या दो लाख रुपये से ज्यादा देखने वाली बात यह है कि इससे कैसा पब्लिक ओपीनियन बनता है और इस चीज की

रिकवरी के लिये कितना स्टाफ लगाना पड़ता है और इससे इन्कम कुल कितनी होगी ?

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, मैंने यह कहा है कि आज भी करोड़ों रुपयों के उचन्ती सौदे हो रहे हैं, ये उनको चैक करें।

लाला बलवन्त राय तायल: जैन साहब, जरा ध्यान से सुनें। मैं सब बातों पर आऊंगा। जितनी तकरीरें मैंने अपोजी इन के साथियों की सुनी हैं। सुझाव बहुत कम लोगों ने दिए हैं डाक्टर मंगल सैन तो इस तरह से बोल रहे थे जिस तरह से किसी ड्रामे में पार्ट प्ले कर रहे हों। (व्यवधान व भाोर)

डा० मंगल सैन: हम मिलकर ही नौटंकी करते रहे हैं। आप तो उधर भाग गये हैं, लेकिन हम तो वहीं कायम हैं। (व्यवधान व भाोर)

लाला बलवन्त राय तायल: चेयरमैन साहब, मैं इस बजट के बारे में श्री मूल चन्द जैन की तकरीर का जिक्र कर रहा था। इन्होंने कुद तजवीजें दी। इन्होंने यह कहा कि फरीदाबाद के अन्दर जो बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उन्होंने अपने हैड आफिस दिल्ली वगैरा में खोले हुए हैं वे अपना माल वहां पर ले जाते हैं जिसकी वजह से हरियाणा को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम वह टैक्स वसूल कर लें तो हरियाणा के बजट का घाटा पूरा किया जा सकता है हो सकता है कि इनकी राय में यह ठीक

हो कि हम उन इंडस्ट्रीज को अपना हैड आफिस दिल्ली में खोलने की इजाजत न दें। इनको याद होगा कि एक बार इन्होंने ऐसा ही किया था जिस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दखल किया था और यह कहा था कि किसी भी स्टेट को इस तरह की पाबन्दी लगाने का अधिकार नहीं है। यही नहीं उसके तहत जो कानून बनाया गया था उसको वापिस भी लेना पड़ा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, इसी के साथ मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूँ कि इनके द्वारा बना हुआ सामाना जितना हरियाणा में बिकता है उसका टैक्स हमें मिलता है और इसके साथ ही साथ हरियाणा के लोगों को मजदूरी मिलती है। (व्यवधान) यह बात ठीक है कि उनका बिजनेस चलता है लेकिन यहां के लोगों को मजदूरी भी तो मिलती है। स्पीकर साहब, अबर हम उन पर इतना हैवी टैक्स लगाच दें जितने की उनकी फ़ैक्टरी भी न हो तो आप यह बात मानेंगे कि ये सोयेंगे और कौलकुलेट करेंगे कि हरियाणा में इतना टैक्स देना पड़ता है जितनी कीमत की फ़ैक्टरी नहीं है तो साथ वाली स्टेटस में जैसे यू0पी0 है, वहां गाजियाबाद में वे अपनी फ़ैक्टरीज ले जायेंगे। इसलिए उतना ही टैक्स लगाना वाजिब होगा जितना वे दे सकें। स्पीकर साहब, जितनी चीजें उन फ़ैक्टरीज द्वारा बनाई जाती हैं और उन चीजों की जितनी खपत हरियाणा में होती है उनका सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स हमें सारा मिलता है। स्पीकर साहब, इन्होंने बजट में छः परसेंट बचत की बात की है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम आगे भी इसी तरह से बचत करते रहेंगे। मैं सदन को यह भी बता दूँ कि जब ये

मिनिस्टर थे तो इन्होंने डिवैल्पमेंट के कामों पर कम खर्च किया। हम बचत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा डिवैल्पमेंट के कामों पर खर्च करेंगे।

इसके साथ ही साथ जैन साहब ने यह भी कहा कि जो बजट पे 1 किया गया है उसमें लीकेज बहुत ज्यादा है और अगर लीकेज को कम कर दें तो खर्चा पूरा हो जाएगा। मैं जैन साहब का भुक्रगुजार होऊंगा अगर लीकेज दूर करने के बारे में ये कोई ठोस सुझाव देंगे। स्पीकर साहब, आजकल एक और जहनियत पैदा हो गई है कि अगर बजट में कोई टैक्स न लगाया जाए तो कहा जाता है कि बजट में कोई जान नहीं है। स्पीकर साहब, आज जिस जगह पर जैन साहब बैठे हैं, मैं कह नहीं सकता कि वह जगह इसके लिए मौजू भी है या नहीं। ये ऐसी जगह पर बैठे हैं, जो जगह पुराने जमींदारों के लिए हैं। स्पीकर साहब, पता नहीं इनको याद भी है या नहीं, मैं याद करा देता हूँ कि 1938 में ये और मैं कांग्रेस में आए थे और उस समय आसोदा में जमींदारों ने इनकी पिटाई की थी। आज जिस हैसियत में ये वहां बैठे हैं उससे तो ऐसा गलता है जैसे कि ये भागे टोए हहों। इससे ज्यादा कुछ नहीं लगते। (व्यवधान) बी०के०डी० तो मैंने बनाई थी। चौधरी चरण सिंह उस वक्त बी०के०डी० में नहीं आए थे और जब वे आए थे तो मैं छोड़ गया था। स्पीकर साहब, जैन साहब ने खादी बोर्ड का जिक्र किया। ये कह रहे थे कि कुछ रुपया खादी बोर्ड का जो चेयरमैन था उसको काम करने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर

साहब, इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर चेयरमैन ईमानदारी से काम करना चाहे तो सरकार उसको रोकती नहीं है उसको ऐनकरेज करती है। अगर चेयरमैन यह सोचना भुय कर दें कि जो कर्जा दिया जाए उसमें कमी न ले लूंगा तो यह चीज कैसे सरकार बर्दा त कर सकती है।। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। चेयरमैन को जो सस्पेंड किया गया है और जो चार्ज फिट दी गई है उसमें भी यह चार्ज नहीं है। (व्यवधान)

लाला बलवन्त राय तायल: जैन साहब को भांति से सुनना चाहिए। स्पीकर साहब, जैन साहब कह रहे हैं कि यह चार्ज गलत है। अगर जैन साहब, खादी बोर्ड की फाइल देखें तो सब कुछ पता लग जाएगा। खादी बोर्ड का चेयरमैन होने के बाद इस चेयरमैन ने अपनी माली हालत कितनी बनाई है, वह सब पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको बाद में टाईम मिलेगा, अभी आप बैठिए।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, पे कमी न के ऊपर बोलते हुए इन्होंने वर्क चार्ज के ऐम्पलाइज, टैक्नोक्रेटस, डाक्टर्स तथा दूसरे एम्पलाइज के बारे में कहा। इस पे कमी न

के बारे में असैम्बली में भी सवाल उठाया गया और इस सम्बन्ध में आधे घंटे का समय डिककान के लिए दिया गया है। स्पीकर साहब, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सुझाव दिए गए हैं उन पर जरूर गौर किया जाएगा, उन पर सोचा जाएगा। अगर सर्विसिज में जैसे टैक्नाक्रैट्स, डाक्टरज और दूसरी कैटेगरीज में कोई बेचैनी होगी तो सरकार उसको दूर करेगी और पे कमीकान के बारे में जो कमेटी बनाई हुई है वह इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

स्पीकर साहब, यहां पर हरिजन चौपालों के बारे में कहा गया है। चौपालों की स्कीम 1978-79 में आरम्भ हुई थी। 1980-81 में इनके लिए हमने 25 लाख रुपया रखा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर हरिजन चौपाल के लिए कहीं से भी डिमान्ड आएगी तो सरकार उसको पूरा करेगी। कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कहीं से हरिजन चौपाल की डिमान्ड आए और उनकी मांग स्वीकार न हो। इसलिए हरिजन चौपाली के बारे में कोई बात नहीं है।

श्री मूल चन्द जेन: आप यह बताइए कि सह साल 96 लाख रुपया हरिजन चौपालों के लिए रखा है या पच्चीस लाख रुपया रखा है ?

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, अपनी एक स्पीच में इन्होंने कहा था कि 96 लाख रुपया रखा है और अब यह कह रहे हैं कि पच्चीस लाख रुपया रखा है।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, 25 लाख रुपया रखा है। स्पीकर साहब, मैंने यह भी कहा है कि हरिजन चौपाल के लिए जहां से भी डिमांड आएगी उसको अब यही पूरा किया जाएगा। कोई चौपाल बनने से रह जाए यह बात नहीं होगी।

स्पीकर साहब, जैन साहब ने ऐजुके ान के बारे में कहा कि कम खर्च किया है। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में कहा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं इनकी इंफमे ान के लिए बताना चाहता हूं कि इन्होंने कितना खर्च किया था और हम कितना खर्च करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, ऐजुके ान पर 1978-79 के अंदर 49.6 करोड़ रुपया खर्च किया। 1979-80 के अंदर 55.36 करोड़ रुपया खर्च किया और 1980-81 के अंदर 58.58 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। आप बताइए कि कौन सा खर्च कम किया है ? अब मैं मैडिकल के बारे में बताना चाहता हूं कि 1978-79 में 12.65 करोड़ रुपये खर्च हुए, 1979-80 में 14.48 करोड़ रुपया खर्च किया और 1980-81 में 16.16 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं लेकिन यह कहते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आप यह ऐग्नी करेंगे कि सड़कें कितनी जरूरी हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 1978-79 में 20.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 1979-80 में 21.

46 करोड़ रुपया खर्च किया गया और 1980-81 में 22.86 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं।

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं इरीगे टन के बारे में कुछ फिगरज देना चाहता हूँ जो कि इस वक्त इकौनमी के लिये बहुत जरूरी है। 1978-79 के अन्दर इस पर 97.24 करोड़ रुपया, 1979-80 के अन्दर 104.51 करोड़ रुपया और 1980-81 के अंदर इसके ऊपर इसके ऊपर 110.39 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आप ही अब देख लीजिये कि इस स्कीम पर जो ये कहते हैं कि कम खर्च किया है, क्या कम खर्च हुआ है ? स्पीकर साहब, इससे आगे मैं वैलफेयर आफ भाडयूल्ड कास्टस एंड बैकवर्ड क्लासिज डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ फिगरज देना चाहता हूँ। 1978-79 में 3.57 करोड़ रुपया, 1979-80 में 5 करोड़ और 1980-81 में 5.61 करोड़ रुपया इन जातियों की बहबूदी के लिये खर्च किया गया।

स्पीकर साहब, अब मैं कृषि के बारे में भी कुछ फिगरज यहां पर बताना चाहता हूँ। कृषि को बढ़ावा देने के लिये 1978-79 में 13.57 करोड़ 1979-80 में 20.22 करोड़ और 1980-81 में 20.41 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। मैंने अभी थोड़ी थोड़ी सी फिगरज यहां पर दी हैं और ये लोग अभी भी यह कहते हैं कि गांवों में सरकार ने बहुत कम खर्च किया है अधिकन न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा और मुझे इस बारे में एक भोर याद आ गया:

खुद कांटे बिछाये बैठे हैं राहों पर,

और उम्मीद करते हैं कि बहार आयेगी।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मुझे जवाब देने का मौका होना चाहिये

आप गैरों की बात करते हैं,

हमने अपने भी आजमाये हैं,

आप कांटों की बात करते हैं,

हमने तो फूलों से जख्म खाये हैं।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल: स्पीकर साहब, मैं भी एक भोर अर्ज कर देता हूँ—

अपना भोवा कि जलाते हैं अन्धेरे में चिराग,

उनकी साजि । है कि जमाने में सदा रात रहे।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि सरकार हर तरफ उन्नति के पथ पर सदा ही अग्रसर रही है। चौधरी राम लाल जी और जैन साहब ने भी अपनी स्पीच में बोलते हुए काफी बातें सरकार के बारे में कहीं। चौधरी राम लाल वधवा जी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी राम लाल जी जिस वक्त हम और आप सभी दिल्ली में इकट्ठे हुए थे,

आपने अपना इस्तीफा लिखकर जेब में डाल दिया था और यह कहा था कि मैं चण्डीगढ़ जाते ही यह गवर्नर साहब को दे दूंगा तथा इस हरियाणा सरकार को बदलवा देंगे। स्पीकर साहब, वह इस्तीफा पता नहीं करनाल आने पर कहां पर रह गया, यह सब कुछ ही भूल गये। (गोर एव व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, इन्होंने बोलते हुए मेरे बारे एक और बात कही कि मैं गांधीवादी हूं और प्रोहिबिशन की पालिसी की मदद करूंगा तथा सारे हरियाणा में भाराब बन्दी कर दूंगा। स्पीकर साहब, मेरा भी यही विचार था कि ये आर०एस०एस० वाले जिसके श्री राम लाल जी सेवक हैं, भी भायद राजनीति को छोड़ कर ऐसे सामाजिक काम करेंगे पर इन्होंने तो खुद दुकानें खोलने के लाइसेंस मांगे। इसी तरह हमारे माननीय देसराज जी ने भी बोलते हुए कहा कि चौधरी राम लाल जी ने सुरा के लिये लाइसेंस लिये लेकिन इन्होंने इससे भी इन्कार किया। स्पीकर साहब, सुरा, आयुर्वेदिक दवाई के नाम से एक भाराब बनाई जाती है जिसके अन्दर 44 परसेंट भाराब के अंश होते हैं जबकि असली भाराब में 50 परसेंट अंश होते हैं। हरियाणा में 20 प्रतिशत से ऊपर तक जिसमें भाराब हो, भाराब का अंश हो, वह दवाई बिक नहीं सकती। इसलिये ये लोग मंसूरी जैसी जगहों पर, जहां कि टोटल प्रोहिबिशन है, दवाईयों के तौर पर सुरा को बेचते हैं लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इन्कार किया

कि हमारा किसी कम्पनी में कोई भोयर नहीं है। फ़ैक्ट यह है कि इनके लड़के का उसके अन्दर भोयर है। (गोर एवं व्यवधान)

आवाजें: नाम बता दें स्पीकर साहब।

लाला बलवन्त राय तायल: नाम भी बता देता हूँ। अ गोक कुमार उसका नाम है, मृत्यु संजीवनी सुरा के नाम से लाईसैंस लिया हुआ है। (विघ्न) स्पीकर साहब, इसको एल-2 का लाईसैंस कहते हैं। स्पीकर साहब इन्होंने बोलते हुए कहा था कि इस बजट स्पीच में टैक्सों के लिये कोई तजवीजें नहीं दी गई हैं, यह तो लक्ष्यहीन बजट हैं। मैं नहीं समझता कि लक्ष्य वाला बजट कौन सा है और लक्ष्यहीन कौन सा है ? हरियाणा की जनता के लिये जो इस बजट में टैक्सों का कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है, उससे तो मैं समझता हूँ कि हरियाण की जनता ने सुख का सांस लिया है। आज यह इस बजट को लक्ष्य हीन कहते हैं ? अगर ये लोग कहीं बाहर जनता के सामने जाकर ऐसा कहें तो कोई इनकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं होगा।

स्पीकर साहब, इस बजट पर डिसकान के समय बोलते हुए चौधरी जगजीत सिंह पोहलू जी ने कुछ तजवीजें दी हैं और साथ में उन्होंने इसकी तारीफ भी की है। सरकार उनकी तजवीजों को ध्यान में रखे हुए हैं और जो बातें उन्होंने कहीं हैं। उनकी तरफ सरकार पूरा ध्यान रखेंगी और जो तजवीजें मानने योग्य होंगी उनको अवयव अमलीजामा पहनाया जाएगा।

स्पीकर साहब, हीरा नन्द आर्य जी ने बोलते हुए अपने विचार इस हाउस के सामने रखे जो कि स्कूलज के अपग्रेडे इन के सम्बन्ध में थे। उन्होंने कहा कि जहां जहां जरूरत समझी गई वहां पर स्कूलज अपग्रेड कर दिये गये। सरकार ने यह देखा है कि जिस तरह से उन्होंने स्कूलज को अपग्रेड किया है, उससे उन्होंने अपना पोलिटिकल अखाड़ा बनाने की कोशिश की है। अगर वे यह कोशिश करते कि जहां जहां कमी है वहां पर ही स्कूलज अपग्रेड किये जाएं तो बेहतर था पर उन्होंने तो अपने ही हल्के को प्राथमिकता दी। पब्लिक की जरूरतों को बिलकुल मद्देनजर नहीं रखा। फिर भी सरकार ने यह फैसला किया है और मुख्य मंत्री महोदय ने यह कह भी दिया है कि जहां जहां बिल्डिंगें बनी होंगी, वे लोग सभी तरह की जरूरतों को पूरा करते होंगे तो वहां पर अपग्रेडे इन में किसी प्रकार की डिले नहीं की जायेगी और ऐसे सभी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा इसके साथ साथ जो स्कूलज इन्होंने अपग्रेड किये थे, वे भी अगर सारी फारमैलिटीज फुलफिल करते होंगे तो उन स्कूलों को भी वैसे के वैसे रखने का वायदा किया गया है। इसलिये इस सरकार को निष्पक्षता का वातावरण बनाना होगा ताकि जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके और जनता यह महसूस न करे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है।

इससे आगे मैं स्पीकर साहब, कहना चाहता हूं कि हमारे एक आनरेबल मैम्बर श्री मांगेराम गुप्ता जी ने कहा है कि

रामलीला के वक्त पर उन लोगों से बिजली की खपत के लिये फ्री यूनिट कीमत ज्यादा ली जाती है। जबकि रैंड क्रॉस फेयर्ज में फ्री यूनिट कम ली जाती है इसके लिये हम ने यह किया है कि हम इनके रैट्स एक सा कर देंगे। इस सुझाव के लिये मैं उनका एहसान मन्द हूँ। उन्होंने और भी बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा।

18.00 बजे

स्पीकर साहब, जब डा0 मंगल सैन जी बोलने के लिए खड़े हुए तो मेरा ख्याल यह था कि ये सन् 57 से एम0एल0ए0 चलते आए हैं, बीच में एक दफा 1972 में हार गये थे। (गोर)

डा0 मंगल सैन: आप तो तीन बार हारे हो।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि यह दल बदलुओं की सरकार है और मैं सुनता रहा। मैं तो सोच रहा था कि ये पुराने मेंबर हैं और कोई तजवीज देंगे कि घाटे को कैसे पूरा किया जाए लेकिन इन्होंने कोई तजवीज नहीं दी। इससे तो यही लगता है कि इन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं होगा। इन्होंने जो दल बदल की बात कही मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब जनता पार्टी बनी तो जिन पार्टियों ने जनता पार्टी बनाई थी उन्होंने अपने आपको खत्म करके बनाई थी लेकिन ये वह लोग थे जिनहोंने अपने असली रूप को नहीं छोड़ा। इनका ब्यान गि कि दस साल

के बाद हम दे 1 के ऊपर राज करेंगे। तो स्पीकर साहब ये लोग ऐसे ख्वाब लेने लग गए थे। जब हिन्दुस्तान की डैमोक्रेटिक फोर्सिज ने इस बात को सोचा कि अगर दस साल के बाद इन लोगों ने * * * * * तो इन लोगों को आज ही क्यों न उखाड़ दिया जाए। (गोर)

डा० मंगल सैन: वे नै 1नल मानुमेंटस है और उनके बारे में हाउस में आज तक कभी कोई भाब्द नहीं आया लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी बात कर रहे हैं (गोर) It should not be allowed to be recorded. (Interruptions)

Mr. Speaker: I will examin it and if it is unparliamentary or unjustified, I will get it expunged.

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब यही बात तो मैं कहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान मानता है कि वह इन्सान एक मानुमेंट है लेकिन ये नहीं मानते। इनको तो महात्मा गांधी का पूरा नाम पता नहीं है। (गोर) स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं कि ये लोग दूसरों को तो कहते हैं कि लेकिन अपनी डबल मैंबरि 1प के मामले पर फैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं। स्पीकर साहब, इनका दिमाग उसी तरह का बना हुआ है जैसा आपको याद होगा कि दुनिया के अन्दर हिटलर नाम का एक आदमी पैदा हुआ था और वह कुछ फोर्सिज का सहारा लेकर जर्मनी के ऊपर हावी हो गया था। उसी तरह से ये आदमी जनता पार्टी के कुछ आदमियों को लेकर दे 1 पर कब्जा करना चाहते

थे। जिस दिन हिटलर ने जर्मन के ऊपर काबू पाया उसी रात को उसने अपने लाखों विरोधियों का कत्ल करवा दिया। उस भाख्स ने कहा कि जर्मनों ने यह क्यों नहीं कहा कि तुम सबसे महान आदमी हो और तुम दुनिया पर राज करो। तो जब उसके मुकाबले में डैमोक्रेटिक फोर्सिज इकट्ठी हुई। (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या ये बजट का जवाब दे रहे हैं और जर्मनी पर बोल रहे हैं ? (गोर)

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, दुनिया की डैमोक्रेटिक फोर्सिज ने उस नाजी डिक्टेटरिप का मुकाबला किया जिसने 40 लाख आदमियों को मरवाया (गोर)

Mr. Speaker: On a point of order, Sir. How is he relevant ? स्पीकर साहब, इन्हें डिबेट के संबंध में रैलेवेंट बोलना चाहिए। यहां हाउस में ऐसी कोई बात नहीं आई कि हमने इनको कहा हो। कि ये हिटलर के प्रतीक हैं। अगर तो किसी ने ऐसी बात कही हो तब तो जवाब दें लेकिन हमने तो ऐसा जिक्र ही नहीं किया। हमने तो कहा था कि आपने दल क्यों बदला, जनता से वि वासघात क्यों किया ? (गोर)

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): It is not a point of order. (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: Who is he to check me ? Mr. Speaker, Sir it is for you to judge. He shouldc not be allowed to assume the powers of the Chair.

Mr. Speaker: Hon. Members, I would request you not to interrupt the speech too much. I have always requested the hon. Members not to stray away from the subject in hand. Even previously, I am sorry to say that most of the members strayed away from the subject in hand. There was a lot of talk about defection which had no relevance to the Budget. I can only request the hon. Members to stick to the subject in hand and not to stray away from it.

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैं बजट स्पीच में ये बातें नहीं लाना चाहता था लेकिन जितने भी आर०एस०एस० वाले बोले इन्होंने बोलते हुए सिवाए दल बदल की बात के और कोई बात नहीं की। स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि दुनिया के 40 लाख आदमियों को हिटलर द्वारा मरवाया गया और डेमोक्रेटिक फोर्सिज ने जब उसका मुकाबला किया तो जर्मनी के दो टुकड़े हुए। (गोर)

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इस बात का इससे क्या संबंध है ? (गोर)

Mr. Speaker: I have already given my ruling that the hon. Members should stick to the subject in hand, but I am sorry to say that almost every member referred to defection which had nothing to do with the Budget. So, I can only say that my ruling will equally apply to both the sides. If the members from this side (Opposition) did not desist from making references to the defection, how can I now check the Finance Minister from giving the reply to that point. (Interruptions)

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा। स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन ने एक दो बातें और कहीं। वैसे तो इनका रोल जो था वह मैंने भुरू में कहा कि जैसे कोई ड्रामों के अन्दर पार्ट प्ले करता है उसी तरह का था एक बात इन्होंने मोरनी हिल्ज के बारे में कहीं (तोर)

डा0 मंगल सैन: * * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए।

लाला बलवन्त राय तायल: * * * * *

डा0 मंगल सैन: * * * * *

श्री अध्यक्ष: ये बातें रिकार्ड न की जाएं। I would request the Hon. Minister not to pass uncomplimentary remarks about senior legislators in the Opposition.

* * * * *

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, डा0 साहब ने बजट पर चर्चा करते हुए मोरनी हिल के बारे में कुछ बातें कही थीं। उन बातों का जवाब मिनिस्टर कंसन्ड ने भी इनको दिया और हमारे आनरेबल मैम्बर श्री लछमन सिंह जी ने भी दिया। स्पीकर साहब, जितनी बातें मोरनी हिल के बारे में इन्होंने बनाई हुई हैं उतनी बातें नहीं हैं बल्कि जो गवर्नमेंट ने ठेके दिए थे उसी के मुताबिक दरख्तों की कटाई हुई है। स्पीकर साहब, इसके बाद हमारे आनरेबल मैम्बर चौधरी गया लाल जी ने रिजर्वे उन के बारे

में और मेवाल डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाने के बारे में गवर्नमेंट को भाबा गी दी और कहा कि ये दोनों काम निहायत ही जरूरी थे। स्पीकर साहब, मैं पिछले दिनों मेवात एरिया देखने के लिए गया था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी मेवात एरिया नहीं देखा था। जब मैंने यह देखा कि हरियाणा प्रान्त में ऐसा इलाका अब भी मौजूद है जब कि हरियाणा प्रान्त हिन्दुस्तान भर में विकास के कार्यों में तीसरे नम्बर पर है, मुझे यह कहना पड़ा कि इस इलाके की डिवैल्पमेंट की बहुत जरूरत है। सरकार ने मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बना कर इस इलाके के साथ बहुत भलाई का काम किया है। स्पीकर साहब, हमारे आनरेबल मैम्बर चौधरी सतवीर सिंह मलिक जो कि पिछली जनता पार्टी की सरकार में फाईनैस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बजट पर चर्चा करते हुए कुछ बातें कहीं। उन्होंने यह का कि इस सरकार के ताकत में आने के बाद जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और यह भी कहा कि जब उस समय की जनता पार्टी के भासन में हरियाणा में ओलावृष्टि हुई थी तो उस सरकार ने किसानों की बहुत ज्यादा इमदाद की थी। स्पीकर साहब, इस सरकार के सत्ता में आने के बाद तो हरियाणा प्रान्त में ओलावृष्टि हुई ही नहीं है। ओला वृष्टि तो उसी सरकार के समय में होती थी ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इनकी सरकार के समय में ओलावृष्टि तो नहीं हुई लेकिन कहर तो पड़ा हुआ है।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैं आपके सामने एक गांव में ओला वृष्टि में हुए नुकसान के बारे में दी गई सहायता के आंकड़े रखता हूं। चौटाला गांव के अन्दर 19 हजार 52 एकड़ जमीन है। 19 हजार 52 एकड़ जमीन में से यह माना गया है कि 2/3 जमीन की का त होती है। इस 2/3 जमीन के अन्दर 3345 एकड़ जमीन में गेहूं की का त थी और 9682 एकड़ जमीन में चने की का त थी। इस तरह से कुल 13027 एकड़ जमीन में का त थी और जब वहां से आंकड़े लिए गये तो 2422 एकड़ जमीन की बजाये 923 एकड़ जमीन में नुकसान हुआ था। उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने उस नुकसान के लिए चौटाला गांव में 24 लाख 40 हजार 140 रुपए दिए। स्पीकर साहब, वह सारा रुपया उन गरीब किसानों को नहीं मिला बल्कि वहां के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको वह सारा रुपया मिला। स्पीकर साहब, उसी साल उस गांव में जो मंडी के लिए जगह बनाई हुई थी उसमें 8 हजार टन गेहूं की सरकार ने खरीद की थी। ये तो मैंने एक ही गांव के आंकड़े बताये हैं जो कि उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने गरीब किसानों के नाम खैरात दी थी। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को तो 6-6 और 7-7 करोड़ रुपए दे दिए लेकिन ये किसानों के डैमेज को खैरात कहते हैं किसानों के खून पसीने की कमाई को खैरात कहते हैं। (गोर एवं विघ्न)

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सबसिडी दी जाती है वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हरियाणा सरकार का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर साहब, सरकार के पास लैण्ड रेवेन्यू का 4 करोड़ 35 लाख रुपया आता है और एक करोड़ 97 लाख रुपए इस रेवेन्यू के कलैक्ट करने पर खर्च हो जाते हैं और इसमें ऐक्साइज एण्ड टैक्से इन का 45.28 परसेंट रुपया लैण्ड रेवेन्यू का और खर्च होता है। स्पीकर साहब, 1979-80 का लैण्ड रेवेन्यू 138.06 करोड़ रुपए बनता है जबकि कलैक्ट इन हुई है। 2.31 करोड़ रुपए यानी 1.6 परसेंट। स्पीकर साहब, ये तो मैंने लैण्ड रेवेन्यू की मोटी मोटी फिर्ज बताई हैं। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं थोड़ी बातें इरीगे इन सिस्टम के ऊपर बताना चाहता हूँ। इस सिस्टम से जो हमारी आमदनी है वह 11.57 करोड़ रुपए की ळे और इस पर जो खर्चा होता है वह 16.80 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से हमें हर साल लगभ 5-6 करोड़ रुपए का घाटा रहता है और पिछले 3-4 साल से लगभ हर साल इतना ही घाटा रहा है। स्पीकर साहब, मैं हाउस का थोड़ा समय और लूंगा। मेरे साथियों ने कुछ और भी इल्जाम लगाए हैं। हमारे आनरेबल मैम्बर श्री कंवल सिंह जी ने जो कि कैप्टन रणजीत सिंह जी के लड़के हैं और जिनकी कांस्टिचुएँसी मेरी कांस्टिचुएँसी के साथ ही लगती हैं, कुछ ऐसी बातें कहीं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐक्साइज एण्ड टैक्से इन से सरकार को बहुत आमदनी होती है लेकिन इस साल की रिकवरी कम है। स्पीकर साहब, पिछले साल

ऐकसाइज एण्ड टैक्स से इन से सरकार को 132 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी लेकिन इस साल फरवरी तक 135 करोड़ हो चुकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आमदनी सेल्ज टैक्स से 69.5 परसेंट होगी, यह पहले से बढ़ेगी। स्पीकर साहब, इनको यह ख्याल था कि रेवेन्यु की रिसीट चूंकि कम आई हैं। इसलिए कहीं खाते न बदल लिए हों स्पीकर साहब, खाते ऐसे नहीं बदले जाते। चंदा इकट्ठा करने के लिए इनके पास दो ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जिस तरह इन्होंने किसानों से चन्दा इकट्ठा किया था और दूसरा तरीका डा0 मंगल सैन के पास हैं, उनसे पूछ लेते। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मेरी कांस्टिट्यूएँसी में एक स्कूल था जिसके बारे में कई मैम्बरों ने कहा कि खाली करवा लिया गया। इस स्कूल के खिलाफ 1976 में डिक्री हुई थी, हमने इस डिक्री को ऐग्जिक्यूट करवाया है। इन्होंने कहा था कि हमने भावित में आने के बाद स्कूल को खाली करवाया ऐसी बात नहीं है, हमने तो डिक्री को जो 1976 में हुई थी, ऐग्जिक्यूट करवाया है। इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री की कांस्टिट्यूएँसी में कत्ल हुआ और इस कत्ल को इनके नाम लगा दिया, कभी कह दिया कि सरपंच को पिटवा दिया। अगर मैं यह कहूं कि इन की कांस्टिट्यूएँसी में कत्ल हुआ है और उस कत्ल को इनके जिम्मे लगा दूं तो कोई अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री की कांस्टिट्यूएँसी में अगर कत्ल हुआ है इसका मतलब यह तो नहीं है कि उन्होंने किया है या किसी को पिटवाया है। (व्यवधान) स्पीकर साहब, थोड़ी सी बातें हाउस को और बताचना चाहूंगा। श्री इन्द्रजीत सिंह

हाउस के यंग मैम्बर हैं, इन्होंने अपनी तकरीर में बड़ी अच्छी तजवीज दी। इन्होंने कहा कि जुडीयरी और ऐग्जैक्टिव के पेस्केल्ज में डिफ्रेंस नहीं होना चाहिए। बजट पर डिसकशन करते समय अगर ऐसी बातें बताई जाएं तो जो कमी रह जाती है वह दूर हो सकती है। श्रीमती सुशमा स्वराज ने भी कुछ बातें कहीं। मैं सोच रहा था कि सुशमा जी तैयार हो कर आयेंगी और हाउस में कुछ तजवीजें रखेंगी। (व्यवधान) सुशमा जी ने कोई सुझाव नहीं दिया। यहीं कहा कि हमें खर्च को कम करना चाहिए, टैक्स इवेजन को रोकना चाहिए और फ़ैक्ट्री के आफिसिज हरियाणा की टैरिटरी के बाहर न जाने दीजिए, इस तरह थोड़ी सी बातें कहीं लेकिन ठोस सुझाव कोई नहीं दिया। स्पीकर साहब, मैं सदन के नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि सेल्ज टैक्स में कमी हुई है। वह कभी इसलिए हुई है कि प्रान्त में कहर पड़ गया और किसानों के 165 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। मंडिया में अनाज आने से, चावल आने से 5-6 करोड़ रुपये के बीच सेल्ज टैक्स आना था, वह नहीं आ सका क्योंकि फसल नहीं हुई। श्री सुरेन्द्र सिंह जी, मेरे अजीज हैं। इन्होंने कहा कि नहरों में पानी नहीं है और पानी की कमी को दूर करने के लिए एस0वाई0एल0 और हथनी कुंड की नहरों का निर्माण हरियाण सरकार को करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पंजाब से जो पानी पाकिस्तान को जाता है, अगर वह हरियाणा को न मिला और पंजाब सरकार का यही रवैया रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी पड़ेगी और हरियाणा को पानी देना पड़ेगा।

सैंटर हमें मदद देगा क्योंकि आज सैंटर मजबूत हैं स्पीकर साहब, हथनी कुंड के मसले का पहले ही फैसला हो जाता अगर यू0पी0 वाले हमसे पहले बात करते चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला ने जो सुझाव रखे, मैं उनका बड़ा अहसानमन्द हूँ। जो सुझाव उन्होंने रखे हैं, उन पर सोचने वाली बात है। स्पीकर साहब, मेरे साथियों ने बजट पर बहस करते समय जो जो तजवीजें दी हैं। जो कटाघ्न किये हैं। मैंने उस सब बातों के बारे में हाउस में कहा। अब मैं आ ा करता हूँ कि तमाम साथी इस बजट को खूबसूरती के साथ पास करेंगे और हरियाणा के लोगों को अच्छा नक ा देंगे, ताकि बगैर टैक्स के बजट से स्टेट का काम चल सके।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(1) चौधरी राम लाल वधवा द्वारा

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जिनके बारे में मैंने पहले कहा कि वे गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, गांधीवादी होते हुए भी बड़ी गलत बात कही है। अगर सच बात होती तो मुझे गिला न होता। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भाक नहीं कि करनाल में एक आयुर्वेदिक फ़ैक्टरी खोलने के लिए दो डाक्टरों ने लाइसेंस मांगा जिसमें मेरा लड़का भोयर होल्डर था। डाक्टर ने बात की कि हम

दोनों फ़ैक्टरी लगायेंगे और लाइसेंस लेने के लिए एप्लाइ किया। उन्होंने नौ दस आइटम्ज बनानी थी जैसे च्यवन प्रा । है। (व्यवधान) आप मेरी बात को सुन तो लो। अध्यक्ष महोदय, इन आइटम्ज में एक आइटम थी 'मृत संजीवनी सुरा'। 'मृत संजीवनी सुरा' आयुर्वेदिक दवाई है लेकिन प्रोहिबिटिड ऐरिया में जब यह जाती है तो लोग भाराब के बदले में इसे इस्तेमाल करते हैं उन्होंने इस फ़ैक्टरी के लिए जगह ली थी, फ़ैक्टरी लगाने के लिए सामान भी आ गया था लेकिन वह फ़ैक्टरी नहीं लगाई गई। (व्यवधान) हमारे ऐक्सार्ज एंड टैक्से इन मिनिस्टर को जहां इस बात का पता है कि मेरा लड़का फ़ैक्टरी में हिस्सेदार है, वहां वे यह भी पता कर लेते कि वह फ़ैक्टरी बनकर तैयार भी हुई है या नहीं क्या चालु हुई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: अब काफी हो गया। आपने बता दिया कि आपने वह फ़ैक्टरी नहीं चलते दी।

चौधरी राम ताल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी बात तो कहने दें।

Mr. Speaker: I am sorry. I cannot give you more time. आपने ऐक्सप्लेन कर दिया कि आपने फ़ैक्टरी नहीं लगाई।

चौधरी राम ताल वधवा: इसके बाद कुछ लोग लाइसेंस लेने के लिए इनके पास गए। उनसे इन्होंने कहा कि इस तरह की फ़ैक्टरी पर पाबन्दी लगा दी जाए। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग

इनके पास फिर पहुंचे और उनके ऊपर पाबन्दी नहीं लगाई। क्या ये मुझे बताएंगे कि उनके ऊपर इन्होंने पाबन्दी लगाई ? (गोर) मैं मांग करता हूँ कि इस पर तुरन्त पाबन्दी लगाई जाये। महोदय ये जेल में मेरे साथी रहे हैं और इनको देखकर यही लगता है :-

दोस्तों की जान पर सदमे उठाए

दु मनों की बेवफाई का ठिकाना

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए समय दिया जाए।

Mr. Speaker: When you were called upon earlier, you were not ready. You cannot make a joke of it like this. (Interruptions) I called upon you 3-4 times but, I am sorry to say, you were fumbling about at that time and were not prepared for it. Now you are intervening in the half an hour discussion and asking for time for making personal explanation for which there is not occasion now. Do not tax my patience to break it. मैंने आपे कहा था कि डिबेट के आखिर में आपको समय मिलेगा and I gave you the chance but you were not ready for it.

Chaudhri Ram Lal Ji, you please wind up now.

चौधरी राम ताल वधवा: ठीक है जी, मैं पांच मिनट में ही सारी बातें मुकम्मल करके खत्म कर देता हूँ। केवल दो तीन कैटेगरीज के विषय में ही अर्ज करके एच0सी0एस0 के बराबर होते

थे जैसे ऐक्सीयन और एच०सी०एस० के ग्रेडज बराबर के होते थे। अब उन ग्रेडज में काफी अन्तर है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बराबर किया जाये। अगर मैं इन सारे ग्रेडज को पढ़ने लूँ तो बहुत समय लगेगा, काफी लम्बा चार्ट है। लेकिन सरकार ने जो पे स्केल दिये हैं उनके बारे में अब य अर्ज करना चाहता हूँ। आजकल ये जो टोटल पे ले रहे हैं। उससे कम तन्खाह नये स्केल में बनेगी। जब पुराने स्केल के अन्दर अधिक तनखाह बैठती है तो ये नये स्केल लेने का क्या लाभ हुआ ? इसी तरीक से लैक्चरार का पे स्केल 700-1400 का था। अब नया पे स्केल 630 से भुरु होता है। ऐसी ही हालत एस०डी०ओ०, ऐक्सियन, अकाउन्टैन्ट, जूनीयर आडिटर, सीनियर आडिटर आदि की है। सब के पे स्केल कम हैं।

स्पीकर साहब, अब मैं जेल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के विशय में भी अर्ज करना चाहता हूँ। जेल और पुलिस के कर्मचारियों क एक ही कैटेगरी होती है और दोनों के फंक्शनज भी एक ही होते हैं। इसलिए उनके पे स्केल भी बराबर के होने चाहिए। डिप्टी सुप्रिन्टैन्डैन्ट जेल पुलिस के बराबर और असिस्टेंट सुप्रिन्टैन्डैन्ट जेल पुलिस के सब इन्स्पैक्टर के बराबर होता है। पुलिस से भी कई कार लोगों को जेल डिपार्टमेंट में लेते हैं लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंटस के ग्रेडज में काफी अंतर है। इसी प्रकार के सैक्रेटेरिएट के सुप्रिन्टैन्डैन्टस में और दूसरे विभागों के सुप्रिन्टैन्डैन्टस में अन्तर रखा गया है। इसी तरह से यदि कोई

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्स्पैक्टर होता है और उसकी प्रोमोशन असिस्टेंट मैनेजर की हो जाये तो आज वह तनखाह ले रहा है नय स्केल में उसे उससे कम मिलेगी। इसके अलावा पहले ग्रेडज में जो अन्तर था वह अन्तर नए ग्रेडज में नहीं रखा गया। टैक्नोक्रेटस को सरकार की तरफ से यह आवासन दिया जा चुका है कि उनकी कान्फीडेन्स जल रिपोर्ट डीसी नहीं लिखेगा लेकिन वह अब भी लिखता है यह गलत बात है। डाक्टर और इंजीनियर तो प्रान्त की प्रगति की रोड़ की हड्डी होते हैं। असल मायनों में डिप्लोमैट को इंजीनियर और डाक्टर ही करते हैं। इसलिए उनको एच0सी0एस0 के बराबर समझा जाना चाहिए और बराबर के ही पे स्केल दिये जाने चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। लेकिन बैठने से पूर्व सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके साथ फर्क हो रहा है उस फर्क को दूर करके इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रान्त संख्या 1417 पर कुछ लोगों की मांग पर आधा घन्टा की डिस्कशन को स्वीकार किया है। प्रान्त काल में इस प्रान्त के उत्तर में बताया गया था कि पे कमीशन की रिपोर्ट वर्कचाज्ड कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी लेकिन स्पीकर साहब टर्म्ज आफ रैफरेन्स में यह लिखा हुआ है कि आल कैटेगरीज आत इम्पलाइज चाहे वह टैम्परेरी हो, चाहे ऐडहाक हो या वर्क चाज्ड हो या

रैगुलर हो उन सब कर्मचारियों पर वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी।

स्पीकर साहब, मैं ज्यादा तफसील में न जाकर कुछ भाब्द रिपोर्ट बारे में भी अर्ज करना चाहती हूँ। मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि इस आयोग की सिफारिशों पर वर्कचाजर्ड पर लागू नहीं होगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन गरीब वर्कचाजर्ड से क्या इनको कोई हमदर्दी नहीं है ? हमारे हरियाण में 35 हजार व्यक्ति वर्कचाजर्ड हैं। 20-20 साल से और दस दस साल से वे सर्विस कर रहे हैं लेकिन वे सरकार का अंग नहीं हैं। आपको यह सुनकर दुःख होगा कि ऐसा कर्मचारी बीस साल से काम कर रहा है लेकिन उसको कोई भी सर्विस बेंनेफिट नहीं दिया जाता है जैसे मैडिकल, ग्रेचुटी, पेंशन, जीपीएफ, इन्सुरेन्स आदि। आप इस बात से और ज्यादा हैरान होंगे कि उसके मरने के पश्चात उसकी फैमिली को कोई फैमिली पेंशन भी नहीं दी जाती है। स्पीकर साहब, यदि हमारे घर में कोई पांच साल नौकर काम करता है और पांच साल के पश्चात जब वह नौकरी छोड़ कर जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ हमें भी मोह हो जाता है परन्तु जो व्यक्ति सरकार की 25 वर्ष तक नौकरी करता है, उसको कोई सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं। उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। इन्होंने कहा है कि वर्कचाजर्ड ऐम्पलाइज वेतन आयोग की टर्म्ज आफ रेफरेंस में नहीं आते हैं। लेकिन मेरी

प्रार्थना यह है कि उनको रैगुलर कर दिया जाये और उन पर भी पे कमी ान की रिपोर्ट लागू की जाये। जिस प्रकार हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने ऐडहाक कर्मचारियों को दो वर्ष के प चात रैगुलर कर दिया उसी प्रकार से इनको क्यों नहीं किया जा सकता ? यदि दो साल के कर्मचारियों को रैगुलर किया जा सकता है तो बीस बीस साल वालों को क्यों नहीं किया जा सकता ? उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। क्या सरकार उन गरीब लोगों पर अनायत नहीं कर सकती ?

स्पीकर साहब, समय का अभाव है इसलिए एक दो और कैटेगरीज के बारे में अर्ज करना चाहूंगी क्योंकि डिटेल में तो चौधरी राम लाल वधवा ने जिक्र कर दिया है। हमारे यहां स्कूल इन्सपैक्टर की पोस्ट होती हैं वे करीब साठ या सत्तर ही होंगे। उन्हें इस वक्त डिमान्सट्रेटर का ग्रेड तो 225-400 का स्केल दिया हुआ था। वेतन उन्हें इस वक्त डिमान्सट्रेटर का ग्रेड तो 500-800 कर दिया परन्तु इन्सपैक्टर स्कूल का ग्रेड 225-400 ही रहने दिया जब कि डिमान्सट्रेटर का भी इतना ही ग्रेड था। इसलिए दोनों को बराबर स्केल दिया जाये। सरकार के खजाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिमान्सट्रेटर की क्वालिफिके ान बी0एस0सी0 होती है और स्कूल इन्सपैक्टर की बी0ए0 होती है लेकिन उसके साथ डिप्लोमा भी होता है। इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करती हुई मैं अपना स्थान लेती हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, आपने पे कमी इन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कुछ अलग से समय निर्धारित किया है। समय की तो कमी है परन्तु एक दो बातें आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। एक दिन क्वै चन आवर में पूछा गया था कि वर्कचाजर्ड इम्पलाइज किस किस विभाग में हैं तो उत्तर दिया गया था कि पब्लिक हैल्थ, इरीगे इन तथा पी0डब्ल्यू0डी0 में हैं। स्पीकर साहब, आपको जानकारी खु ि होगी और हाउस को भी जान कर खु ि होगी कि इन वर्कचाजर्ड के लिए तीनों विभागों के चीफ इंजीनियर्ज की एक कमेटी बनायी गई थी, उस कमेटी ने उनकी कुछ डिमान्ड मंजूर की थीं, उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरीज ने इस बात को रिकमेंड कर दिया था कि उनकी मांग मान ली जाये। स्पीकर साहब जहां तक मुझे याद है उस समय पांच साल तक के वर्कचाजर्ड मान ली गई थी। इसलिए मैं सरकार से हय चाहूंगा कि वह इस बात का यहां हाउस में एलान करें कि जो 35 हजार वर्कचाजर्ड की डिमान्ड ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरीज तक ने मान ली थी उसे माना जाता है क्योंकि उन्होंने बड़े सोच विचार करने के प चात ही उस डिमांड को माना था। (विघ्न) सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सिफारि ात ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरीज ने की हैं उनको माना जाये और वर्क चाजर्ड ऐम्पलाइज को जल्दी से जल्दी रैगुलर किया जाये ताकि वे भी पे कमी इन की रिपोर्ट का फायदा उठा सकें।

स्पीकर साहब, पे कमी इन की रिपोर्ट में जो ऐनामलीज रह गई हैं, उनकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी सरकार ने पुलिस के अन्दर जो डी०एस०पी० के पद हैं उनके पे स्केल एच०सी०एस० के पे स्केलों के बराबर करने की अनाउसमेंट की थी। वह पालिसी सरकार की ऐ योरेंस है यह उनकी बड़ी रीजनेबल डिमान्ड है। उस समय सारे हाउस के सदस्यों ने बड़ी तालियां बजा बजा कर इस बात को माना था। एक दूसरी बात की ओर भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। पे कमी इन की रिपोर्ट के पेज 10 पर कुछ कैटेगरीज हैं। जिनकी क्वालिफिके इन मैट्रिक होती है उनका ग्रेड 160-425 था लेकिन अब उनका ग्रेड 525-1050 कर दिया गया है। इनमें हैड क्लर्क, एसिसटेन्ट, सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर आदि भामिल हैं। लेकिन जिन लोगों की क्वालिफिके इन मिनिमम बी०ए०, बी०एड०, बी०एस०सी० आदि है और जिनमें जुनियर आडिटर, एकाउन्टेन्ट आदि आते हैं उनका स्केल 160-425 था लेकिन इनका ग्रेड अब 480-760 का कर दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि इस ऐनोमली को दूर किया जाये। एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने जो पे कमी इन की रिपोर्ट 1-4-79 से लागू की है इसको 1-4-79 से लागू करने की बजाये 1-4-78 से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब ने अपनी पे कमी इन की रिपोर्ट 1-4-78 से लागू की है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि

पंजाब में और हरियाणा में जो मकान यू0टी0 द्वारा दिये जाते हैं उन मकानों की अलाटमेंट में पंजाब वाले कर्मचारी सीनियर हो जायेंगे और हरियाणा वाले कर्मचारी जूनियर रह जायेंगे। इस प्रकार पंजाब के कर्मचारियों को हरियाणा के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक मकान मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को 1-4-78 से लागू किया जाये। आप बे तक इस अवधि के दौरान का पैसा कर्मचारियों को नकद न देकर उनके जी0पी0एफ0 या कम्पसलरी डिपोजिट स्कीम में जमा कर दें। यदि पीछे से यह रिपोर्ट लागू हो जाये तो उन्हें भी मकान अधिक मात्रा में मिल सकेंगे और इस प्रकार से सीनियरिटी और जूनियरिटी खत्म हो जायेगी। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पे कमी इन की रिपोर्ट पर बोलते हुए कुछ साथियों ने कई सुझाव दिए हैं। पे कमी इन के बनाये जाने के बारे में खासकर चौधरी रामलाल वधवा ने कहा कि यह कमी इन किस वक्त बना था ? पे कमी इन चौधरी देवी लाल जी के टाईम पर बना था और उस समय चौधरी राम लाल वधवा और डा0 मंगल सैन उनके सलाहकार हुआ करते थे। पे कमी इन सरकार द्वारा 23-1-79 को बनाया गया था। उस समय चौधरी रामलाल वधवा साहब और डा0 मंगल सैन मन्त्री मण्डल में भी भागिल थे। मैंने उस समय यह कहा था कि कमी इन कभी भी दो आदमियों का

नहीं हुआ करता है। कमी इन या तो एक आदमी का हुआ करता है या तीन आदमियों का या पांच आदमियों का हुआ करता है। दो आदमियों का कमी इन कभी नहीं हुआ करता है क्योंकि अगर 3 आदमियों का कमी इन होगा तो उन तीन आदमियों में से कम से कम दो आदमियों की तो एक रिपोर्ट हो सकती है। यदि दो आदमियों का ही कमी इन होगा तो उनकी रिपोर्ट भी अलग अलग होगी।

अध्यक्ष महोदय, बाबू मूल चन्द जैन जी जो बड़ी जिम्मेदारी से बातें किया करते हैं, लेकिन मैं उनको यह बात बताना चाहता हूँ। कि मैंने उस समय प्वायंट आऊट किया था कि या तो एक आदमी का कमी इन बनाया जाता है या 3 आदमियों का या पांच आदमियों का कमी इन हुआ करता है। लेकिन चौधरी देवी लाल जी के सलाहकारों ने दो आदमियों का कमी इन बनवा दिया।

चौधरी राम लाल वधवा: आप के सलाहकार कौन कौन हैं ?

चौधरी भजन लाल: वधवा साहब, हमने चौधरी देवी लाल जी की तरह कोई ऐडवाइजन नहीं रख रखें हमारे तो 52 साथी सलाहकार हैं जिन्होंने कल सरकार का साथ दिया है।
(तोर)

श्री मूल चन्द जैन: * * * * *

श्री अध्यक्ष: पे कमी ान की रिपोर्ट के अलावा जो बातें
हो रही हैं वे रिकार्ड न की जायें।

चौधरी राम लाल वधवा: * * * * *

* * * * * (गोंर एवं विघ्न) * * *

चौधरी भजन लाल: * * * * *

* * * * * * * * * *

श्री मूल चन्द जैन: * * * * *

* * * * * * * * * *

चौधरी भजन लाल: * * * * *

* * * * * * * * * *

चौधरी राम लाल वधवा: * * * * *

* * * * * * * * * *

श्री मूल चन्द जैन: * * * * *

* * * * * * * * * *

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में तो
नहीं पड़ना चाहता था। समय का काफी अभाव है। इसलिए पे
कमी ान का जहां तक ताल्लुक है हमें दिसम्बर 1979 में रिपोर्ट

मिली। हमने रिपोर्ट मिलते ही फैसला कर लिया कि 1-4-79 से पे कमी इन की रिपोर्ट लागू की जाये। हमने इतनी जल्दी इस पे कमी इन की रिपोर्ट को लागू किया है जबकि पंजाब के अन्दर 1977 में कमीशन बनाया गया था और 1978 में उसी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक पंजाब ने वह लागू नहीं की है। हमारे पास जैसे ही पे कमी इन की रिपोर्ट आई हम लागू करते गए। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की रिपोर्ट लागू होनी बाकी हैं अथवा जिनके साथ ठीक प्रकार से न्याय नहीं हुआ होगा उन सभी की रिपोर्ट हम 3 महीने के अन्दर अन्दर प्रदे 1 भर में लागू कर देंगे।

जहां तक वर्कचाजर्ड स्टाफ का सवाल है, उनके साथ कई माननीय सदस्यों ने बहुत हमदर्दी जाहिर की है लेकिन जितनी हमदर्द गरीब आदमियों की यह सरकार है उतना पिछली सरकार नहीं थी। उस सरकार ने तो गरीबों के बारे में ख्याल तक भी नहीं किया था। बहन सुशमा जी ने वर्क चाजर्ड के बारे में काफी जिक्र किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार में वे भी मंत्री थी और डा0 मंगल सैन जी भी मंत्री थे उस समय इन्होंने वर्क चाजर्ड के बारे में विचारा तक नहीं।

श्री मूल चन्द जैन: हमारी सरकार ने पिछले साल 24 लाख रुपये दिए हैं। (गोर एवं विघ्न) * * * * *
 * * * * *
 * *

डा0 मंगल सैन: * * * * *
* * * * *

सदन की बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सैन्स हो तो 10 मिनट समय और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है।

आधे घण्टे की चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon. Chief Minister may please continue.

19.00 बजे

चौधरी भजन लाल: मैं तो पे कमी इन की ही बात कर रहा था लेकिन दल बदल की बात भुरु की। इसलिये मुझे कहना पड़ा है। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इनसे तंग आकर बाबू जगजीवन राम जी जैसे आदमी भी इनको छोड़कर यदि जा सकते हैं तो हमें तो इन्हें दोश नहीं देना चाहिए। क्या हम जनता पार्टी में रह सकते हैं जिसमें केवल

आर०एस०एस० के प्रभुत्व वाला जनसंघ ही हावी हो ? इसमें तो केवल एक ही घटक रह गया है जनसंघ, ये बेचारे समाजवादी तो फंसे हुए हैं। और सुशमा जी जैसे सोच रहे हैं कि कहां जायें ? एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि एक दफा बहिन सुशमा जी भी लोक दल में भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने इनको कहा था कि थोड़ा ठहरिये। इसलिये वे नहीं गईं। इसी तरे से बलदेव तायल जी के बारे में भी मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम कांग्रेस (आई) पार्टी में जा रहे थे तो बलदेव भाई मेरे पास आये (व्यवधान व भाोर)

एक आवाज: जो आदमी हाउस में मौजूद नहीं है, उसके बारे में इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए।

चौधरी भजन लाल: मैं यह हकीकत बता रहा हूं मैं यह बात आन ओथ कहता हूं

श्री मूल चन्द जैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मैंने जहां तक बलदेव तायल जी की स्पीच सुनी है, उन्होंने कभी कोई बात डिफैक्ट इन की बाबत नहीं की। यह बेकार में उनके बारे में डिफैक्ट इन की बात कर रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: आपको क्या इस बात का पता है कि उन्होंने क्या कहा था ?

श्री मूल चन्द जैन: सारी बातें रिकार्ड पर हैं। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: आप सुनिए तो सही। बलदेव तायल जी मुझे उस समय क्या कहते हैं जिस समय हम कांग्रेस (आई) में भाामिल हो रहे थे। वे यह कहते हैं कि भजन लाल जी, लाला बलवन्त राय तायल कहां हैं, वह तो आपके साथ होंगे ? मैंने कहां हां। तो वह कहने लगे कि फिर तो मेरे लिये कोई मिनिस्टरी नहीं मिल सकती। इसलिये मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। (व्यवधान व भाोर) यह हकीकत है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज! मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन्ट्रान न करें और मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे पे कमी इन के बारे में बतायें तो अच्छा रहेगा।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं तो उसी के बारे में बात कर रहा था लेकिन बीच में इन्हीं लोगों ने टोका-टोकी की। मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ा है। मैं तो कभी ऐसी कोई बात कहता ही नहीं हूँ। मैं कभी ऐसी भाशा इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह की ये इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, जहां तक पे कमी इन का ताल्लुक है, जिसके बारे में अभी यहां पर चर्चा हुई है, उसमें जहां तक वर्कवाज्ड ऐम्पलाईज का ताल्लुक है, जिन वर्कचाज्ड ऐम्पलाईज की सर्विस 31-12-78 को 5 वर्ष की हो गयी है, उन सबको रैगुलर कर दिया गया है।

यह रिपोर्ट उन पर भी दूसरी कैटेगरीज की तरह से ही लागू होगी। इतना बड़ा फैसला सरकार ने किया है। (व्यवधान) यह तो बात करते हैं यहां पर दल बदल की, इन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, कुछ महकमों का जिक्र किया गया। इसके अलावा कुछ दूसरे महकमों का भी जिक्र किया गया। हमने इसके लिये अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी हुई है। उस कमेटी में तीन हमारे कमि नर्ज भी शामिल हैं। वह कमेटी एक एक बात की गहराई में जायेगी और ठीक तरीके से सारी रिपोर्ट देखेगी। जिस भी महकमे के साथ पे कमी न ने कोई ठीक बात नहीं की है, किसी महकमे को इग्नोर किया है, उस महकमे को पूरी तरह से ध्यान में रख कर सब अधिकारियों को और कर्मचारियों का इंसोफ दिया जायेगा और हम इसे तीन महीने के अन्दर अन्दर सारे प्रदे 1 के अन्दर लागू कर देंगे। इसके अलावा ला एंड आर्डर के बारे में कुछ अपोली न के भाईयों ने जिक्र किया। तायल साहब उसका जवाब देना भूल गए।

श्री मूल चन्द जैन: वत तो रैलवैन्अ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उसके लिये कल आपको टाईम दूंगा।

चौधरी भजन लाल: आखिर में मैं फिर सदन को यह वि वास दिलाना चाहूंगा कि पे कमी न की रिपोर्ट को हम तीन महीने के अन्दर अन्दर लागू कर देंगे और किसी भी महकमे के

किसी भी कर्मचारी के साथ किसी तरह की ज्यादाती नहीं होने देंगे। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9 बजे तक के लिये ँडर्न किया जाता है।

***19.05 बजे**

(तत्प चात सदन मंगलवार दिनांक 18-3-1980 प्रातः 9 बजे तक के लिए * स्थगित हुआ)